सूर्योदय 5:50 सूर्यास्त 7:00

आज का तापमान

शिमला	16.6 न्यू	26.0 अधि
धर्मशाला	18.7 न्यू	29.0 अधि

बाजार

सेंसेक्स	77,538
निफ्टी	24,232

सोना 1,57,000 चांदी 2,38,000

भारतेन्दु शिखर

हिमाचल, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू व उत्तराखंड में प्रसारित

आरएनआई नं. HPHIN/2000/02437 | शिमला | शुक्रवार, 21 अगस्त 2026 | 5 भाद्रपद, विक्रमी संवत 2083 | वर्ष 28, अंक 116, कुल पृष्ठ 12 | मूल्य : 5 रुपए | info@bhartendushikhar.com | 8894677702

न्यूज शॉर्ट्स

तेलंगाना प्रिंसिपल मर्डर केस, 10वीं के 2 स्टूडेंट्स गिरफ्तार

एजेंसी, हैदराबाद। तेलंगाना के नलगोंडा में 48 साल की स्कूल प्रिंसिपल कल्लू रूपा रेड्डी की हत्या के मामले में 10वीं के दो छात्रों को गिरफ्तार किया गया है। रूपा रेड्डी कोंडामल्लेपल्ली के नागार्जुन पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल और डायरेक्टर थीं। 12 अगस्त की सुबह वह अपने घर में मृत मिली थीं। उनके शरीर पर चाकू से 27 वार किए गए थे। पुलिस की जांच में सबसे अहम सुराग उनकी आखिरी फोन कॉल में बोले गए 'बाबू' शब्द से मिला। रूपा अपने स्कूल के कुछ छात्रों को 'बाबू' कहकर बुलाती थीं। जांच आगे बढ़ी तो 10वीं के दो छात्रों पर शक गहराया और पूछताछ में दोनों ने हत्या की बात कबूल की। पुलिस के मुताबिक, कुछ समय पहले रूपा ने दोनों छात्रों को हॉस्टल बैग में पैसे और मोबाइल फोन मिलने पर डांटा था और उनके माता-पिता को इसकी जानकारी दी थी। पुलिस को शक है कि इसी बात से दोनों छात्र प्रिंसिपल से नाराज थे।

दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर चला बुलडोजर

एजेंसी, नई दिल्ली। दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर बने अवैध ढांचों को बुधवार देर रात बुलडोजर से हटा दिया गया। अधिकारियों के मुताबिक, ये ढांचे हाई कमीशन की तय सीमा से बाहर बने थे। पाकिस्तान हाई कमीशन का ऑफिस दिल्ली के चाणक्यपुरी के शांतिपथ पर है। यहां बैरिकेड, फेंसिंग और वीजा सेक्शन के पास कतार प्रबंधन के लिए बनाए गए ढांचे भी हटाए गए। यह कार्रवाई ऐसे समय हुई है, जब दो दिन पहले इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के बाहर लगाए गए सुरक्षा बैरिकेड और पार्किंग पोल हटाए गए थे। मौके से ली गई तस्वीरों में टूटी रेलिंग, गेट, लोहे के फ्रेम, छत की चादरें, ईंट और कंक्रीट बिखरे दिखाई दिए।

जापान के पास 5500 परमाणु बम बनाने का प्लूटोनियम : चीन

एजेंसी, मॉस्को। चीन ने जापान की परमाणु क्षमता को लेकर फिर चिंता जताई है। रूस में चीन के राजदूत झांग हानहुई ने दावा किया कि जापान के पास इतना प्लूटोनियम है, जिससे करीब 5,500 परमाणु हथियार बनाए जा सकते हैं। प्लूटोनियम एक रेडियोएक्टिव तत्व है जो परमाणु ऊर्जा बनाते वक्त यूरेनियम से बनता है। इसे प्रोसेस कर बहुत ज्यादा ऊर्जा बनाई जा सकती है जिसे परमाणु हथियार बनाने में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी तास में लिखे एक लेख में झांग ने कहा कि जापान के पास परमाणु ईंधन को दोबारा प्रोसेस करने और प्लूटोनियम निकालने की तकनीक भी है। उन्होंने कहा कि अगर जापान के पास परमाणु हथियार बनाने की इच्छा और जरूरी क्षमता है, तो वह चाहे तो कभी भी परमाणु हथियार बना सकता है।

भ्रूण लिंग जांच मामलों में पुलिस नहीं कर सकती सीधे एफआईआर

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अधिकृत अधिकारी ही करेंगे शिकायत और कानूनी कार्रवाई

एजेंसी, नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि पुलिस आम तौर पर भ्रूण लिंग का पता लगाने से जुड़े अपराधों की जांच और एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती है। जस्टिस संजय करोल की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि इस कानून के तहत तय किए गए अधिकारियों को ही ऐसे मामलों में मुख्य भूमिका निभानी चाहिए।

कोर्ट ने कहा कि इस कानून के तहत पुलिस जांचकर्ता की भूमिका नहीं निभा सकती है। हालांकि, उपयुक्त प्राधिकारी की जरूरत होने पर पुलिस सीमित और सहायक भूमिका निभा सकती है। उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस फैसले से सहमति जताई, जिसमें कहा गया था कि पीसीपीएनडीटी एक्ट के उल्लंघन के मामलों में पुलिस न तो जांच कर सकती है और न ही एफआईआर दर्ज कर सकती है। कोर्ट ने कहा कि इस कानून से जुड़े मामले तकनीकी प्रकृति के होते हैं, जिनमें चिकित्सकीय जानकारी और संवेदनशीलता की जरुरत होती है। इसलिए कानून के तहत पुलिस को प्राथमिक जांच एजेंसी नहीं बनाया गया है।

मामला उत्तर प्रदेश के एक डॉक्टर से जुड़ा था, जिसके खिलाफ 2017 में पुलिस ने पीसीपीएनटीडी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की थी। डॉक्टर पर आरोप था कि वह अवैध रूप से भ्रूण का लिंग पता कराकर दंपतियों को कन्या भ्रूण को जन्म लेने से रोकने में मदद कर रहा था। डॉक्टर ने उच्च न्यायालय में मामला रद्द करने की मांग करते हुए दलील दी थी कि इस कानून के तहत एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती, क्योंकि धारा 28 के तहत शिकायत दर्ज कराने का अधिकार उचित प्राधिकरण या अधिकृत व्यक्ति को है। उसका कहना था कि उसके मामले में एफआईआर तहसीलदार की ओर से दर्ज की गई थी, जिसे उचित प्राधिकरण नहीं माना जा सकता।

जंतर-मंतर पुलिस कार्रवाई की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बनाई हाई पावर कमेटी

एजेंसी, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने वीरवार को संसद मार्च के दौरान पुलिस की कार्रवाई के आरोपों की जांच के लिए 5 सदस्यों की हाई पावर्ड कमेटी के नामों का ऐलान किया। कमेटी का अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस आर सुभाष रेड्डी को बनाया गया है। इसमें पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस रवि शंकर झा, दिल्ली हाईकोर्ट की पूर्व जज जस्टिस शलिंदर कौर, सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के रिटायर्ड डीजीपी डॉ. एलआर बिश्नोई शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 18 अगस्त को सुनवाई के दौरान इस कमेटी को बनाने का फैसला लिया था। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पैलेटगन इस्तेमाल करने और महिलाओं से बदसलूकी के आरोप लगाए थे। नीट पेपर लीक और परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन जंतर-मंतर पर 36 दिन चला था। 25 जुलाई को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद खत्म हुआ था।

◆ **5 सदस्यीय समिति में रिटायर्ड जज, पूर्व सीबीआई निदेशक व पूर्व डीजीपी शामिल**

हिमाचल की वन संपदा बनेगी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की ताकत: सीएम सुक्खू

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश वन विभाग ने प्रदेश की वन एवं चरागाह आधारित अर्थव्यवस्था की अप्रयुक्त संभावनाओं को विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित व्यवस्था के माध्यम से साकार करने के लिए भारती इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस (आईएसबी-बीआईपीपी) के साथ पांच वर्ष के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की उपस्थिति में हुए समझौते पर वन विभाग की ओर से प्रधान मुख्य अरण्यपाल डॉ. संजय सूद तथा आईएसबी-बीआईपीपी की ओर से कार्यकारी निदेशक प्रो. अश्विनी छत्रे ने हस्ताक्षर किए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह साझेदारी प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे विज्ञान, स्थानीय समुदायों और सरकार को एक मंच पर लाकर वन प्रबंधन में व्यापक बदलाव लाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि स्थानीय वन प्रजातियों की आर्थिक क्षमता का अधिकतम उपयोग किया जाएगा। इनमें हरड़, बेल और थांगी (हैजलनट) जैसी प्रजातियां शामिल हैं। एमओयू से पहले आईएसबी-

◆ **वन अर्थव्यवस्था की 22,600 करोड़ की अप्रयुक्त क्षमता के दोहन के लिए वन विभाग और आईएसबी के बीच एमओयू**

बीआईपीपी टीम ने संयुक्त वन सर्वेक्षण के निष्कर्ष प्रस्तुत किए। सर्वेक्षण में 500 से अधिक वन रक्षकों ने दो लाख से अधिक पेड़ों के आंकड़े और प्रजातियों की पहचान संबंधी तस्वीरें एकत्र कीं।

इन आंकड़ों को सैटेलाइट इमेजरी तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग तकनीक से जोड़ा गया और मौके पर सत्यापन किया गया। खैर, बांस, चीड़, आंवला, जंगली आम, साल और बुरांश सहित सात प्रजातियों के मानचित्र तैयार किए गए हैं। सर्वेक्षण के अनुसार पांच जैव-संसाधनों में कुल 22,600 करोड़ रुपये की अप्रयुक्त आर्थिक क्षमता आंकी गई है। इसमें आंवला की संभावित कीमत 8,700 करोड़ रुपये, चीड़ की पत्तियों की 5,500 करोड़ रुपये, जंगली आम की 4,800 करोड़ रुपये, साल के बीज की 2,400 करोड़ रुपये और बुरांश के फूलों की 1,200 करोड़ रुपये क्षमता शामिल है। इनके दोहन को पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ सीमा तक ही सीमित रखा जाएगा।

एमओयू में वन अर्थव्यवस्था और सामुदायिक उद्यम, फॉरेस्ट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म, चराई पोर्टल एवं चरागाह आधारित डेटाबेस तथा प्रशिक्षण और क्षमता विकास जैसे चार प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं। पालमपुर वन मंडल में इस व्यवस्था का उपयोग पहले ही कार्ययोजना में किया जा रहा है, जिसे आगे पूरे प्रदेश में लागू करने का लक्ष्य है। महिलाओं के स्वामित्व वाली पांगी की पीर पंजाल जंगल प्रोड्यूसर कंपनी को थांगी कारोबार के सफल उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया।

कांग्रेस का पूरा वंदे मातरम न गाना देशविरोधी : अमित शाह

एजेंसी, नई दिल्ली। गृहमंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कहा कि कांग्रेस का वंदे मातरम पूरा न गाने का फैसला हैरान करने वाला और देशविरोधी है। 1937 में कांग्रेस ने जो फैसला लिया था, उसे पीएम मोदी ने सुधारा है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 1937 में राष्ट्रगीत के दो टुकड़े कर मुस्लिम तुष्टीकरण किया था। उस फैसले से दो-राष्ट्र सिद्धांत को मजबूती मिली और आगे चलकर देश का विभाजन हुआ। शाह के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया। पार्टी के सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा- वंदे मातरम स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा था। यह हमारे लिए भावनात्मक मुद्दा है। बीजेपी स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा नहीं थी। उनके लिए यह राजनीतिक मुद्दा है।

दरअसल, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने बुधवार को ऐलान किया कि पार्टी अपने सभी कार्यक्रमों में वंदे मातरम के 6 में से सिर्फ शुरुआती दो पैरा गाएगी। यह फैसला 15 अगस्त को कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम के गायन को लेकर हुए विवाद के बाद आया। एजेंसी, नई दिल्ली। गृहमंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कहा कि कांग्रेस का वंदे मातरम पूरा न गाने का फैसला हैरान करने वाला और देशविरोधी है। 1937 में कांग्रेस ने जो फैसला लिया था, उसे पीएम मोदी ने सुधारा है।

योगी बोले- आईटीआई को उद्योगों से जोड़कर युवाओं के लिए बढ़ाएं रोजगार के अवसर

एजेंसी, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीरवार को व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता विभाग की कार्ययोजना की समीक्षा करते हुए कहा कि आईटीआई को अधिक से अधिक उद्योगों से जोड़ा जाए।

उद्योगों की आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण विकसित करने के साथ ही अप्रेंटिसशिप तथा ऑन-जॉब प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया जाए, ताकि प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि कौशल विकास को रोजगार के साथ वैश्विक अवसरों से भी जोड़ा जाए। आईटीआई और उद्योगों के बीच निरंतर संवाद की व्यवस्था होनी चाहिए और प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर नियमित रोजगार मेलों का आयोजन किया जाए।

मुख्यमंत्री ने सेंटर फॉर इनोवेशन, इन्वेंशन, इन्क्यूबेशन एंड ट्रेनिंग (सीआईआईआईटी) केंद्रों की प्रगति की समीक्षा करते हुए गोरखपुर, मुजफ्फरनगर और बरेली केंद्रों का संचालन शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन केंद्रों को आधुनिक तकनीक और उद्योग आधारित प्रशिक्षण के उत्कृष्ट केंद्र के रूप में विकसित किया जाए।

कांग्रेस नेता सज्जन का निधन, 1984 सिख विरोधी दंगों के मामलों में थे दोषी

एजेंसी, नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार का गुरुवार को 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। एएनआई के सूत्रों के अनुसार, उन्हें दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मृत अवस्था में लाया गया था। सज्जन कुमार 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद तिहाड़ जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे थे। तीन प्रमुख मामलों में से एक में उन्हें बरी किया गया था, जबकि दो मामलों में दोषी ठहराया गया था।

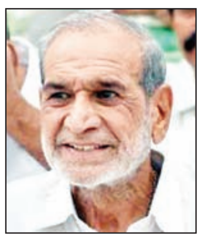

सज्जन कुमार का जन्म 23 सितंबर 1945 को दिल्ली में हुआ था। उन्होंने 1977 में दिल्ली नगर निगम पार्षद के रूप में राजनीतिक सफर शुरू किया और बाद में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के महासचिव बने। वर्ष 1980 में वे पहली बार बाहरी दिल्ली से लोकसभा सांसद चुने गए। इसके बाद 1991 और 2004 में भी सांसद रहे।

1984 के दंगों से जुड़े मामलों ने उनके राजनीतिक जीवन को प्रभावित किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिसंबर 2018 में पालम कॉलोनी में पांच सिखों की हत्या के मामले में उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई थी। फरवरी 2025 में सरस्वती विहार में पिता-पुत्र की हत्या के मामले में भी उन्हें उम्रकैद की सजा मिली थी। वहीं, सुल्तानपुरी में तीन सिखों की हत्या के एक मामले में सितंबर 2023 में उन्हें बरी कर दिया गया था।

ईरान पर होगी सबसे बड़ी 'आर्थिक कार्रवाई': ट्रंप

एजेंसी, वॉशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अब तक की सबसे सख्त आर्थिक कार्रवाई की धमकी दी। उन्होंने कहा कि ईरान को अमेरिका के साथ समझौता करने का सबसे बड़ा मौका दिया गया था, लेकिन उसने इसे गंवा दिया। ट्रंप ने कहा, ईरान को किसी समझौते के लिए मुझसे ज्यादा बड़ा मौका किसी ने नहीं दिया। दुख की बात है कि उन्होंने इस मौके का फायदा नहीं उठाया। इसलिए आज मैं किसी भी देश के खिलाफ अब तक की सबसे कड़ी आर्थिक कार्रवाई की घोषणा कर रहा हूं। उन्होंने दावा किया कि ईरान की नौसेना खत्म हो चुकी है। उसकी वायु सेना नष्ट हो गई है। उसकी सैन्य फैक्टरियां मलबे में बदल गई हैं। ईरान की मुद्रा बेकार हो गई है और देश बेहद कमजोर स्थिति में है।' ट्रंप ने कहा कि जो भी देश ईरान को किसी भी तरह की आर्थिक मदद देगा, उसे भी बड़े आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ेगा।

दिल्ली मास्टर प्लान 2047 जारी, 40 लाख नए आवास व 695 किमी होगा मेट्रो नेटवर्क

एजेंसी, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी के अगले दो दशकों के सुनियोजित और सतत विकास के लिए 'मास्टर प्लान फॉर दिल्ली 2047' जारी कर दिया है। योजना में वर्ष 2047 तक 3.2 करोड़ की अनुमानित आबादी के लिए 30 से 40 लाख नए आवास विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल, उपराज्यपाल सरदार तरनजीत सिंह संधू व सीएम रेखा गुप्ता ने इसे औपचारिक रूप से जारी किया।

मास्टर प्लान के तहत दिल्ली मेट्रो नेटवर्क को वर्तमान 416 किलोमीटर से बढ़ाकर 695 किलोमीटर करने का प्रस्ताव है। इसके साथ छह नई आरआरटीएस लाइनों तथा सरायकाले खां, आनंद विहार और कश्मीरी गेट को आधुनिक मल्टी-मॉडल ट्रांजिट हब के रूप में विकसित करने की योजना है। सीमित भूमि के बेहतर उपयोग के लिए ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट में अधिकतम एफएआर 500 किया गया है। 30 मीटर या उससे अधिक चौड़ी सड़कों से लगे आवासीय भूखंडों पर शुल्क के साथ वाणिज्यिक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी। विकास नियमों को सरल बनाने के लिए परिसर श्रेणियों की संख्या 133 से घटाकर 45 कर दी गई है।

योजना में यमुना के दोनों किनारों पर 52 किलोमीटर साइकिल ट्रैक और 150 किलोमीटर पाथ कनेक्टर विकसित करने का लक्ष्य है। कुछ क्षेत्रों को 24 आवर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। साथ ही यमुना खादर और दिल्ली रिज के वन क्षेत्र को संरक्षित रखने तथा करीब 1,500 हेक्टेयर ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण पर जोर दिया गया है। डेटा सेंटर, स्टार्टअप हब और क्लाउड किचन जैसी नई आर्थिक गतिविधियों को भी मान्यता दी गई है।

प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री से जुड़ी याचिका पर सुनवाई टली

एजेंसी, नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की डिग्री का खुलासा करने से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई 29 सितंबर तक टाल दी है। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह आदेश दिया। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से मामले को दोपहर बाद सुनने का अनुरोध किया गया। इस पर अदालत ने दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से उपलब्धता पूछी। मेहता ने पहले अगले दिन सुनवाई का सुझाव दिया, लेकिन अदालत ने 29 सितंबर की तारीख तय कर दी। याचिकाकर्ताओं में आप सांसद संजय सिंह, आरटीआई कार्यकर्ता नीरज शर्मा और अधिवक्ता मोहम्मद इरशाद शामिल हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय ने डिग्री संबंधी जानकारी को निजी बताते हुए साझा करने पर आपत्ति जताई है। विश्वविद्यालय का कहना है कि इससे कोई सार्वजनिक हित पूरा नहीं होता।

चंपत राय बोले-राम मंदिर निर्माण समिति अध्यक्ष ने की मनमानी

एजेंसी, अयोध्या। अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट से इस्तीफे के बाद चंपत राय ने वीरवार को 9 पन्नों का दूसरा लेटर जारी किया। इसमें उन्होंने मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष और पूर्व आईएएस अधिकारी नृपेंद्र मिश्र की भूमिका को लेकर कई दावे किए हैं।

चंपत राय ने कहा, 'राम मंदिर निर्माण के लिए बने ट्रस्ट में 15 ट्रस्टी थे और नृपेंद्र मिश्र को निर्माण समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। मिश्र के सुझाव पर लार्सन एंड टूब्रो (L&T) को मंदिर निर्माण की जिम्मेदारी दी गई। भवनों के डिजाइन और निर्माण से जुड़े काम के लिए नोएडा की डिजाइन एसोसिएट फर्म का चयन भी किया। चंपत राय ने कहा कि नृपेंद्र मिश्र ने निर्माण समिति में अपनी पसंद के लोगों को शामिल किया। इनमें से कुछ लोग छह साल के दौरान केवल एक-दो बार ही अयोध्या आए। पूर्व एनबीसीसी चेयरमैन अनूप मित्तल लगातार नृपेंद्र मिश्र के साथ निर्माण समिति की बैठकों में शामिल होते थे।

◆ **कहा- पूर्व आईएएस नृपेंद्र ने सलाह कभी नहीं मानी अपनी पसंद के लोग चुने**

चंपत राय ने चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने के बाद 26 जून को महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया था। 6 जुलाई को ट्रस्ट की बैठक में इस्तीफा मंजूर किया गया था। उसी दिन चंपत राय ने एक लेटर जारी कर ट्रस्टी अनिल मिश्र पर गंभीर आरोप लगाए थे।

अमेरिकी में आरएसएस पर बैन लगाने की पैरवी

एजेंसी, वॉशिंगटन। अमेरिकी धार्मिक स्वतंत्रता आयोग ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने अमेरिकी सरकार से आरएसएस नेताओं को राजनयिक सम्मान नहीं देने और उनके साथ उच्चस्तरीय बैठकें नहीं करने को कहा है। आयोग के चेयरमैन आसिफ महमूद ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस के सदस्य हैं और इसके सहयोगी संगठनों ने धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमले किए हैं। पाकिस्तानी मूल के महमूद का यह बयान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के अमेरिका दौरे से कुछ दिन पहले आया है। भागवत 25 अगस्त से अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन के दौरे पर जाएंगे। भागवत 29 अगस्त को न्यूयॉर्क में अमेरिकन हिंदूज फॉर एंगेजमेंट एंड डायलॉग के 'यूनिवर्सल ऑननेस सेलिब्रेशंस' कार्यक्रम में शामिल होंगे।

प्रॉपर्टी आईडी को लेकर मुख्यमंत्री सैनी की दो टूक बोले- शिकायत चंडीगढ़ तक पहुंची तो होगी कार्रवाई

एजेंसी, चंडीगढ़। हरियाणा के शहरों से लगातार आ रही प्रापर्टी आईडी से संबंधित शिकायतों पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अधिकारियों को दो टूक निर्देश दिए हैं कि प्रापर्टी आईडी से संबंधित कोई भी शिकायत चंडीगढ़ नहीं पहुंचनी चाहिए। ऐसी कोई शिकायत मिलने पर अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसलिए अधिकारी उनका निवारण अपने स्तर पर जल्द सुनिश्चित करें।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बुधवार बीती रात चंडीगढ़ में शहरी स्थानीय निकाय, नगर योजनाकर एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ पीआईडी को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन एवं शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि क्रीड के साथ शहरी स्थानीय निकाय की समन्वय बैठक आयोजित कर पीआईडी से संबंधित समस्याओं का त्वरित गति से समाधान सुनिश्चित किया जाए ताकि जनता को किसी प्रकार की दिक्कतें पेश न आए। उन्होंने अधिकारियों को पूरे सिस्टम को भी दुरूस्त करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि चार लाख 42 हजार 570 प्रोप्रटीज की दो लाख 79 हजार 658 पीआईडी अप्रूव की जा चुकी हैं। शेष प्रोप्रटीज की आईडी को भी जल्द ही पूरा कर दिया जाएगा। इसी प्रकार विभाजित की जाने वाली 63 हजार 878 पीआईडी में से भी 36 हजार 545 पीआईडी अप्रूव कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि 50 लाख 50 हजार 72 प्रोप्रटीज में से स्थानीय निकायों संबंधित 19 हजार 403 ऑब्जेक्शन लंबित हैं। उन्हें भी जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा।

◆ **अधिकारियों को अपने स्तर पर शिकायतों के त्वरित समाधान के निर्देश**

मुख्यमंत्री ने प्रोप्रटी आईडी को लेकर विस्तृत जानकारी लेते हुए कहा कि वैद्य कालोनियों की सीमा में यदि कोई प्लाट खाली है तो उसे भी वैद्य मानते हुए एचएसवीपी की तर्ज पर एक्सटेशन फीस लेकर कार्यवाई अमल में लाई जाए। इसके अलावा यदि किसी प्लाट या मकान में कमर्शियल गतिविधिया संचालित है तो उसे भी विकास शुल्क आदि चार्ज लेकर अनुमति प्रदान की जाए।

सौगात चंपावत में स्वास्थ्य सेवाओं को मिली बड़ी सौगात, मुख्यमंत्री ने ब्लड कंपोनेंट यूनिट की लोकार्पित

चंपावत केवल विस क्षेत्र नहीं, मेरी कर्मभूमि है: सीएम धामी

एजेंसी, चंपावत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से जिला चिकित्सालय चंपावत में करीब 50 लाख की लागत से स्थापित ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट का वीरवार को लोकार्पण करते हुए कहा कि यह सुविधा जिले में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि चंपावत उनके लिए केवल विधानसभा क्षेत्र नहीं, बल्कि कर्मभूमि है। जिले में पहली बार ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन की सुविधा उपलब्ध हुई है।

उन्होंने कहा कि जिले में पहली बार ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन की सुविधा उपलब्ध हुई है। इससे आपातकालीन परिस्थितियों में मरीजों को आवश्यक जीवनरक्षक रक्त घटक स्थानीय स्तर पर समय पर उपलब्ध हो सकेंगे। इससे पहले कुमाऊं मंडल के जिला चिकित्सालयों में यह सुविधा रुद्रपुर और पिथौरागढ़ में उपलब्ध थी।

उन्होंने कहा कि चंपावत को आदर्श जिला बनाने के संकल्प के तहत स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जिला चिकित्सालय में करीब 20 करोड़ रुपये की लागत से 50 बेड का अत्याधुनिक क्रिटिकल केयर ब्लॉक तैयार किया गया है। इसके अलावा सीटी स्कैन, एमआरआई और डायलिसिस यूनिट जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा चुकी हैं। करीब 11.71 करोड़ रुपये की लागत से पार्किंग, डायग्नोस्टिक विंग और ऑपरेशन थिएटर का निर्माण कार्य जारी है।

स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक, सुलभ और जन-केंद्रित बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। जिला चिकित्सालय चंपावत में ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट की स्थापना से गंभीर एवं आपातकालीन परिस्थितियों में मरीजों को आवश्यक रक्त घटक स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो सकेंगे। इससे मरीजों को समय पर उपचार मिलने के साथ ही अन्य जिलों के अस्पतालों पर निर्भरता भी कम होगी।

आधारभूत सुविधाओं को मिलेगी नई मजबूती

धामी ने कहा कि जिले में सड़क, पार्किंग, पेयजल और ड्रेनेज जैसी आधारभूत सुविधाओं को भी मजबूत किया जा रहा है। चंपावत रोडवेज स्टेशन पर 62 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से आधुनिक बहुमंजिला पार्किंग एवं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण प्रस्तावित है। वहीं 66 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से आधुनिक सिटी ड्रेनेज सिस्टम तथा 240 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से पेयजल व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है।

विकास परियोजनाओं से बदलेगी जिले की तस्वीर

मुख्यमंत्री ने कहा कि साइंस सेंटर, महिला स्पोर्ट्स कॉलेज और आधुनिक आईएसबीटी जैसी परियोजनाएं जिले के विकास को नई दिशा देंगी। सरकार चंपावत को स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, रोजगार और आधारभूत सुविधाओं के क्षेत्र में उत्तराखंड का आदर्श मॉडल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

हनुमान मंदिर चोरी का आरोपी लुधियाना से गिरफ्तार, नकदी बरामदगी में जुटी पुलिस

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। शिमला जिले के रामपुर में मेन बाजार स्थित हनुमान मंदिर से नकदी चोरी के मामले में पुलिस ने 21 वर्षीय युवक को लुधियाना से गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी घटना के बाद लगातार अपनी जगह बदलकर गिरफ्तारी से बचने का प्रयास कर रहा था। तकनीकी जांच और सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने आरोपी की पहचान कर उसे पकड़ने में सफलता हासिल की।

पुलिस के अनुसार 15 अगस्त को हनुमान मंदिर से नकदी चोरी होने की शिकायत मिली थी। शिकायत के आधार पर सिटी रामपुर थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 331(4) और 305 के तहत मामला दर्ज किया गया। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू करते हुए मंदिर और आसपास के क्षेत्रों में लगे निगरानी कैमरों की फुटेज खंगाली।

जांच के दौरान पुलिस टीम को महत्वपूर्ण सुराग मिले। फुटेज और तकनीकी जानकारी के आधार पर संदिग्ध की पहचान 21 वर्षीय सौरव पुत्र दीप बहादुर निवासी कुल्लू के रूप में हुई। इसके बाद पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी।

पुलिस के मुताबिक चोरी की घटना के बाद आरोपी लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था और पुलिस की पकड़ से बचने का प्रयास कर रहा था। पुलिस टीम ने तकनीकी माध्यमों से उसकी गतिविधियों पर नजर रखी और लगातार तलाश जारी रखी। इसके बाद आरोपी की लोकेशन लुधियाना में मिली, जहां पुलिस टीम ने वीरवार को उसे विधि अनुसार गिरफ्तार कर लिया।

आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने मामले की आगे की जांच शुरू कर दी है। पुलिस चोरी की गई नकदी की बरामदगी के साथ घटना में इस्तेमाल किए गए साधनों और अन्य संभावित तथ्यों की जानकारी जुटा रही है। पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आरोपी ने चोरी की वारदात को किस तरह अंजाम दिया और उसके साथ कोई अन्य व्यक्ति शामिल था या नहीं।

सुक्खू सरकार पर कश्यप का हमला, विकास ठप होने और कर्ज बढ़ने पर उठाए गंभीर सवाल

कश्यप ने सरकार पर बढ़ते कर्ज और ठप विकास को लेकर साधा निशाना, हिमकेयर बचाने की उठाई मांग

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता , शिमला। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला। सीपीआरआई मुख्यालय में आयोजित स्थापना दिवस कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत में कश्यप ने कहा कि मुख्यमंत्री को भाजपा सांसदों की भूमिका पर सवाल उठाने के बजाय अपने तीन साल से अधिक के कार्यकाल, प्रदेश की बिगड़ती आर्थिक स्थिति, बढ़ते कर्ज और ठप पड़े विकास कार्यों की चिंता करनी चाहिए।

कश्यप ने कहा कि भाजपा सांसदों को मुख्यमंत्री से किसी प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं है। लोकसभा और राज्यसभा के सांसद अपनी संवैधानिक एवं राजनीतिक जिम्मेदारियों को अच्छी तरह समझते हैं और हिमाचल के हितों की आवाज उठाना जानते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश से जुड़े मुद्दे समय-समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के समक्ष उठाए गए हैं तथा केंद्र ने हिमाचल को हरसंभव सहयोग दिया है।

केंद्र से सहायता लेकर धन्यवाद भी भूल जाती सरकार : सुरेश कश्यप ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार के मंत्री दिल्ली जाकर केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करते हैं और विकास योजनाओं के लिए धनराशि प्राप्त करते हैं, लेकिन बाद में केंद्र सरकार का धन्यवाद करना भूल जाते हैं। उन्होंने कहा कि विशेष श्रेणी राज्य होने के कारण हिमाचल को कई केंद्रीय योजनाओं में 90:10 के अनुपात में सहायता मिल रही है। आपदा और विकास दोनों परिस्थितियों में केंद्र सरकार ने प्रदेश की मदद की है।

उन्होंने राजस्व घाटा अनुदान को लेकर कहा कि यह अस्थायी व्यवस्था थी। सरकार को केंद्र पर निर्भर रहने के बजाय अपनी आय बढ़ाने, अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण करने और कर्ज का बोझ कम करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।

अधिकारियों का कैडर घटाने पर सवाल : आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के कैडर में कमी के प्रस्ताव पर कश्यप ने कहा कि सरकार को अधिकारियों की संख्या घटाने के बजाय अनावश्यक राजनीतिक नियुक्तियों और फिजूलखर्ची पर रोक लगानी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपने मित्रों की नियुक्तियों और गैरजरूरी खर्चों को कम करने के बजाय प्रशासनिक व्यवस्था पर बोझ डाल रही है।

भाजपा में गुटबाजी के आरोप खारिज : भाजपा में गुटबाजी के कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए कश्यप ने कहा कि भाजपा का केवल एक ही गुट है और वह भारतीय जनता पार्टी है। उन्होंने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा मजबूती के साथ मैदान में उतरेगी। पंचायत और शहरी निकाय चुनावों के परिणामों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि जनता का रुझान भाजपा के पक्ष में दिखाई दे रहा है। हिमकेयर योजना पर कश्यप ने कहा कि यह गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है।

पहली पत्नी के बाद दूसरी पत्नी का पेंशन दावा हाई कोर्ट ने ठुकराया

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने पारिवारिक पेंशन से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में स्पष्ट किया है कि पहली पत्नी के जीवित रहते हुए किया गया दूसरा विवाह कानून की नजर में वैध नहीं माना जाएगा। ऐसी स्थिति में पहली पत्नी की मृत्यु के बाद दूसरी पत्नी को पारिवारिक पेंशन पर दावा करने का अधिकार नहीं है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की एकल पीठ ने दमयंती देवी की याचिका खारिज करते हुए यह व्यवस्था दी।

मामले के अनुसार दमयंती देवी के पति खूब राम शिक्षा विभाग में कनिष्ठ बुनियादी शिक्षक के पद पर कार्यरत थे और एक जून 1996 को सेवानिवृत्त हुए थे। खूब राम की पहली पत्नी खिमी देवी थीं। पहली पत्नी से कोई संतान नहीं होने के कारण खूब राम ने पांच दिसंबर 1970 को दमयंती देवी से दूसरा विवाह किया था।

खूब राम की मृत्यु 13 अक्टूबर 2014 को हुई। उनकी मृत्यु के बाद नियमानुसार पहली पत्नी खिमी देवी को पारिवारिक पेंशन मिल रही थी। दो जुलाई 2023 को खिमी देवी का भी निधन हो गया। इसके बाद दमयंती देवी ने स्वयं को जीवित विधवा बताते हुए अपने नाम पर पारिवारिक पेंशन जारी करने और पिछले बकाया का भुगतान करने की मांग की।

मामला हाई कोर्ट पहुंचने पर अदालत ने विवाह की वैधता और पेंशन के अधिकार से जुड़े प्रावधानों पर विचार किया। अदालत ने कहा कि जब पहली पत्नी का विवाह कानूनी रूप से कायम था, उसी दौरान किया गया दूसरा विवाह वैध नहीं माना जा सकता। इसलिए दूसरी पत्नी को पहली पत्नी की मृत्यु के बाद पारिवारिक पेंशन का उत्तराधिकारी नहीं माना जा सकता।

अदालत ने याचिकाकर्ता की ओर से किए गए पेंशन संबंधी दावे को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और याचिका खारिज कर दी। इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों की पारिवारिक पेंशन में वैध वैवाहिक संबंध और उत्तराधिकार की स्थिति को लेकर महत्वपूर्ण कानूनी स्थिति स्पष्ट हुई है।

हिमाचल में लॉटरी की वापसी तय, जानिए नियम और शर्तों का पूरा ब्यौरा

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश में करीब 25 साल से बंद लॉटरी व्यवस्था को दोबारा शुरू करने की प्रक्रिया निर्णायक चरण में पहुंच गई है। वित्त विभाग के तहत निदेशालय कोषागार, लेखा एवं लॉटरी ने कागजी और ऑनलाइन लॉटरी की बिक्री के लिए एकमात्र बिक्री एजेंट नियुक्त करने को ई-निविदा जारी की है। सरकार का लक्ष्य लॉटरी संचालन को डिजिटल, पारदर्शी और कड़े नियमन के तहत चलाना है।

निविदा की शर्तों के अनुसार प्रतिदिन अधिकतम 12 लॉटरी ड्रा आयोजित किए जा सकेंगे। वर्ष में तीन बड़े ड्रा भी होंगे। 26 जनवरी, 15 अगस्त और दो अक्टूबर को ड्रा आयोजित नहीं किया जाएगा। सभी ड्रा हिमाचल के सार्वजनिक स्थानों पर निर्णायकों और स्वतंत्र पर्यवेक्षकों की निगरानी में होंगे। चयनित एजेंट को सरकार को प्रतिवर्ष 10 करोड़ रुपये लाइसेंस शुल्क देना होगा, जिसमें हर वर्ष पांच प्रतिशत वृद्धि होगी।

मानसून सत्र को लेकर शिमला में 750 जवानों का सुरक्षा घेरा

शिमला में सत्र से पहले कड़ी सुरक्षा

भारतेन्दु संवादाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान राजधानी शिमला में सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए पुलिस ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। विधानसभा सत्र के शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित संचालन के लिए करीब 750 पुलिसकर्मियों और अन्य सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। विधानसभा परिसर और आसपास के क्षेत्र को सुरक्षा की दृष्टि से तीन मुख्य सेक्टरों तथा विभिन्न उपखंडों में बांटा गया है।

प्रत्येक उपखंड की जिम्मेदारी राजपत्रित पुलिस अधिकारी को सौंपी गई है। सभी क्षेत्रों में पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने के साथ बहुस्तरीय जांच और निगरानी व्यवस्था लागू की गई है। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को दक्षिणी रेंज की पुलिस उपमहानिरीक्षक अंजुम आरा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शिमला गौरव सिंह ने विस्तृत जानकारी दी। अधिकारियों ने पुलिसकर्मियों को उनकी जिम्मेदारियों और सुरक्षा संबंधी दिशा-निर्देशों से अवगत करवाया।

प्रवेश मार्गों पर बढ़ाई निगरानी : विधानसभा सत्र को देखते हुए शिमला शहर में प्रवेश करने वाले प्रमुख मार्गों पर भी पुलिस का पहरा बढ़ा दिया गया है। शोघी, मेहली, मशोबरा-ढली बाईपास और तवी मोड़ सहित अन्य प्रवेश मार्गों पर वाहनों की जांच की जा रही है। पुलिस संदिग्ध व्यक्तियों और गतिविधियों पर विशेष नजर रख रही है।

रात में भी जारी रहेगी गश्त : सुरक्षा व्यवस्था के तहत रात के समय भी विशेष जांच और गश्त की जाएगी। होटलों, सरायों और अन्य ठहरने वाले स्थानों की जांच का अभियान भी जारी है। पुलिस का खुफिया और आसूचना तंत्र सक्रिय कर दिया गया है, ताकि किसी भी संभावित सुरक्षा चुनौती की समय रहते पहचान की जा सके।

यातायात व्यवस्था के लिए विशेष योजना : सत्र के दौरान यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए प्रमुख मार्गों, चौराहों और संवेदनशील स्थानों पर यातायात पुलिस की तैनाती की गई है। जरूरत पड़ने पर यातायात को नियंत्रित करने के साथ मार्गों में अस्थायी बदलाव भी किए जाएंगे। पुलिस का उद्देश्य विधानसभा सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के साथ आम लोगों को न्यूनतम परेशानी सुनिश्चित करना है।

आंगनबाड़ी केंद्रों में रिक्त पदों पर चयनित अभ्यर्थियों के परिणाम घोषित

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। बाल विकास परियोजना अधिकारी इंदु शर्मा ने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत बाल विकास परियोजना शिमला शहरी के अधीन संचालित आंगनबाड़ी एवं क्रेच केंद्रों में रिक्त पदों के लिए चयन प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। 18 अगस्त 2026 को चयन समिति द्वारा आयोजित साक्षात्कार के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों के परिणाम घोषित किए गए हैं।

क्रेच कार्यकर्ता के पद पर साधनाघाटी के लिए प्रिया, स्ट्रॉबेरी ब्रोकहास्ट के लिए सुमन, आरटीओ के लिए करिश्मा तथा टूटूंडी के लिए शरोती का चयन हुआ है। क्रेच सहायिका पद पर कुफ्टाधार के लिए अर्चना और बंगाला कॉलोनी के लिए सरिता चयनित हुई हैं। आंगनबाड़ी सहायिका पद पर कृष्णानगर केंद्र के लिए तनुजा का चयन किया गया है। कुफ्टाधार क्रेच सहायिका पद के लिए ममता को प्रतीक्षा सूची में रखा गया है।

एरियर भुगतान पर ग्रुप-डी कर्मचारियों ने जताया आभार

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा नियमित ग्रुप-डी कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान के लंबित एरियर की 20 हजार रुपये राशि अगस्त 2026 में नकद भुगतान करने के निर्णय का चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महासंघ ने स्वागत किया है। महासंघ ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश सरकार का आभार जताते हुए इसे लंबे समय से एरियर की प्रतीक्षा कर रहे कर्मचारियों के लिए राहत भरा कदम बताया।

ग्रुप-डी कर्मचारी संघ के प्रधान संदीप सिंह, महासचिव नरेंद्र कुमार, वरिष्ठ उपप्रधान संजय, संयुक्त सचिव जसविंदर सिंह सहित अन्य पदाधिकारियों और सदस्यों ने सरकार के निर्णय पर खुशी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हजारों कर्मचारी लंबे समय से संशोधित वेतनमान के एरियर के भुगतान की प्रतीक्षा कर रहे थे। ऐसे में सरकार द्वारा अगस्त माह में 20 हजार रुपये की राशि नकद देने का निर्णय कर्मचारियों के लिए आर्थिक राहत लेकर आया है।

संघ पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार के इस निर्णय से कर्मचारियों में सकारात्मक संदेश गया है। उन्होंने प्रदेश के समस्त कर्मचारियों की ओर से मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हुए उम्मीद जताई कि भविष्य में भी सरकार कर्मचारी हितों से जुड़े मामलों को प्राथमिकता के आधार पर हल करेगी।

15 प्रतिशत महंगाई भत्ते की भी मांग : महासंघ ने मुख्यमंत्री के समक्ष कर्मचारियों के लंबित 15 प्रतिशत महंगाई भत्ते का मुद्दा भी उठाया। संघ ने कहा कि कर्मचारियों का 15 प्रतिशत महंगाई भत्ता देय हो चुका है। ऐसे में सरकार को इस संबंध में जल्द आवश्यक घोषणा कर कर्मचारियों को राहत प्रदान करनी चाहिए।

संघ पदाधिकारियों ने विश्वास जताया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कर्मचारियों की इस जायज मांग पर भी सकारात्मक निर्णय लेंगे। उन्होंने कहा कि महंगाई के मौजूदा दौर में कर्मचारियों के लिए लंबित भत्तों का भुगतान काफी महत्वपूर्ण है और इससे उनके आर्थिक बोझ को कम करने में मदद मिलेगी।

महासंघ ने कहा कि प्रदेश के कर्मचारी सरकार के साथ सहयोग करते हुए अपने दायित्वों का पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निर्वहन कर रहे हैं। कर्मचारी भविष्य में भी सरकार की जनहितकारी योजनाओं और कार्यों को धरातल पर पहुंचाने में पूरा सहयोग देते रहेंगे।

जुन्गा पंचायत ने विकास कार्यों के लिए मंत्री से मांगी अतिरिक्त धनराशि

जुन्गा में बढ़ती आबादी के बीच सफाई सड़क और मूलभूत सुविधाओं के विस्तार की मांग

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। ग्राम पंचायत जुन्गा के प्रतिनिधिमंडल ने प्रधान रामलाल के नेतृत्व में ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह से उनके कार्यालय में शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने पंचायत क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न विकासात्मक समस्याओं और मूलभूत सुविधाओं की जरूरतों को मंत्री के समक्ष रखा। पंचायत प्रतिनिधियों ने जुन्गा के समग्र विकास के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने का आग्रह किया।

प्रधान रामलाल ने मंत्री को बताया कि जुन्गा क्षेत्र पिछले कुछ वर्षों में तेजी से विकसित हो रहा है। अब यह केवल एक गांव तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि धीरे-धीरे कस्बे का रूप ले रहा है। क्षेत्र में बढ़ती आबादी और व्यावसायिक गतिविधियों के कारण पंचायत पर सफाई व्यवस्था, सड़कों, नालियों तथा अन्य नागरिक सुविधाओं के रखरखाव का अतिरिक्त आर्थिक भार पड़ रहा है।

उन्होंने कहा कि पंचायत के पास आय के साधन सीमित हैं। ऐसे में बढ़ती जरूरतों के अनुरूप विकास कार्य करवाने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध नहीं हो पा रही है। पंचायत प्रतिनिधियों ने जुन्गा में बेहतर सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने, सड़कों और नालियों की स्थिति सुधारने तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं के विस्तार के लिए अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध करवाने की मांग की।

प्रधान ने कहा कि जुन्गा के सुनियोजित विकास के लिए पंचायत को पर्याप्त आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है। इससे क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के साथ-साथ स्थानीय लोगों को बेहतर नागरिक सेवाएं उपलब्ध करवाई जा सकेंगी।

ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि जुन्गा के चहुंमुखी विकास में धन की कमी को आड़े नहीं आने दिया जाएगा। उन्होंने पंचायत को सरकार की ओर से हरसंभव सहयोग और सहायता उपलब्ध करवाने का भरोसा दिलाया।

मंत्री ने पंचायत प्रतिनिधियों से पंचायत स्तर पर आय के नए और स्थायी संसाधन विकसित करने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि स्थानीय निकायों को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने से विकास कार्यों को गति मिलेगी तथा पंचायत अपनी आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा कर सकेगी। प्रतिनिधिमंडल में उपप्रधान ईश्वर दत्त शर्मा, वार्ड सदस्य योगमाया शर्मा, उर्मिल, रेखा, रमेश और अजय सहित अन्य सदस्य शामिल रहे।

रामपुर खेल मैदान को मिलेगा नया रूप, हाइड्रोसीडिंग से उगेगी हरी घास

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। वन विभाग हिमाचल प्रदेश की वार्षिक खेलकूद एवं कर्तव्य प्रतियोगिता को देखते हुए पाटबंगला स्थित पीजी कालेज रामपुर मैदान को सुंदर और व्यवस्थित बनाने का काम तेज हो गया है। मैदान को समतल करने के बाद अब हाइड्रोसीडिंग तकनीक से घास उगाने की तैयारी की गई है। इसके लिए शुक्रवार 21 अगस्त से मैदान के दोनों गेट करीब एक सप्ताह तक बंद रहेंगे।

वन विभाग ने आम जनता से अपील की है कि घास उगाने की प्रक्रिया के दौरान मैदान में प्रवेश न करें, ताकि नई घास को नुकसान न पहुंचे और वह अच्छी तरह विकसित हो सके। विभाग का कहना है कि मैदान को बेहतर स्वरूप देने के लिए स्थानीय प्रशासन और आम जनता का सहयोग बेहद जरूरी है।

पाटबंगला मैदान में 11 से 13 सितंबर तक वार्षिक खेलकूद एवं कर्तव्य प्रतियोगिता आयोजित होनी है। प्रतियोगिता की तारीख तय होने के बाद वन वृत्त रामपुर ने मैदान को समतल, स्वच्छ और खेल गतिविधियों के अनुकूल बनाने का कार्य शुरू किया। इसी क्रम में हाइड्रोसीडिंग तकनीक से घास उगाने का निर्णय लिया गया है। घास तैयार होने के बाद मैदान की सुंदरता बढ़ने के साथ खिलाड़ियों को बेहतर सुविधा मिलने की उम्मीद है।

मैदान को समतल करने के कार्य में अरण्यपाल रामपुर सीबी ताशीलदार, वन मंडलाधिकारी गुरहर्ष सिंह सहित वन परिक्षेत्र अधिकारियों, उप वन परिक्षेत्र अधिकारियों, वन रक्षकों, वन मित्रों और अन्य कर्मचारियों ने योगदान दिया। विभाग का प्रयास है कि प्रतियोगिता से पहले मैदान को बेहतर रूप दिया जा सके।

परिवहन कर्मचारियों ने निगम सुधार को लेकर उठाईं अहम मांगें

कर्मचारियों की लंबित समस्याएं दूर करने और बस सेवाएं बढ़ाने की उठी मांग

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। परिवहन कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति की महत्वपूर्ण बैठक शिमला में समिति के अध्यक्ष समर चौहान की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में हिमाचल पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों से जुड़ी विभिन्न लंबित समस्याओं, कार्य परिस्थितियों और निगम की कार्यप्रणाली में सुधार से संबंधित विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में समिति के अध्यक्ष समर चौहान, उपाध्यक्ष हरीश पराशर, सचिव खेमेन्द्र गुप्ता, प्रवक्ता हरी कृष्ण, राजेश ठाकुर सहित सभी आठ संगठनों के प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक के बाद समिति की ओर से निगम प्रबंधन को सुझाव और मांग-पत्र सौंपा गया। इसमें कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित समस्याओं का समाधान करने के साथ निगम की कार्यप्रणाली को अधिक व्यावहारिक, पारदर्शी और कर्मचारी हितैषी बनाने की मांग की गई।

समिति ने मांग की कि यात्रियों की वास्तविक आवश्यकता और मांग को ध्यान में रखते हुए बस सेवाओं का विस्तार किया जाए। केवल रूट कम करने के बजाय ऐसे मार्गों पर सेवाएं बढ़ाई जाएं, जहां यात्रियों की संख्या अधिक है। इससे यात्रियों को सुविधा मिलने के साथ निगम की आय में भी वृद्धि हो सकती है।

परिचालकों की वेतन विसंगति के मामले में उच्च न्यायालय के आदेश को तत्काल लागू करने की मांग भी उठाई गई। इसके अलावा बिना टिकट यात्रियों के संबंध में जारी मानक संचालन प्रक्रिया की समीक्षा करने तथा हर स्थिति में केवल परिचालक को जिम्मेदार ठहराने की व्यवस्था में बदलाव करने की मांग की गई। समिति ने सामान नीति और ढाबा तथा ठहराव नीति की भी समीक्षा करने का सुझाव दिया।

बैठक में कार्यशालाओं में कल-पुर्जों की कमी का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। समिति ने बसों की समयबद्ध मरम्मत और रखरखाव सुनिश्चित करने तथा चालकों और परिचालकों के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार उचित विश्रामगृह उपलब्ध कराने की मांग की।

कर्मचारियों की मांगों पर प्रबंधन हो गंभीर

कर्मचारियों की ड्यूटी और समय-सारणी को व्यावहारिक बनाने पर भी जोर दिया गया। समिति ने कहा कि ड्यूटी निर्धारित करते समय वास्तविक परिचालन परिस्थितियों और कर्मचारियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। साथ ही चालकों और परिचालकों के वेतन, ड्यूटी, अवकाश, विश्राम तथा अन्य सेवा संबंधी मामलों का समयबद्ध समाधान करने की मांग की गई। समिति ने लंबित वेतन, भत्तों और अन्य सेवा लाभों से जुड़े मामलों का शीघ्र निपटारा करने तथा कर्मचारियों को आवश्यक संसाधन और सुरक्षित कार्य वातावरण उपलब्ध कराने की मांग की। कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए निगम प्रबंधन और समिति के बीच नियमित संवाद की व्यवस्था करने का सुझाव भी दिया गया। समिति अध्यक्ष समर चौहान ने कहा कि परिवहन निगम को मजबूत बनाने के लिए कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है।

शिमला पुलिस ने नशे और साइबर अपराध पर कसा मजबूत शिकंजा

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। शिमला पुलिस की मासिक अपराध समीक्षा बैठक में नशे के अवैध कारोबार पर कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों से नशा तस्करी के मामलों में मुख्य आरोपितों तक पहुंचने, उनके नेटवर्क की जांच करने और अवैध संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई तेज करने को कहा गया। वित्तीय जांच और पिछड़ी कड़ियों की पड़ताल को भी प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए।

बैठक में महिलाओं से जुड़े अपराधों की संवेदनशील और समयबद्ध जांच पर जोर दिया गया। चोरी और सेंधमारी के मामलों में आरोपितों की गिरफ्तारी तथा सामान की बरामदगी जल्द सुनिश्चित करने को कहा गया।

पुलिस ने साइबर गश्त, सामाजिक माध्यमों पर निगरानी और रात्रि गश्त मजबूत करने का निर्णय लिया। नाकाबंदी और अन्य निवारक उपायों को प्रभावी बनाने पर भी चर्चा हुई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पुलिसकर्मियों को अनुशासन, टीम भावना और संवेदनशीलता के साथ जनता की सेवा करने के निर्देश दिए। शिमला पुलिस की मासिक अपराध समीक्षा बैठक में नशे के अवैध कारोबार पर सख्ती बढ़ाने और बड़े तस्करी नेटवर्क तक पहुंचने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों को नशा तस्करी के मामलों में मुख्य आरोपितों की गिरफ्तारी के साथ उनके नेटवर्क और वित्तीय स्रोतों की गहन जांच करने को कहा गया। अवैध संपत्ति को जब्त करने तथा जरूरत पड़ने पर निवारक कानून के तहत कार्रवाई करने पर भी जोर दिया गया।

बैठक में महिलाओं से जुड़े अपराधों की संवेदनशील और समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

सौहार्द जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्रीय भेदभाव से दूर रहकर सद्भाव बढ़ाने का किया आह्वान

सद्भावना दिवस पर शिमला प्रशासन ने दिलाई एकता की शपथ

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 82वीं जयंती के अवसर पर जिला प्रशासन शिमला की ओर से बचत भवन में सद्भावना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में अतिरिक्त उपायुक्त शिमला सचिन शर्मा ने अधिकारियों और कर्मचारियों को सद्भावना दिवस की शपथ दिलाई। इस दौरान उपस्थित सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने देश की एकता, अखंडता, आपसी भाईचारे और सामाजिक सौहार्द को मजबूत करने का संकल्प लिया।

अतिरिक्त उपायुक्त सचिन शर्मा ने कहा कि सद्भावना दिवस का मुख्य उद्देश्य समाज में शांति, प्रेम, सहिष्णुता और आपसी सहयोग की भावना को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि भारत विविधताओं वाला देश है, जहां अलग-अलग जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र से जुड़े लोग मिल-जुलकर रहते हैं। ऐसे में समाज में आपसी सम्मान और भाईचारे की भावना को मजबूत करना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है।

उन्होंने अधिकारियों एवं कर्मचारियों से जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव से दूर रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को अपने कार्य और व्यवहार के माध्यम से समाज में समानता, सद्भाव और सहयोग की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि आपसी विश्वास और सम्मान से ही समाज में स्थायी शांति कायम की जा सकती है।

सचिन शर्मा ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने आधुनिक तकनीक, शिक्षा, संचार और युवा शक्ति को राष्ट्र निर्माण से जोड़ने की दिशा में कई महत्वपूर्ण प्रयास किए। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी का आधुनिक भारत के निर्माण का दृष्टिकोण आज भी प्रासंगिक है। युवा वर्ग को देश के विकास और निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करना समय की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि देश की प्रगति केवल सरकारों के प्रयासों से संभव नहीं है, बल्कि समाज के प्रत्येक वर्ग की भागीदारी जरूरी है। नागरिकों को आपसी मतभेद भुलाकर देशहित को प्राथमिकता देनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों से अपील की कि वे अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा और निष्पक्षता से करें तथा समाज में सद्भावना और राष्ट्रीय एकता का संदेश पहुंचाएं।

कार्यक्रम के दौरान उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने सद्भावना, भाईचारे और राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करने का संकल्प लिया। सभी ने समाज में शांति और सौहार्द बनाए रखने तथा किसी भी प्रकार के भेदभाव से दूर रहने की प्रतिबद्धता दोहराई।

इस अवसर पर एडीएम प्रोटोकॉल ज्ञान सागर नेगी, एसडीएम शिमला ग्रामीण मंजीत शर्मा सहित जिला प्रशासन के विभिन्न अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी ने आपसी सहयोग, सामाजिक समरसता और देश की एकता एवं अखंडता को मजबूत करने की दिशा में निरंतर कार्य करने का संकल्प लिया।

रिटायर अफसरों पर मेहरबानी, बल्ह के विकास से सरकार ने मोड़ा मुंह

भारतेन्दु संवाददाता, मंडी। बल्ह विधायक इंद्र सिंह गांधी ने प्रदेश सरकार पर सेवानिवृत्त अधिकारियों को सलाहकार नियुक्त कर सरकारी सुविधाएं देने और बल्ह विधानसभा क्षेत्र के विकास की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार की कथनी और करनी में स्पष्ट अंतर दिखाई दे रहा है।

इंद्र सिंह गांधी ने कहा कि एक ओर मुख्यमंत्री भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के अधिकारियों की संख्या कम करने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर वर्षों पहले सेवानिवृत्त अधिकारियों को सलाहकार नियुक्त कर उन्हें कैबिनेट स्तर की सुविधाएं दी जा रही हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि सरकार मितव्ययिता की बात कर रही है तो फिर सेवानिवृत्त अधिकारियों पर सरकारी धन क्यों खर्च किया जा रहा है।

विधायक ने कहा कि बल्ह विधानसभा क्षेत्र के साथ लगातार अन्याय हो रहा है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में क्षेत्र में कोई नया बड़ा विकास कार्य शुरू नहीं हो पाया है। पिछली सरकार और उनके प्रयासों से शुरू की गई योजनाओं तथा परियोजनाओं को ही आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बल्ह की जनता को नई योजनाओं, सड़कों, स्वास्थ्य सुविधाओं और अन्य विकास परियोजनाओं की उम्मीद थी, लेकिन सरकार की उदासीनता के कारण विकास कार्यों की गति धीमी पड़ गई है।

उन्होंने कहा कि केवल बल्ह ही नहीं, बल्कि प्रदेश के कई अन्य क्षेत्रों में भी विकास कार्य प्रभावित हुए हैं। सरकार को राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के बजाय जनता की समस्याओं के समाधान और विकास कार्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए।

इंद्र सिंह गांधी ने सरकार से मांग की कि बल्ह क्षेत्र में लंबित विकास योजनाओं को शीघ्र पूरा किया जाए और नई परियोजनाओं के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध करवाया जाए। साथ ही उन्होंने सरकार से सेवानिवृत्त अधिकारियों की नियुक्तियों और उन्हें दी जा रही सुविधाओं को लेकर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की।

मंडी-कुल्लू हाईवे पर 2 ट्रकों की टक्कर; 4 की मौत, 6 लोग घायल

भगत सिंह गुलेरिया, भारतेन्दु संवाददाता, मंडी। टनल नंबर 12 के पास एक गंभीर सड़क दुर्घटना में दो ट्रकों की आपस में टक्कर हो गई। हादसे में चार लोगों की मौत हो गई, जबकि छह अन्य घायल हुए हैं। दुर्घटनाग्रस्त वाहनों में ट्रक नंबर पीबी11डीक्यू1249 और एचपी33सी1730 शामिल हैं।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ट्रक नंबर पीबी11डीक्यू1249 कुल्लू की ओर जा रहा था, जबकि एचपी33सी1730 कुल्लू से मंडी की ओर आ रहा था। इसी दौरान टनल नंबर 12 के पास दोनों ट्रकों की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य के साथ आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू की। चिकित्सा अधिकारियों ने दुर्घटना में चार लोगों को मृत घोषित किया। मृतकों की पहचान शकील (20) पुत्र करीम, निवासी जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश, विशाल (21) पुत्र राजेंद्र सिंह, निवासी फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश, मेघनाथ शर्मा (30) पुत्र दुखी शर्मा, निवासी पश्चिम चंपारण, बिहार, तथा रवि कुमार (22) पुत्र श्धऊजी राम,

निवासी फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है।

दुर्घटना में घायल छह लोगों में से चार का उपचार क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में चल रहा है। इनमें दीपक (26), ऐजात (18), दीपक (20) और सहजाद (20) शामिल हैं। वहीं भागीरथ, निवासी बल्ह, मंडी तथा मुकेश कुमार (40), निवासी बल्ह, मंडी का उपचार मेडिकल कॉलेज नेरचौक में किया जा रहा है। पुलिस ने इस मामले में थाना औट में भारतीय न्याय संहिता की धारा 281, 126(ए) तथा 106(1) के तहत अभियोग पंजीकृत किया है। पुलिस द्वारा दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है तथा मामले में आगामी अन्वेषण जारी है।

प्रदेश में 23 से धीमा पड़ेगा मानसून

अगले दो दिन भारी बारिश के आसार, मंडी में सबसे ज्यादा 62 सड़कें अवरुद्ध

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश में लगातार सक्रिय मॉनसून के बीच अब लोगों को भारी बारिश से कुछ राहत मिलने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार अगले दो दिन प्रदेश में मॉनसून सक्रिय रहेगा और कई क्षेत्रों में भारी बारिश हो सकती है। इसके बाद 23 अगस्त से मानसून की रफ्तार धीमी पड़ने की संभावना है।

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 23 से 26 अगस्त तक प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश जारी रह सकती है, हालांकि इस अवधि के लिए किसी तरह का अलर्ट जारी नहीं किया गया है। इससे संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले दिनों में बारिश का असर पहले की तुलना में कम रहेगा। वीरवार सुबह राजधानी शिमला में कुछ समय के लिए धूप खिली। प्रदेश के कई अन्य हिस्सों में भी कहीं धूप तो कहीं बादल छाए रहे। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। सोलन जिले के नालागढ़ में सबसे अधिक 50 मिलीमीटर बारिश हुई। इसके अलावा

बिलासपुर के ब्रह्माणी में 49 मिलीमीटर, नैनादेवी में 36 मिलीमीटर, मररान में 25 मिलीमीटर और मंडी जिले के सलापड़ में 21 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई।

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार अगस्त महीने में अब तक प्रदेश में सामान्य से 8 फीसदी कम बारिश हुई है। इस दौरान बिलासपुर, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला और सिरमौर जिलों में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई है। वहीं चंबा, हमीरपुर, किन्नौर, लाहौल-स्पीति, सोलन और ऊना जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई है। सिरमौर जिले में सामान्य से 31 फीसदी अधिक बारिश दर्ज की गई है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार वीरवार सुबह तक प्रदेश में भूस्खलन के कारण एक नेशनल हाईवे और 145 सड़कें अवरुद्ध हैं। इसके अलावा 115 बिजली ट्रांसफार्मर और 117 पेयजल परियोजनाएं भी प्रभावित हैं। मंडी जिले में एनएच-003 मंडी-कोटली नेशनल हाईवे धर्मपुर क्षेत्र में रोपड़ू के पास बंद है। सड़क बंद होने की सबसे ज्यादा समस्या मंडी जिले में बनी हुई है। यहां 62 सड़कें अवरुद्ध हैं। कुल्लू में 35 और चंबा में 19 सड़कें बंद हैं। बिजली आपूर्ति पर भी बारिश का असर पड़ा है। हमीरपुर जिले में 42, लाहौल-स्पीति में 41 और सिरमौर जिले के पांवटा साहिब क्षेत्र में 29 बिजली ट्रांसफार्मर बंद हैं। हमीरपुर जिले में 107 पेयजल योजनाएं प्रभावित हुई हैं।

मानसून से हिमाचल में हो चुकीं 205 मौतें

प्रदेश में इस मानसून सीजन के दौरान 30 जून से अब तक बारिश से जुड़े हादसों में 205 लोगों की मौत हो चुकी है। इस अवधि में 318 लोग घायल हुए हैं, जबकि तीन लोग अभी भी लापता हैं। बारिश और भूस्खलन से 85 मकान, 14 दुकानें और 296 पशुशालाएं पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुई हैं। इसके अलावा 325 मकानों को आंशिक नुकसान पहुंचा है। मानसून सीजन में अब तक प्रदेश को 1085 करोड़ रुपये की संपत्ति का नुकसान हो चुका है। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान जल शक्ति विभाग को हुआ है। विभाग को करीब 802 करोड़ रुपये का नुकसान आंका गया है।

सीएम सुक्खू ने पूर्व पीएम राजीव गांधी को अर्पित की पुष्पांजलि

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने छोटा शिमला स्थित सद्भावना चौक में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने प्रदेशवासियों से राजीव गांधी के दिखाए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजीव गांधी को 'आधुनिक भारत के निर्माता' के रूप में याद किया जाता है।

उन्होंने राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति राजीव गांधी की दूरदर्शी सोच का परिणाम है, जिसका लाभ आज की युवा पीढ़ी व्यापक रूप से उठा रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उपस्थित लोगों को सद्भावना की शपथ भी दिलाई। इसके पश्चात, मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश सचिवालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता एवं सांप्रदायिक सौहार्द की शपथ दिलाई। इस अवसर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी, उप-मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया, विधायक संजय अवस्थी, सुरेश कुमार एवं हरीश जनारथा, नगर निगम शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान, केहर सिंह खाची, देवेंद्र श्याम, बलदेव ठाकुर, विदित चौधरी, महासचिव विनोद जिंटा एवं अन्य गणमान्य उपस्थित थे।

न्यूज ब्रीफ

कांगड़ा मंदिर में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने टेका माथा

भारतेन्दु संवाददाता, कांगड़ा। बज्रेश्वरी मंदिर कांगड़ा में श्रावण अष्टमी के दिन 3800 श्रद्धालुओं ने माथा टेका। मंदिर में आए हुए यात्रियों ने नाचने गाने का खूब आनंद लिया मां के गानों से मंदिर गूंजता रहा। मंदिर अधिकारी प्रकाश चंद ने बताया सातवें मेले के दिन श्रद्धालुओं द्वारा 1,59,095 रुपए का चढ़ावा चढ़ाया गया।

ठारू में श्रद्धा, सेवा और प्रसाद का संगम

भारतेन्दु संवाददाता, नगरोटा बगवां। श्रावण अष्टमी के पावन अवसर पर 'जय जलविम्बी महादेव' त्रिण्ड (नगरोटा बगवां) के नौजवानों ने वीरवार को ठारू में विशाल भंडारे का आयोजन किया। सुबह से शुरू हुआ भंडारा शाम तक जारी रहा। इस दौरान बाहरी राज्यों से पहुंचे श्रद्धालुओं सहित स्थानीय लोगों ने भी प्रसाद ग्रहण कर पुण्य लाभ कमाया। भोलेनाथ की भक्ति, सेवा और श्रद्धा से सराबोर इस आयोजन ने पूरे क्षेत्र को भक्तिमय बना दिया।

पुराना कांगड़ा में 60 लोगों का जांचा स्वास्थ्य

भारतेन्दु संवाददाता, कांगड़ा। आंगनबाड़ी केंद्र, वार्ड नंबर 3, पुराना कांगड़ा में आयुष विभाग की ओर से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का आयोजन उपमंडल आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डॉ. बबिता गौतम के मार्गदर्शन में किया गया, जिसमें कुल 60 लाभार्थियों ने स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। शिविर के दौरान विशेषज्ञों ने मर्म चिकित्सा, स्नेहन-स्वेदन, कपिंग थेरेपी और एक्यूप्रेशर जैसी विभिन्न आयुष उपचार पद्धतियों के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया। इसके साथ ही प्रतिभागियों को नियमित योगाभ्यास, संतुलित आहार और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के संबंध में भी जागरूक किया गया। डॉ. प्रियंका और डॉ. सोनाली ने शिविर में पहुंचे लाभार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया तथा उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के अनुसार आवश्यक चिकित्सकीय परामर्श एवं उचित मार्गदर्शन प्रदान किया। चिकित्सकों ने लोगों को बीमारी से बचाव के साथ-साथ दैनिक जीवन में स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने के लिए प्रेरित किया। शिविर का मुख्य उद्देश्य आमजन को आयुष चिकित्सा पद्धतियों के प्रति जागरूक करना और स्वस्थ एवं संतुलित जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करना रहा। स्थानीय लोगों ने आयुष विभाग की इस पहल की सराहना की।

विद्यार्थियों को नशे से दूर रहकर साथियों को भी करना चाहिए जागरूक : एसपी

अमर सिंह ठाकुर, भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोठीपुरा में वीरवार को पुलिस अधीक्षक बिलासपुर अभिषेक द्वारा विद्यार्थियों के लिए जागरूकता सत्र आयोजित किया गया। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों तथा नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे पुलिस अभियान के बारे में जानकारी दी और नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित किया।

उन्होंने विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई, करियर एवं व्यक्तित्व विकास पर ध्यान केंद्रित कर देश और समाज के लिए सकारात्मक योगदान देने का संदेश दिया। साथ ही नागरिक बोध के महत्व पर जोर देते हुए स्वच्छता बनाए रखने, कूड़ा न फैलाने तथा यातायात सहित सभी नियमों का स्वयं पालन करने के लिए प्रेरित किया। अंत में उन्होंने विद्यार्थियों से एक अच्छा इंसान बनने, दूसरों के प्रति दयालु, सहायक एवं सम्मानजनक व्यवहार करने तथा समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने का आह्वान किया।

एमसीएम डीएवी कॉलेज कांगड़ा में एमए अंग्रेजी चौथे सेमेस्टर का परिणाम सराहनीय

अंशिका व ईशा चौधरी ने झटका पहला स्थान

आशीष दमीर, भारतेन्दु संवाददाता, कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा घोषित एमए अंग्रेजी चौथे सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम में एमसीएम डीएवी कॉलेज कांगड़ा की छात्राओं ने अच्छा प्रदर्शन किया है। कॉलेज स्तर पर तैयार की गई मेरिट सूची में छात्राओं ने बेहतर स्थान प्राप्त करते हुए अपनी शैक्षणिक उपलब्धि दर्ज करवाई।

कॉलेज की मेरिट सूची में अंशिका और ईशा चौधरी ने 7.48 सीजीपीए के साथ संयुक्त रूप से प्रथम स्थान हासिल किया। शिवानी ने 7.43 सीजीपीए के साथ द्वितीय स्थान प्राप्त किया, जबकि रितांक्षा 7.41 के साथ तृतीय स्थान पर रहीं। छात्राओं के इस प्रदर्शन से महाविद्यालय में प्रसन्नता का माहौल है। एमए अंग्रेजी चौथे सेमेस्टर के परिणाम में प्राप्त यह उपलब्धि छात्राओं की नियमित मेहनत, विषय के प्रति रुचि और परीक्षा की बेहतर तैयारी को दर्शाती है। कॉलेज स्तर पर मेरिट सूची में स्थान हासिल करने वाली इन छात्राओं ने अपनी कक्षा में अच्छा प्रदर्शन करते हुए अन्य विद्यार्थियों के लिए भी प्रेरणा प्रस्तुत की है।

छात्राओं की इस उपलब्धि पर एमसीएम डीएवी कॉलेज कांगड़ा के प्राचार्य डॉ. बलजीत सिंह पटियाल ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए अंशिका, ईशा चौधरी, शिवानी और रितांक्षा को बधाई दी। उन्होंने कहा कि परीक्षा परिणाम विद्यार्थियों की मेहनत का महत्वपूर्ण प्रतिबिंब होता है। उन्होंने छात्राओं को भविष्य में भी इसी लगन और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।

प्राचार्य ने कहा कि महाविद्यालय में विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के साथ-साथ उन्हें अपनी शैक्षणिक क्षमता को बेहतर बनाने के लिए उचित मार्गदर्शन दिया जाता है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की सफलता में उनके परिश्रम के साथ-साथ शिक्षकों के मार्गदर्शन और अभिभावकों के सहयोग की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है।

डॉ. पटियाल ने अंग्रेजी विभाग के प्राध्यापकों को भी छात्राओं के अच्छे प्रदर्शन के लिए बधाई देते हुए कहा कि विद्यार्थियों को विषय की गहन समझ विकसित करने तथा बेहतर परिणाम हासिल करने के लिए विभाग द्वारा निरंतर मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।

उन्होंने कहा कि महाविद्यालय का उद्देश्य विद्यार्थियों को केवल परीक्षा तक सीमित शिक्षा देना नहीं, बल्कि उन्हें उच्च शिक्षा और भविष्य की चुनौतियों के लिए सक्षम बनाना है। ऐसे परिणाम विद्यार्थियों में आत्मविश्वास बढ़ाने के साथ-साथ उन्हें आगे और बेहतर करने के लिए प्रेरित करते हैं।

रानीताल में जल्द लगेगा सोलर प्लांट : मोंगरा

कहा-25 कनाल भूमि पर हिम ऊर्जा के तहत किया जाएगा निर्माण

भारतेन्दु संवाददाता, कांगड़ा। प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू का सपना हिमाचल को ग्रीन हिमाचल व क्लीन हिमाचल बनाना है। जिसके तर्ज पर प्रदेश में हिम ऊर्जा के तहत सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं।

वहीं कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र के रानीताल में सरकार द्वारा हिम ऊर्जा के तहत सोलर प्लांट लगाया जाएगा, जोकि 25 कनाल की भूमि पर बनेगा। यह बात विशेष बातचीत के दौरान एपीएमसी के जिला व प्रदेश कांग्रेस ओबीसी विभाग के अध्यक्ष चौधरी नरेंद्र निशु मोंगरा ने कही। उन्होंने कहा कि चयनित भूमि का आज जायजा लिया। इस दौरान एसडीएम कांगड़ा डॉक्टर अंजली गर्ग, नायब तहसीलदार रमन कायस्था सहित स्थानीय पंचायत प्रतिनिधि व लोग भी मौजूद रहे। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा इस प्लांट के लगने से पंचायत को इनकम होगी 50% इनकम सरकार को जाएगी वहीं 50% इनकम पंचायत को जिसमें पंचायत 25% विकास कार्यों पर खर्च कर सकती हैं वही 25% जरूरतमंद लोगों की सेवा में दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पिछले कल आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा ने कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र के लिए 64 लाख रुपए की आयुष डिस्पेंसरी की सौगात दी है जिसके लिए वह आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा का धन्यवाद व आभार व्यक्त करते हैं।

उन्होंने कहा है कि कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र के 16 चिन्हित खेल मैदाने के सौंदर्य करने के लिए भी आयुष मंत्री को फाइल सौंपी गई है और जल्द ही मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से यह सभी योजनाएं शुरू कर दी जाएगी। कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र तरक्की की ओर आगे बढ़ रहा है।

मंडी में एबीवीपी-पुलिस में तीखी झड़प

प्रदर्शन के दौरान छात्रा हुई बेहोश, छात्रों ने धक्का-मुक्की के लगाए आरोप

भारतेंदु संवाददाता, मंडी। अखिर एबीवीपी ने पुलिस के साथ तीखी झड़प व छीना झपटी होने के बावजूद सेरी मंच के सामने सड़क पर प्रदेश सरकार का पुतला दहन कर ही दिया। एबीवीपी द्वारा प्रदेश स्तरीय मांगों के समर्थन में चलाए जा रहे आंदोलन के तहत आज उपायुक्त कार्यालय के नजदीक धरना प्रदर्शन चल रहा था। जिला पुस्तकालय के बाहर सड़क पर जमकर नारेबाजी चल रही थी। इस दौरान पुलिस बल जो कुछ ज्यादा ही संख्या में तैनात था, द्वारा छात्रों की गतिविधियों पर पैनी निगाह थी। तभी थोड़ी दूरी से पुतला लाया जाने लगा

तो पुलिस ने छीना झपटी करते हुए बल प्रयोग किया। एक बिना वर्दी में कथित सुरक्षा कर्मी ने छात्र को दांतों व घुंसो से पीटा। इस दौरान कुछ छात्र छात्राओं को खरौंचे भी आई। थोड़ी देर पुलिस व छात्रों में ठीक गुत्थमगुत्थी हुई। एक छात्रा बेहोश हो गई।उसे अस्पताल ले जाया गया जो शाम तक स्वस्थ हो गई। पुलिस दो छात्रों को भी भी गाड़ी में डाल कर ले जाने लगी तो विद्यार्थी जीप से ही भिड़ गए। इस दौरान कुछ अनहोनी भी हो सकती थी। छात्राओं ने पुरुष पुलिस द्वारा धक्का-मुक्की के आरोप लगाए हैं।

सदन में जनहित से जुड़े मुद्दों के लिए दिया जाएगा पर्याप्त समय

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने सर्वदलीय बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि मानसून सत्र को निर्विघ्न और सुचारू रूप से चलाने के उद्देश्य से बैठक बुलाई गई थी। बैठक में संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानियां मौजूद रहे। 10 दिनों तक चलने वाले सत्र के दौरान उठाए जाने वाले विषयों की जानकारी भी साझा की गई। पठानिया ने कहा कि सदन में जनहित से जुड़े मुद्दों पर सार्थक चर्चा के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। उन्होंने सत्तापक्ष और विपक्ष से नियमों की मर्यादा में रहकर सदन की गरिमा बनाए रखने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि 14वीं विधानसभा की उत्पादकता अब तक 90 से 132 प्रतिशत तक रही है, जो देश में सर्वाधिक है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सभी सदस्यों के सहयोग से यह परंपरा आगे भी कायम रहेगी।

उत्तर रेलवे

ई-निविदा सूचना

क्र. सं.	निविदा संख्या	कार्य का विवरण	निविदा खुलने की तिथि / समय	अनुमानित लागत (₹)	धरोहर राशि (₹)	कार्य पूरा करने की अवधि
1.	OT-25/ 2026-27	एनुअल रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डेल्ट्रॉन मेक यूनिवर्सल फेल-सेफ ब्लॉक इंटरफेस (यूएफएसबीआई) ब्लॉक पैनल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ 72 ब्लॉक सेक्शनंस ओवर अंबाला डिवीजन फॉर अ पीरियड ऑफ टू इयर्स।	14.09.2026 at 15:00 hrs.	₹1,21,54,392.91	₹2,43,100/-	24 महीने
2.	OT-26/ 2026-27	(1) एस्टिमेट फॉर यूटिलिटी शिफ्टिंग ऑफ एस एंड टी एसेट्स इन कनेक्शन विद प्लेटफॉर्म रेजिंग ऑफ सरहिंद जंक्शन स्टेशन अंडर गति शक्ति अंबाला। (2) एस्टिमेट फॉर यूटिलिटी शिफ्टिंग ऑफ एस एंड टी एसेट्स इन कनेक्शन विद प्लेटफॉर्म रेजिंग ऑफ अबोहर स्टेशन अंडर गति शक्ति अंबाला। (3) एस्टिमेट फॉर यूटिलिटी शिफ्टिंग ऑफ एस एंड टी एसेट्स इन कनेक्शन विद प्लेटफॉर्म रेजिंग ऑफ नंगल डैम स्टेशन अंडर गति शक्ति अंबाला। (4) एस्टिमेट फॉर यूटिलिटी शिफ्टिंग ऑफ एस एंड टी एसेट्स इन कनेक्शन विद प्लेटफॉर्म रेजिंग ऑफ संगरूर स्टेशन अंडर गति शक्ति अंबाला।	14.09.2026 at 15:00 hrs.	₹59,36,922.85	₹1,18,700/-	180 दिन
3.	OT-27/ 2026-27	(i) प्रोविजन ऑफ एसएसडीएसी इन एडिशन टू एग्जिस्टिंग ट्रैक सर्किट ऑफ साइडिंग फॉर इम्प्रूविंग रिलायबिलिटी ऑफ ट्रैक सर्किट इन वाटर लॉगिंग एरिया ओवर अंबाला डिवीजन। (ii) स्ट्रेंथनिंग ऑफ ब्रिज नं. 313-ए (8x8 आरसीसी बॉक्स) किलोमीटर 275/4-6 एंड 314-ए (8x8 आरसीसी बॉक्स) किलोमीटर 275/16-18 बाय प्रोविजन ऑफ स्टैंडर्ड विंग एंड रिटर्न वॉल्स विथ अदर्स प्रोटेक्शन एंड एनसिलरी वर्क्स ऑन यूएमबी-एलडीएच सेक्शन।	14.09.2026 at 15:00 hrs.	₹1,14,04,611.32	₹2,28,100/-	270 दिन
4.	OT-28/ 2026-27	सिगनलिंग वर्क इन कनेक्शन विद (i) प्रोविजन ऑफ इलेक्ट्रिक लिफ्टिंग बेरीअर (ई०एल०बी०)इन ल्यू ऑफ लेफ्ट ओवर मैकेनिकल लिफ्टिंग बेरीअर(एम०एल०बी०) एण्ड प्रोविजन ऑफ रोड सिग्नलस ऑन इंटरइंटरलॉकड लेवल क्रॉसिंग गेट्स ओवर अंबाला डिवीजन (ii) प्रोविजिन ऑफ आई०पी०एस० ऑन लेफ्टओवर इन्टरलॉक्ड लेवल क्रॉसिंग गेट्स ओवर अंबाला डिवीजन।	14.09.2026 at 15:00 hrs.	₹2,65,68,133.09	₹5,31,400/-	270 दिन
5.	OT-29/ 2026-27	प्रोविजन ऑफ फुल लेंथ शंटिंग नेक बाय एक्सटेंशन ऑफ लाइन नं. 1 टुवर्ड्स नंगल डैम एंड एट कीरतपुर साहिब (KART) स्टेशन।	14.09.2026 at 15:00 hrs.	₹65,37,366.93	₹1,30,800/-	180 दिन
6.	OT-30/ 2026-27	एस&टी वर्क इन कनेक्शन विद 1). कन्स्ट्रक्शन ऑफ 2 लेन आर ओ बी इन ल्यू ऑफ एल् सी -06 एट किमी० 12/2-3 ऑन जाखल - हिसार सेक्शन नीयर जमालपुर शेखा. 2). प्रोविजन ऑफ वन हुक प्लेसमेन्ट ऑफ हाफ गुड्ज रैक एट गुड्ज साइडिंग एट बस्सी पठाना (बीएसपीएन) स्टेशन ऑफ अंबाला डिवीजन. 3) कन्स्ट्रक्शन ऑफ 2 नंबर एल एच एस (5mx5m) बाइ पुशिन्ग इन ल्यू ऑफ सी-18 एट किमी० 29/1-2 & एल् सी - 59 एट किमी० 77/15-78/0 ऑन जाखल हिसार सेक्शन. 4). रिप्लेसमेंट ऑफ गर्डर विद पी०एस०सी० स्लैब & स्ट्रेंथनिंग ऑफ सबस्ट्रक्चर ऑफ ब्रिज सं. 190, 197ए-1, 220ए, 232 धुरी- जाखल ब्रिज सं. 49 जाखल-हिसार, 30, 82, 135 लुधियाना -धुरी ब्रिज सं 60-ए, 100 राजपुरा-धुरी 221, 292 धुरी-भटिंडा-143 भटिंडा-श्रीगंगानगर सेक्शन. 5). प्रोविजन ऑफ 3मी० एफ०ओ०बी० एट बरवाला (बी एक्स सी).	14.09.2026 at 15:00 hrs.	₹52,33,706.01	₹1,04,700/-	180 दिन
7.	OT-31/ 2026-27	एस&टी वर्क इन कनेक्शन विद 1) प्रोविजन ऑफ बॉन्डरी वाल एट सी०आर०ओ० लोकेशनस बिटविन कुराली-मियानपुर स्टेशनस 2) प्रोविजन ऑफ बॉन्डरी वॉल एट सी०आर०ओ० लोकेशनस बिटविन घनौली-भरतगढ़ स्टेशनस 3)। प्रोविजन ऑफ बॉन्डरी वॉल एट सी०आर०ओ० लोकेशनस बिटविन रूपनगर - घनौली स्टेशनस सरहिन्द -दौलतपुर चौक सेक्शनस. 4) प्रोविजन ऑफ बॉन्डरी वॉल एट लोकेशनस प्रोन टू इंक्रोचमेंट इन द अप्रोच ऑफ नगल डेम एण्ड कीरतपुर यार्ड. 5) प्रोविजन ऑफ बॉउन्ड्री वाल अलॉग दा ट्रैक फॉर सेफ रनिंग ऑफ ट्रेनस ऑन वल्नरेबल सी आर ओ लोकेशनस नियर अबोहर जंक्शन।	14.09.2026 at 15:00 hrs.	₹51,66,949.80	₹1,03,300/-	180 दिन

1. वरि० मंडल सिग० एवं टेली० इंजी०/उ०रे० डी०आर०एम० ऑफिस, रेल विहार, अम्बाला छावनी के द्वारा इच्छुक निविदाकारों से उपरोक्त संदर्भित कार्यों हेतु खुली निविदा दर्शायी गयी तिथि अनुसार 15:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। निविदाकारों के द्वारा सभी आवश्यक दस्तावेज की स्कैन प्रतिलिपि अपलोड करें। 2. टेंडर डाकूमैंटस व निविदा सूचना की विस्तृत जानकारी के लिए रेलवे वेबसाइट **www.ireps.gov.in** पर लॉग ऑन करें। 3. निविदाकारों को ई-टेंडरिंग में भाग लेने के लिए उनके पास क्लास-III डिजीटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होना चाहिए तथा उन्हें उपरोक्त साइट पर रजिस्टर्ड होना आवश्यक है। निविदाकारों से निवेदन है कि टेंडर नोटिस और टेंडर डाकूमेंट्स में दी गई हिदायतों/शर्तों इत्यादि को टेंडर डालने से पहले भली भांति पढ़ लें।

संख्याः एस.डब्ल्यू./सिग/अंबाला/एनआईटी०-08-2026-27 दिनांकः 19.08.2026 2895/2026

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

रफ्तार 75 करोड़ का 132 केवी उपकेंद्र, 45 नए ट्रांसफॉर्मर और 74 करोड़ की सिंचाई परियोजना पर फोकस

घुमारवीं के विकास को मिलेगी नई गति: धर्माणी

अमर सिंह ठाकुर, भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। नगर एवं ग्राम नियोजन, आवास, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र में विद्युत, पेयजल, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण तथा सड़क अवसंरचना को मजबूत करने के लिए व्यापक स्तर पर विकास कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत कर लोगों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध करवाना है। धर्माणी ग्राम पंचायत कोटलू ब्राह्मणा में नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों के लिए आयोजित अभिनंदन समारोह में बतौर मुख्यातिथि संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र में बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए नए 33 केवी उपकेंद्र स्वीकृत किए गए हैं। इन्हें बड़े विद्युत ग्रिड से जोड़ने की प्रक्रिया जारी है। वर्तमान में घुमारवीं क्षेत्र को 132 केवी कांगू उपकेंद्र से विद्युत आपूर्ति मिल रही है। पुरानी विद्युत लाइनों के कारण तकनीकी हानियां बढ़ रही हैं

और ओवरलोड की स्थिति में बार-बार शटडाउन की समस्या सामने आती है। इसके समाधान के लिए करीब 5 करोड़ रुपये की लागत से कांगू-कंदरौर विद्युत लाइन की रिकंडक्टिंग का कार्य किया जा रहा है।

धर्माणी ने बताया कि घुमारवीं क्षेत्र के करयालग में लगभग 75 करोड़ रुपये की लागत से नया 132 केवी विद्युत उपकेंद्र स्थापित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जाहू, बड़सर, कोटलागड़ तथा एम्स के समीप विकसित हो रहे विद्युत उपकेंद्रों को भी क्षेत्र के नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। इससे किसी एक स्थान पर तकनीकी खराबी आने की स्थिति में दूसरे स्रोत से बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी। उन्होंने बताया कि घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के लिए 45 नए विद्युत ट्रांसफॉर्मर स्वीकृत किए गए हैं, जिन्हें मानसून के बाद चरणबद्ध तरीके से आगामी एक वर्ष में स्थापित किया जाएगा। इससे आने वाले वर्षों में विद्युत व्यवस्था और मजबूत होगी।

उन्होंने कहा कि क्षेत्र की पेयजल व्यवस्था को भी दीर्घकालिक दृष्टि से सुदृढ़ किया जा रहा है। सतलुज नदी पर आधारित तीन बड़ी पेयजल योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। इनके माध्यम से भराड़ी, कपाहड़ा तथा घुमारवीं के आसपास के क्षेत्रों की पेयजल समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत करीब 74 करोड़ रुपये की परियोजना केंद्र सरकार को भेजी गई है। पूरे विधानसभा क्षेत्र को सिंचाई सुविधा से जोड़ने के लिए 600 से 700 करोड़ रुपये की व्यापक परियोजना केंद्रीय जल आयोग के समक्ष भी प्रस्तुत की गई है।

सड़क विकास का उल्लेख करते हुए धर्माणी ने कहा कि निहारी-बरठीं सड़क सहित कई महत्वपूर्ण सड़क उन्नयन परियोजनाओं पर कार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार गुणवत्ता और पारदर्शिता के साथ विकास कार्यों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने घुमारवीं क्षेत्र में 111 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं के उद्घाटन तथा 488 करोड़ रुपये की परियोजनाओं के शिलान्यास के लिए मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से क्षेत्र में विकास को नई गति मिलेगी और लोगों को बेहतर सुविधाएं प्राप्त होंगी। समारोह में ग्राम पंचायत कोटलू ब्राह्मणा के प्रधान रोशन लाल जम्वाल, उपप्रधान विशाल जम्वाल, बीडीसी सदस्य मंजुला देवी सहित कई लोग उपस्थित रहे।

चरणबद्ध तरीके से सीवरेज सुविधाओं का होगा विस्तार

मंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से सीवरेज सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। इसके लिए दो परियोजनाएं नाबार्ड के माध्यम से भेजी गई हैं। बाढ़ नियंत्रण के लिए सीर खड्ड की करीब 198 करोड़ रुपये की परियोजना केंद्र सरकार के पास विचाराधीन है, जबकि सुकर खड्ड के चैनलाइजेशन का प्रस्ताव भी भेजा गया है। तत्काल खतरे वाले स्थानों पर प्राथमिकता के आधार पर सुरक्षात्मक कार्य किए जाएंगे।

रजिस्ट्री घोटाले में 141 लोगों पर कार्रवाई की तैयारी, तहसीलों में मचा हड़कंप

कृषि भूमि दिखाकर महंगी संपत्तियों की रजिस्ट्री, स्टांप ड्यूटी चोरी के आरोपों के मामले जांच के घेरे में

भारतेन्दु संवाददाता, लुधियाना

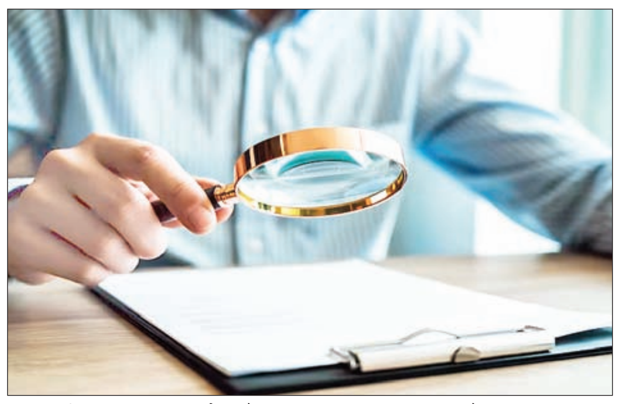

महानगर की विभिन्न तहसीलों और उप-तहसीलों में सामने आए कथित रजिस्ट्री घोटाले को लेकर प्रशासनिक और कानूनी हलकों में हलचल तेज हो गई है। कमर्शियल इमारतों, शोरूमों और महंगी शहरी संपत्तियों को दस्तावेजों में कृषि भूमि दर्शाकर स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क में कथित तौर पर बड़े पैमाने पर गड़बड़ी किए जाने के मामले में 141 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू होने की जानकारी सामने आई है। कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ने की खबर के बाद तहसीलों में सक्रिय संपत्ति एजेंटों, वसीका नवीसों और संबंधित अधिकारियों में भी बेचैनी का माहौल बताया जा रहा है।

जांच में सामने आए तथ्यों के अनुसार, शहर की कई प्रमुख और महंगी जगहों पर स्थित संपत्तियों की रजिस्ट्री के दौरान उनकी वास्तविक प्रकृति के बजाय दस्तावेजों में उन्हें कृषि योग्य भूमि के रूप में दर्शाया गया। इससे संपत्तियों पर लागू होने वाली स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क कम हो गया। आरोप है कि इस तरीके से सरकारी राजस्व को भारी नुकसान पहुंचाया गया। 141 मामलों में अनियमितताओं के सामने आने के बाद अब यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या यह गड़बड़ी केवल संपत्ति खरीदने और बेचने वालों तक सीमित थी या फिर इसमें तहसील स्तर पर काम करने वाले एजेंटों, दस्तावेज तैयार करने वालों और अधिकारियों की भी भूमिका थी। जांच आगे बढ़ने के साथ इस पूरे नेटवर्क की कार्यप्रणाली सामने आने की संभावना जताई जा रही है।

हाईकोर्ट के निर्देश पर जांच: जानकारी के अनुसार, पूरे मामले की जांच पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुरूप की जा रही है। जांच एजेंसियां संबंधित रजिस्ट्रियों के दस्तावेजों और संपत्तियों से जुड़े रिकॉर्ड की जांच कर रही हैं। जिन मामलों में स्टांप ड्यूटी कम जमा होने की पुष्टि होगी, वहां संबंधित पक्षों से सरकारी राजस्व की वसूली की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

अधिकारियों के स्तर पर यह भी देखा जा रहा है कि रजिस्ट्री के समय संपत्ति की वास्तविक स्थिति क्या थी और दस्तावेजों में उसे किस श्रेणी में दर्ज किया गया। इसके अलावा उस समय लागू कलेक्टर रेट तथा संपत्ति के वास्तविक बाजार मूल्य से जुड़े पहलुओं की भी जांच की जा सकती है।

पुराने रिकॉर्ड भी जांच के दायरे में : मामले की गंभीरता को देखते हुए पुराने रजिस्ट्री रिकॉर्ड खंगाले जाने की संभावना बढ़ गई है। प्रशासनिक स्तर पर संबंधित तहसीलों और उप-तहसीलों में पूर्व में हुई रजिस्ट्रियों की जांच का दायरा बढ़ाया जा सकता है। संपत्तियों की मौके पर स्थिति, पुराने राजस्व रिकॉर्ड और रजिस्ट्री दस्तावेजों का मिलान किए जाने की बात सामने आ रही है।

यदि जांच में और अनियमितताएं सामने आती हैं तो कार्रवाई का दायरा 141 मामलों से आगे भी बढ़ सकता है। ऐसे में उन एजेंटों, वसीका नवीसों और तत्कालीन अधिकारियों की भूमिका भी जांच के घेरे में आ सकती है, जिनके कार्यकाल के दौरान संबंधित रजिस्ट्रियां हुई थीं।

राजस्व की होगी वसूली : जिन मामलों में कम स्टांप ड्यूटी जमा होने की पुष्टि होगी, उनमें बकाया राशि की वसूली के साथ जुर्माना और ब्याज भी लगाया जा सकता है।

सीवर सफाई बनी जानलेवा, पंजाब में साढ़े पांच साल में 12 सफाईकर्मियों की मौत

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

पंजाब में सीवर और सेप्टिक टैंक की खतरनाक सफाई के दौरान पिछले साढ़े पांच वर्षों में 12 सफाईकर्मियों की मौत हुई है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने लोकसभा में यह जानकारी दी। हालांकि, केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि इन मौतों को सीधे तौर पर मैनुअल स्कैवेंजिंग के कारण हुई मौत नहीं माना गया है।

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, एक जनवरी 2021 से 30 जून 2026 के बीच देशभर में सीवर और सेप्टिक टैंक की खतरनाक सफाई के दौरान 332 सफाईकर्मियों की जान गई। महाराष्ट्र में सबसे अधिक 58 मौतें दर्ज की गईं। इसके बाद हरियाणा में 47, तमिलनाडु में 38, उत्तर प्रदेश में 37, दिल्ली में 29, गुजरात में 27 और राजस्थान में 23 मौतें हुईं। पंजाब में 12 मौतें दर्ज की गई हैं।

पंजाब में 231 मैनुअल सफाईकर्मी चिन्हित : मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2013 और 2018 में हुए दो सर्वेक्षणों में देशभर में 58,098 मैनुअल सफाईकर्मी चिन्हित किए गए थे। इनमें पंजाब के 231 लोग शामिल थे। वर्ष 2024-25 में देश के सभी जिलों में नया सर्वेक्षण कराया गया, जिसमें सरकार के अनुसार कोई मैनुअल सफाईकर्मी नहीं मिला।

मैनुअल सफाईकर्मियों और उनके आश्रितों को वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार कौशल विकास प्रशिक्षण और पूंजीगत सब्सिडी जैसी योजनाएं चला रही है। हालांकि पंजाब में वर्ष 2021-22 से 2025-26 के दौरान किसी भी मैनुअल सफाईकर्मी को कौशल विकास प्रशिक्षण नहीं मिला। इस अवधि में केवल पांच लोगों को पूंजीगत सब्सिडी दी गई।

सुरक्षा नियमों का पालन जरूरी : केंद्र ने बताया कि सीवर और सेप्टिक टैंक की खतरनाक सफाई के दौरान होने वाली मौतों को रोकने के लिए सुरक्षा नियमों का पालन अनिवार्य है। बिना आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था के सीवर या सेप्टिक टैंक की सफाई कराना प्रतिबंधित है।

न्यूज ब्रीफ

विदेशी नंबरों से कारोबारी परिवार को धमकी रंगदारी नहीं दी तो अपहरण की दी चेतावनी

भारतेन्दु संवाददाता, लुधियाना। महानगर में विदेशी नंबरों से कॉल कर कारोबारियों और उनके परिवारों को धमकाने का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता प्रदीप सिंगला ने पुलिस को बताया कि उसे, उसके चार भाइयों और परिवार के अन्य सदस्यों को लगातार अलग-अलग विदेशी नंबरों से व्हाट्सऐप कॉल और वॉयस मैसेज मिल रहे थे। कॉल करने वाला खुद को गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों बताकर मोटी फिरौती मांग रहा था। शिकायतकर्ता के अनुसार मांग पूरी नहीं करने पर आरोपी ने परिवार के बच्चों और सदस्यों के अपहरण की धमकी दी। लगातार धमकियों से परिवार में दहशत का माहौल है। पुलिस ने शिकायत और उपलब्ध कराए गए विदेशी नंबरों तथा ऑडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस की साइबर अपराध और तकनीकी टीमें कॉल से जुड़े नंबरों, इंटरनेट पते और संभावित स्थानीय मददगारों की जानकारी जुटा रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि आरोपी की पहचान और नेटवर्क का पता लगाने के प्रयास जारी हैं।

संयुक्त अरब अमीरात में बस चालकों के लिए सुनहरा रोजगार अवसर

भारतेन्दु संवाददाता, जालंधर। संयुक्त अरब अमीरात की प्रमुख तेल कंपनी की एक परियोजना के लिए वैध खाड़ी सहयोग परिषद का वाहन चालक लाइसेंस रखने वाले बस चालकों की आवश्यकता है। इच्छुक उम्मीदवारों की आयु 21 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। चयनित चालकों को प्रतिदिन 11 घंटे और महीने में 26 दिन काम के लिए तीन हजार दिरहम वेतन मिलेगा। कंपनी की ओर से रहने और खाने की व्यवस्था निशुल्क की जाएगी। उम्मीदवारों के खाड़ी सहयोग परिषद के लाइसेंस को संयुक्त अरब अमीरात के लाइसेंस में बदला जाएगा। इसके लिए 1090 दिरहम शुल्क वेतन से काटा जाएगा। चयन के लिए साक्षात्कार 25 अगस्त को जालंधर और 26 अगस्त को ऊना में होगा। इच्छुक अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त रोजगार एजेंसी से संपर्क कर सकते हैं।

केमिकल से लदे ट्रक में भीषण आग लगने से ट्रांसपोर्ट नगर में मची अफरा-तफरी

भारतेन्दु संवाददाता, लुधियाना। ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में गुरुवार दोपहर केमिकल से लदे एक ट्रक में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरे ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया और ऊंची लपटों के साथ काले धुएं का गुबार उठने लगा। इससे आसपास मौजूद दुकानदारों, राहगीरों और वाहन चालकों में अफरा-तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक के पिछले हिस्से और केबिन के पास से अचानक धुआं निकलने लगा। चालक ने समय रहते ट्रक को सड़क किनारे रोका और नीचे कूदकर अपनी जान बचाई। ज्वलनशील रसायन होने के कारण आग तेजी से फैल गई और आसपास खड़े वाहनों तथा दुकानों तक खतरा पहुंच गया। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और कर्मियों ने आग बुझाने का अभियान शुरू किया। पुलिस ने एहतियातन यातायात रोककर मार्ग को दूसरे रास्ते से भेजा। दमकल कर्मियों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया।

जीएसटी चोरी मामले में दो गिरफ्तार, कई फर्में जांच के घेरे में

भारतेन्दु संवाददाता, लुधियाना। वस्तु एवं सेवा कर खुफिया महानिदेशालय ने के.एन.एल. ड्राइव लाइन पार्ट्स प्राइवेट लिमिटेड सहित कई फर्मों के ठिकानों पर कार्रवाई के बाद दो लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में के.के. गर्ग और एक अन्य व्यक्ति शामिल बताए जा रहे हैं, जबकि एक व्यक्ति को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। सूत्रों के अनुसार मामला 15 करोड़ रुपये से अधिक की कथित कर चोरी और फर्जी डेबिट नोट से जुड़ा है। जांच टीमों ने मंगलवार को लुधियाना में सात से आठ ठिकानों पर छापेमारी कर खरीद-बिक्री रिकॉर्ड, कर दस्तावेज और डिजिटल आंकड़ों की जांच की थी। आरोप है कि बिना वास्तविक माल की आवाजाही के डेबिट नोट तैयार किए गए। सूत्रों के अनुसार जांच में सारंग थापर से जुड़ी कथित फर्जी फर्मों की भूमिका भी सामने आ रही है।

लंबित मांगों को लेकर खाद्य आपूर्ति निरीक्षकों ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

पंजाब में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के फील्ड इंस्पेक्टर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। कर्मचारियों ने विभाग पर उनकी लंबे समय से लंबित मांगों की अनदेखी करने और वेतन में अनुचित कटौती करने का आरोप लगाया है। यूनियन ने सरकार से तत्काल हस्तक्षेप कर समस्याओं का समाधान करने की मांग की है।

यूनियन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष यादविंदर सिंह ने कहा कि फील्ड इंस्पेक्टर सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अनाज खरीद, भंडारण, परिवहन और खाद्यान्न वितरण जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाते हैं। इसके बावजूद कर्मचारी लंबे समय से वित्तीय और मानसिक दबाव का सामना कर रहे हैं। उनका कहना है कि विभागीय स्तर पर कई बार मांगें उठाने के बावजूद ठोस कार्रवाई नहीं की गई।

यूनियन के महासचिव राजेश बंसल ने कहा कि कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में वेतन से की जा रही अनुचित कटौती को तत्काल बंद करना शामिल है। देर से दस्तावेज जमा होने के नाम पर की गई कटौतियों की समीक्षा कर अनुचित रूप से काटी गई राशि वापस करने की भी मांग की गई है। यूनियन के अनुसार संबंधित मंत्री से बैठक के लिए कई बार अनुरोध किया गया, लेकिन बैठक लगातार टलती रही।

कर्मचारियों ने फील्ड स्तर पर जरूरी संसाधनों की कमी का मुद्दा भी उठाया है। उनका आरोप है कि अनाज के सुरक्षित भंडारण के लिए आवश्यक क्रेट और तिरपाल पिछले करीब चार वर्षों से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। कई बार कर्मचारियों को अपने स्तर पर खर्च कर खाद्यान्न को सुरक्षित रखना पड़ा।

यूनियन ने फील्ड कार्यालयों में बेहतर आधारभूत ढांचा, आवश्यक सामग्री और लंबित भत्ते जारी करने की मांग की है। इसमें कन्वेयंस भत्ता भी शामिल है।

मोहाली के भूखंड आवंटन में गड़बड़ी के आरोप, ई-नीलामी के बाद बदली शर्तों पर जांच

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

मोहाली के फोकल प्वाइंट में 2.112 एकड़ के व्यावसायिक भूखंड के करीब 33 करोड़ रुपये में आवंटन को लेकर पंजाब स्माल इंडस्ट्रीज एंड एक्सपोर्ट कारपोरेशन में जांच की प्रक्रिया तेज हो गई है। प्रवर्तन निदेशालय की 4 से 6 अगस्त तक हुई कार्रवाई के बाद निगम के निदेशक मंडल ने मामले की तथ्यात्मक जांच के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों की कमेटी गठित करने का निर्णय लिया है। कमेटी का उद्देश्य पूरे मामले की जांच कर जिम्मेदारी तय करना और भविष्य में निगम के वित्तीय हितों को सुरक्षित करना है।

पीएसआईईसी बोर्ड की 14 अगस्त को हुई बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार भूखंड आवंटन से जुड़े अधिकारियों को जांच से संबंधित चर्चा से अलग रखा गया। बैठक में भूखंड को ई-नीलामी में शामिल करने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए गए। सामने आया कि ई-नीलामी से पहले संबंधित भूखंड का उचित साइट निरीक्षण नहीं किया गया था और उसकी व्यवहार्यता से जुड़ी रिपोर्ट भी तैयार नहीं की गई थी।

मामले में सबसे महत्वपूर्ण सवाल ई-नीलामी पूरी होने के बाद शर्तों में किए गए बदलाव को लेकर उठ रहे हैं। जांच में यह देखा जाएगा कि नीलामी के समय निर्धारित नियम और बाद में किए गए बदलाव किस स्तर पर हुए तथा इसके पीछे क्या कारण थे। साथ ही यह भी पता लगाया जाएगा कि इन बदलावों से निगम के वित्तीय हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा या नहीं।

निगम के निदेशक मंडल ने मामले की निष्पक्ष और तथ्यात्मक जांच के लिए अन्य विभागों के अधिकारियों को शामिल करने का फैसला किया है। कमेटी संबंधित दस्तावेजों, नीलामी प्रक्रिया, अधिकारियों की भूमिका और भूखंड आवंटन से जुड़े निर्णयों की जांच करेगी।

चन्नी ने कहा- पीयू की अंतिम परीक्षा जरूरी थी, इसलिए कांग्रेस बैठक में नहीं हो सका शामिल

परीक्षा देने पहुंचे चन्नी, बैठक छोड़ी; बोले कांग्रेस अगले साल जीतेगी पंजाब चुनाव

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी वीरवार को पंजाब यूनिवर्सिटी पहुंचे, जहां उन्होंने एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अंतिम परीक्षा दी। चन्नी ने पाठ्यक्रम का 20वां और अंतिम पेपर दिया। परीक्षा केंद्र पहुंचने से पहले उन्होंने कहा कि वह पूरी तैयारी के साथ परीक्षा देने आते हैं और प्रयास रहता है कि पूरा प्रश्नपत्र हल किया जाए। उन्होंने बताया कि अब वह अगले माह पीएचडी में प्रवेश के लिए परीक्षा देने की तैयारी करेंगे।

चन्नी से कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में शामिल नहीं होने को लेकर सवाल किया गया। इस पर उन्होंने कहा कि पार्टी की बैठकें होती रहती हैं और भविष्य में भी बैठक आयोजित की जा सकती है, लेकिन परीक्षा देने का अवसर बार-बार नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि परीक्षा का मौका एक साल बाद आता है, इसलिए उन्होंने अपनी पढ़ाई को प्राथमिकता दी।

चन्नी ने कहा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई के दौरान उनकी विशेष रुचि नीति सुधारों और प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाने से जुड़े विषयों में रही है। उनका मानना है कि किसी भी राज्य के विकास में प्रभावी नीतियों और बेहतर प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने कहा कि वह आगे भी इस क्षेत्र में अध्ययन और काम करना चाहते हैं।

पंजाब के विकास पर जताई चिंता : पूर्व मुख्यमंत्री ने पंजाब की मौजूदा स्थिति पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि पंजाब विकास की दौड़ में पीछे चला गया है और राज्य को दोबारा विकास की राह पर लाने के लिए बेहतर नीतियां तैयार करने की आवश्यकता है। उनके अनुसार केवल राजनीतिक घोषणाओं से राज्य की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। इसके लिए शिक्षा, रोजगार, उद्योग, कृषि और प्रशासनिक सुधारों पर गंभीरता से काम करना होगा।

उन्होंने कहा कि नीति निर्माण में जमीनी परिस्थितियों को ध्यान में रखना जरूरी है। सरकार की योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचे, इसके लिए प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी और जवाबदेह बनाने की जरूरत है। चन्नी ने संकेत दिया कि सार्वजनिक प्रशासन के क्षेत्र में उनकी पढ़ाई और अनुभव भविष्य में राज्य से जुड़े मुद्दों पर उनकी भूमिका को और मजबूत कर सकते हैं।

विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की जीत का दावा : पंजाब में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी चन्नी ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि चुनावी परीक्षा में कांग्रेस जीत दर्ज करेगी। उनके इस बयान को पार्टी की आगामी चुनावी तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। चन्नी ने कहा कि कांग्रेस को जनता से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाना होगा और राज्य के विकास के लिए ठोस दृष्टिकोण सामने रखना होगा।

टेबल एजेंडा वापसी पर निगम सदन में विपक्ष का जोरदार हंगामा

◆ टेबल एजेंडा वापस लेने पर कांग्रेस 'आप' पार्षदों ने मेयर से जवाब मांगा

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ नगर निगम की वीरवार को हुई सदन की बैठक में टेबल एजेंडा को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। बैठक में टेबल एजेंडा नहीं लाए जाने पर विपक्षी पार्षदों ने मेयर के फैसले पर सवाल उठाते हुए विरोध दर्ज कराया।

मेयर सौरभ जोशी ने कहा कि टेबल एजेंडा को नगर निगम की अगली बैठक में लाया जाएगा और उस समय सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि फिलहाल सभी टेबल एजेंडे वापस ले लिए गए हैं। इस पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने आपत्ति जताते हुए कहा कि सदन की मंजूरी के बिना एजेंडे वापस लेने का अधिकार किसे है।

विपक्षी पार्षदों का कहना था कि यदि किसी विषय को सदन में चर्चा के लिए लाया गया है तो उसे बिना सदन की सहमति के वापस नहीं लिया जाना चाहिए। इसी मुद्दे को लेकर बैठक में काफी देर तक हंगामा होता रहा।

मेयर सौरभ जोशी ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि यदि पार्षदों को एजेंडे पर इतनी ही चिंता है तो उन्हें सदन में शाम तक बैठकर चर्चा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि महीने में केवल एक दिन सदन की बैठक होती है, लेकिन चर्चा के समय कई पार्षद बैठक से उठकर चले जाते हैं। उन्होंने सवाल किया कि जब महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा का समय आता है तो पार्षद सदन में रुकने के बजाय अपने घर क्यों चले जाते हैं।

एनेस्थीसिया विशेषज्ञ की कमी पर पीयू डेंटल विद्यार्थियों का जोरदार प्रदर्शन

चार वर्षों से विशेषज्ञ नहीं, जटिल सर्जरी का प्रशिक्षण प्रभावित, छात्रों ने उठाई मांग

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

पंजाब यूनिवर्सिटी के डेंटल कॉलेज के विद्यार्थियों ने वीरवार को प्रशासनिक ब्लॉक के बाहर प्रदर्शन किया और कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विद्यार्थियों का आरोप है कि कॉलेज में पिछले करीब चार वर्षों से जनरल एनेस्थीसिया देने वाला विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं है। इसके कारण ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी की पढ़ाई और विद्यार्थियों का व्यावहारिक प्रशिक्षण लगातार प्रभावित हो रहा है। विद्यार्थियों ने कॉलेज प्रशासन से जल्द विशेषज्ञ की नियुक्ति करने की मांग की है।

विद्यार्थियों के मुताबिक डेंटल कॉलेज में यूजी विद्यार्थियों को पढ़ाई के दौरान विभिन्न प्रकार की सर्जरी और जटिल मामलों का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाना जरूरी है। ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में कई ऐसे मामले सामने आते हैं, जिनमें मरीज को पूरी तरह बेहोश करके सर्जरी करनी पड़ती है। ऐसे मामलों में जनरल एनेस्थीसिया विशेषज्ञ की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। विद्यार्थियों का कहना है कि विशेषज्ञ की अनुपलब्धता के कारण उन्हें इन जटिल प्रक्रियाओं को प्रत्यक्ष रूप से सीखने का पर्याप्त अवसर नहीं मिल पा रहा है।

विद्यार्थियों ने दावा किया कि डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया के वर्ष 2007 के नियमों के अनुसार यूजी पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों के प्रशिक्षण के लिए एनेस्थीसिया से संबंधित आवश्यक व्यवस्था होना जरूरी है। उनका कहना है कि लंबे समय से विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं होने के बावजूद इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया है। इससे विद्यार्थियों के शैक्षणिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण पर असर पड़ रहा है।

बड़े सर्जरी मामलों का नहीं मिल रहा प्रशिक्षण : प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने कहा कि कॉलेज में आने वाले कई मरीजों को जटिल सर्जरी की आवश्यकता होती है। जनरल एनेस्थीसिया की सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण ऐसे मामलों को पंजाब के दूसरे बड़े चिकित्सा संस्थानों में भेजना पड़ता है। विद्यार्थियों के अनुसार कई बड़े और जटिल मामलों को पीजीआई तथा जीएमसीएच-32 रेफर किया जा रहा है।

विद्यार्थियों का कहना है कि जब मरीजों को दूसरे संस्थानों में भेज दिया जाता है तो उन्हें उन सर्जरी को देखने और उनसे व्यावहारिक अनुभव हासिल करने का अवसर भी नहीं मिल पाता। इससे पाठ्यक्रम में निर्धारित प्रशिक्षण पूरा करने में कठिनाई हो रही है। विद्यार्थियों ने कहा कि केवल किताबों और कक्षा में पढ़ाई से जटिल सर्जरी की पूरी जानकारी हासिल नहीं की जा सकती। इसके लिए अस्पताल में वास्तविक मामलों के साथ प्रशिक्षण बेहद जरूरी है।

चार वर्षों से समस्या का समाधान नहीं : विद्यार्थियों ने आरोप लगाया कि जनरल एनेस्थीसिया विशेषज्ञ की कमी कोई नई समस्या नहीं है। कॉलेज में करीब चार वर्षों से यह स्थिति बनी हुई है। इसके बावजूद अब तक विशेषज्ञ की नियमित व्यवस्था नहीं की गई। विद्यार्थियों का कहना है कि लगातार मांग उठाने के बाद भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं होने के कारण उन्हें प्रदर्शन के लिए मजबूर होना पड़ा।

प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से मांग की कि विद्यार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द योग्य जनरल एनेस्थीसिया विशेषज्ञ की नियुक्ति की जाए। उन्होंने कहा कि इससे न केवल विद्यार्थियों को निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार व्यावहारिक प्रशिक्षण मिल सकेगा, बल्कि मरीजों को भी कॉलेज में बेहतर उपचार की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

विद्यार्थियों ने कहा कि मामला केवल उनकी पढ़ाई और परीक्षा तक सीमित नहीं है। एनेस्थीसिया विशेषज्ञ की कमी का सीधा असर मरीजों के उपचार पर भी पड़ रहा है।

ईडी के पत्र पर पंजाब में सियासी घमासान, बिट्टू ने मान से मांगा जवाब

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा प्रवर्तन निदेशालय के पत्र पर की गई टिप्पणियों को लेकर भाजपा नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने पलटवार किया है। बिट्टू ने कहा कि मुख्यमंत्री गंभीर आरोपों को केवल राजनीतिक रूप से प्रेरित बताकर खारिज नहीं कर सकते। यदि जांच एजेंसी ने पंजाब पुलिस से किसी मामले में जानकारी मांगी है तो सरकार को राजनीतिक बयानबाजी के बजाय संबंधित अधिकारियों को तथ्यों की जांच करने देनी चाहिए।

बिट्टू ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय देश की प्रमुख जांच एजेंसियों में शामिल है। यदि एजेंसी ने किसी विशेष मामले को लेकर सवाल उठाए हैं तो उनका जवाब तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर दिया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री अपनी सरकार या उससे जुड़े राजनीतिक लोगों के खिलाफ होने वाली हर जांच को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताकर मामले को टालने की कोशिश करते हैं। इससे जवाब मिलने के बजाय नए सवाल खड़े होते हैं।

उन्होंने कहा कि अगर आरोप गलत हैं तो सरकार को संबंधित दस्तावेज और तथ्य सार्वजनिक करने चाहिए। यदि छिपाने के लिए कुछ नहीं है तो जांच से डरने की कोई वजह नहीं होनी चाहिए। पंजाब की जनता को जांच एजेंसियों पर आरोप लगाने के बजाय पूरे मामले में स्पष्ट जवाब चाहिए।

बिट्टू ने कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है कि वह सरकार के कामकाज से जुड़े सवालों का जवाब दे। मुख्यमंत्री दूसरों से जवाबदेही की मांग कर सकते हैं लेकिन अपनी सरकार को लेकर उठ रहे सवालों से बच नहीं सकते। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक पद किसी व्यक्ति को जांच और सवालों से बचने की ढाल नहीं दे सकता।

भाजपा नेता ने कहा कि जांच एजेंसियों को अपनी वैधानिक जिम्मेदारियां स्वतंत्र रूप से निभाने का अवसर मिलना चाहिए। किसी भी जांच का अंतिम निष्कर्ष सबूत और कानून के आधार पर ही निकलना चाहिए।

जम्मू-कश्मीर पर अमेरिकी राजदूत के बयान से भड़का पाकिस्तान

पाकिस्तान की नाराजगी पर उमर अब्दुल्ला बोले- न आप कुछ कर सकते, न मैं

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर

अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के जम्मू-कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताए जाने वाले बयान पर पाकिस्तान ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। पाकिस्तान ने इस बयान को लेकर इस्लामाबाद में अमेरिकी राजनयिक को तलब कर अपना विरोध दर्ज कराया। वहीं, जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पाकिस्तान की प्रतिक्रिया पर तंज कसते हुए इसे पाकिस्तान और अमेरिका के बीच का मामला बताया।

अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने बुधवार को जम्मू-कश्मीर की यात्रा के दौरान क्षेत्र को भारत का अभिन्न हिस्सा बताया था। उनके इस बयान के बाद पाकिस्तान की ओर से आपत्ति जताई गई। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस्लामाबाद में अमेरिकी चार्ज डी अफेयर्स को तलब किया और जम्मू-कश्मीर से संबंधित गोर की टिप्पणियों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तान की इस कार्रवाई को लेकर जब मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने कहा कि वहां जो कुछ हुआ, वह पाकिस्तान और अमेरिका के बीच का मामला है। उन्होंने कहा कि न तो वह और न ही आम लोग इस मामले में कुछ कर सकते हैं। अमेरिकी राजदूत ने जो कहा, वह कह चुके हैं और अब यह दोनों देशों के बीच की बात है।

> आने वाले समय में इस मुद्दे पर अमेरिका, पाकिस्तान और भारत की ओर से अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ सकती हैं। फिलहाल पाकिस्तान की आपत्ति के बाद मामले ने कूटनीतिक रंग ले लिया है। जम्मू-कश्मीर में भी राजनीतिक दल इस घटनाक्रम को अपने-अपने नजरिए से देख रहे हैं।

उमर अब्दुल्ला की इस प्रतिक्रिया को पाकिस्तान की आपत्ति पर उनका व्यंग्यात्मक जवाब माना जा रहा है। उन्होंने इस मुद्दे पर सीधे तौर पर किसी पक्ष का समर्थन करने के बजाय इसे दोनों देशों के बीच का राजनयिक मामला बताया। सर्जियो गोर की जम्मू-कश्मीर यात्रा और उनके बयान के बाद यह मामला भारत-पाकिस्तान के बीच संवेदनशील मुद्दे को लेकर एक बार फिर चर्चा में आ गया है। पाकिस्तान की ओर से अमेरिकी राजनयिक को तलब किए जाने के बाद इस घटनाक्रम पर राजनीतिक और कूटनीतिक नजरें बनी हुई हैं। फिलहाल उमर अब्दुल्ला ने साफ संकेत दिया है कि इस पूरे विवाद में जम्मू-कश्मीर की भूमिका सीमित है और इसका फैसला संबंधित देशों के बीच कूटनीतिक स्तर पर ही होना है।

इस बीच मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार, अमेरिकी राजदूत की टिप्पणी के बाद पाकिस्तान की ओर से जताई गई आपत्ति दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संवाद का विषय बन सकती है। वहीं, जम्मू-कश्मीर सरकार फिलहाल पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। उमर अब्दुल्ला के बयान से स्पष्ट है कि वह इस मामले को भारत-पाकिस्तान और अमेरिका के बीच राजनयिक स्तर का विषय मान रहे हैं।

उमर के बयान से गरमाई राजनीति

हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में जम्मू-कश्मीर सरकार की भूमिका सीमित है, लेकिन मुख्यमंत्री की टिप्पणी ने राजनीतिक चर्चा को जरूर बढ़ा दिया है। पाकिस्तान की आपत्ति के बाद अब सभी की नजरें अमेरिका की प्रतिक्रिया पर भी टिकी हैं। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर कूटनीतिक स्तर पर बयानबाजी और तेज हो सकती है। फिलहाल, उमर अब्दुल्ला ने स्पष्ट किया है कि जम्मू-कश्मीर को इस विवाद से अलग रखते हुए मामले को संबंधित देशों के बीच ही सुलझाया जाना चाहिए।इस बीच भारत की ओर से भी स्थिति पर नजर रखी जा रही है और कूटनीतिक गतिविधियां लगातार जारी हैं।

विधानसभा कर्मचारियों का प्रतिनियुक्ति के खिलाफ प्रदर्शन

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर विधानसभा के कर्मचारियों ने गुरुवार को विधानसभा परिसर में सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) के उप सचिव बिलाल अहमद मीर की प्रतिनियुक्ति के आदेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने नारेबाजी करते हुए इस फैसले पर अपनी आपत्ति जताई। कर्मचारियों का कहना था कि प्रतिनियुक्ति का आदेश विधानसभा सचिवालय में लागू स्थापित नियमों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के अनुरूप नहीं है। उन्होंने अधिकारियों से आदेश पर तत्काल पुनर्विचार करने की मांग की। कर्मचारियों ने कहा कि विधानसभा सचिवालय की कार्यप्रणाली और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े नियमों का पालन किया जाना चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट किया कि जब तक उनकी मांग पर विचार नहीं किया जाता, तब तक वे अपना विरोध जारी रखेंगे। कर्मचारियों ने अधिकारियों से मामले का जल्द समाधान निकालने की अपील भी की। कर्मचारियों ने कहा कि आदेश वापस होने तक विरोध जारी रहेगा।

विदेशी मेहमानों के कार्यक्रम पहले से तय होने का लगाया आरोप

महबूबा मुफ्ती ने सर्जियो गोर के कश्मीर दौरे पर उठाए सवाल, बोलीं बदली परंपरा

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर

जम्मू-कश्मीर के अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के दौरे को लेकर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में विदेशी राजदूतों और अन्य विदेशी हस्तियों के दौरे पहले की तुलना में काफी बदल गए हैं। महबूबा ने विशेष रूप से वर्ष 2019 के बाद होने वाले विदेशी दौरों को लेकर अपनी बात रखी।

महबूबा मुफ्ती के अनुसार, 2019 से पहले जब विदेशी राजदूत जम्मू-कश्मीर का दौरा करते थे, तो वे केवल सरकारी अधिकारियों तक सीमित नहीं रहते थे। वे समाज के अलग-अलग वर्गों के लोगों से मुलाकात करते थे। इनमें पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोग, व्यापारी, आदिवासी समुदाय और अलग-अलग विचार रखने वाले लोग शामिल होते थे। इन मुलाकातों के माध्यम से विदेशी प्रतिनिधि क्षेत्र के हालात और लोगों की समस्याओं को समझने का प्रयास करते थे। महबूबा ने आरोप लगाया कि अब विदेशी मेहमानों के दौरे पहले से तय कार्यक्रमों तक सीमित रह गए हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि विदेशी मेहमान यहां आते हैं, मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल से मुलाकात करते हैं, शिकारा की सवारी करते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे दौरों से जम्मू-कश्मीर की वास्तविक स्थिति की पूरी तस्वीर सामने नहीं आ पाती। उनके मुताबिक, किसी क्षेत्र को समझने के लिए वहां के आम लोगों, व्यापारियों, पर्यटन से जुड़े लोगों और विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधियों से बातचीत करना जरूरी है।

सर्जियो गोर ने अपने जम्मू-कश्मीर दौरे के दौरान क्षेत्र को लेकर टिप्पणी की थी, जिसके बाद उनका बयान चर्चा में आया। इस बीच, महबूबा मुफ्ती की टिप्पणी ने भी राजनीतिक बहस को तेज कर दिया है। उन्होंने विदेशी प्रतिनिधियों के दौरों में व्यापक जनसंपर्क की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों से संवाद के बिना क्षेत्र की वास्तविक परिस्थितियों और जनभावनाओं को समझना संभव नहीं है। इसलिए विदेशी प्रतिनिधियों को व्यापक बातचीत करनी चाहिए।

उधमपुर को मिली तीसरी वंदे भारत की सौगात, यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत

भारतेंदु संवाददाता, ऊधमपुर। उधमपुर में तीसरी वंदे भारत के ठहराव से जिले के यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। नौकरी, कारोबार, शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी कार्यों के लिए जम्मू और श्रीनगर जाने वाले लोगों को अब दूसरे स्टेशन तक जाने की जरूरत नहीं होगी। उधमपुर से सीधे इस तेज रेल सेवा का लाभ लिया जा सकेगा। इससे क्षेत्र की रेल कनेक्टिविटी मजबूत होने के साथ पर्यटन और व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। यात्रियों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी होने से लोगों में उत्साह है। इससे यात्रियों का समय बचेगा और जम्मू-श्रीनगर के बीच आवागमन अधिक सुविधाजनक और तेज होने की उम्मीद है। नई रेल सेवा से यात्रियों को मिलेगी राहत, समय की बचत के साथ यात्रा होगी और आसान।

(संशोधित) युद्धवीर सेठी ने लगाया जनता दरबार, जन-केंद्रित शासन व्यवस्था को दोहराया

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू। जम्मू ईस्ट विधायक युद्धवीर सेठी ने कच्ची छावनी स्थित भाजपा कार्यालय में जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनीं। क्षेत्रवासियों ने सड़क, जल निकासी, बिजली, पेयजल, स्वच्छता और विकास कार्यों से जुड़ी शिकायतें विधायक के सामने रखीं। सेठी ने संबंधित अधिकारियों से समन्वय कर समस्याओं के शीघ्र समाधान का भरोसा दिया। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को जरूरी मामलों पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

श्रीनगर में 10 हजार की रिश्वत लेते महिला इंस्पेक्टर गिरफ्तार

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने श्रीनगर नगर निगम की जूनियर बिल्डिंग इंस्पेक्टर गजाला अख्तर को 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। अधिकारी पर आरोप है कि भवन निर्माण की अनुमति होने के बावजूद उन्होंने शिकायतकर्ता से रिश्वत की मांग की थी। जानकारी के अनुसार, शिकायतकर्ता ने इस संबंध में एसीबी से संपर्क किया था। शिकायत की जांच के बाद ब्यूरो ने मामले को सही पाया और आरोपी अधिकारी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। निर्धारित योजना के तहत शिकायतकर्ता को रिश्वत की रकम देने के लिए भेजा गया।

जम्मू-कश्मीर के पांच मेडिकल कॉलेजों में चौथे दिन भी हड़ताल, मरीज बेहाल

सरकार की चुप्पी से कर्मचारियों में लगातार बढ़ता जा रहा आक्रोश

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू

जम्मू-कश्मीर के पांच मेडिकल कॉलेजों में गैर राजपत्रित कर्मचारियों की काम छोड़ो हड़ताल गुरुवार को लगातार चौथे दिन भी जारी रही। कर्मचारियों की हड़ताल के कारण इन मेडिकल कॉलेजों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं और मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार उनकी मांगों पर बातचीत के लिए आगे नहीं आ रही है।

जम्मू संभाग के कठुआ, राजौरी और डोडा तथा कश्मीर संभाग के बारामुला और अनंतनाग में वर्ष 2019 में मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए थे। कर्मचारियों का कहना है कि मेडिकल कॉलेज स्थापित होने के कई वर्ष बाद भी यहां सेवा भर्ती नियम तैयार नहीं किए गए हैं। इसके कारण कर्मचारियों की नियमित भर्ती और पदोन्नति की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है।

इसी मांग को लेकर पांचों मेडिकल कॉलेजों के गैर राजपत्रित कर्मचारियों ने सोमवार से काम छोड़कर आंदोलन शुरू किया था। गुरुवार को भी कर्मचारियों ने कॉलेज परिसरों में प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ रोष जताया। उनका कहना है कि जब तक भर्ती नियमों को लेकर स्पष्ट निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक आंदोलन जारी रखा जाएगा।

डोडा में भारी बारिश से नदियों का बढ़ा जलस्तर

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू। जम्मू-कश्मीर में लगातार बारिश के कारण कई क्षेत्रों में नदी-नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। डोडा जिले में लगातार हो रही बारिश और खराब मौसम के चलते नदियों के जलस्तर में खतरनाक वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं, ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में बारिश के कारण रियासी जिले में स्थित सलाल बांध में पानी की आवक भी बढ़ गई है। बढ़ती पानी की आवक को देखते हुए एहतियाती कदम के तौर पर सलाल बांध के कई स्पिलवे गेट खोल दिए गए हैं। प्रशासन और संबंधित एजेंसियां स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। डोडा में नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए स्थानीय लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने लोगों से नदी और नालों के किनारे जाने से बचने की अपील की है।

मां वैष्णो देवी यात्रा फिर शुरू, श्रद्धालुओं में खुशी

श्रद्धालुओं के लिए खुले ताराकोट और बैटरी कार मार्ग

भारतेंदु संवाददाता, कटड़ा

खराब मौसम के बाद मां वैष्णो देवी यात्रा बहाल, भवन की ओर रवाना श्रद्धालु।

लगातार खराब मौसम और बारिश के कारण बुधवार रात करीब आठ बजे अस्थायी रूप से स्थगित की गई मां वैष्णो देवी यात्रा को वीरवार सुबह फिर से सुचारू कर दिया गया। यात्रा बहाल होने की जानकारी मिलते ही पंजीकरण करवाने वाले श्रद्धालुओं में खुशी की लहर दौड़ गई। श्रद्धालु जयकारे लगाते हुए भवन की ओर रवाना होते रहे।

श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने मौसम में सुधार और आवश्यक सुरक्षा जांच के बाद यात्रा मार्ग को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया। इसके साथ ही नया ताराकोट मार्ग भी फिर से शुरू कर दिया गया। बैटरी कार सेवा बहाल होने से श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिली है। विशेषकर बुजुर्गों, बच्चों और चलने में असमर्थ यात्रियों के लिए यह सेवा काफी सुविधाजनक मानी जाती है।

बारिश के कारण यात्रा रोकने के बाद प्रशासन और श्राइन बोर्ड की ओर से मार्ग की स्थिति पर लगातार नजर रखी गई। सुरक्षा व्यवस्था की जांच और मार्ग को सुरक्षित पाए जाने के बाद यात्रा को दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया गया।

यात्रा मार्ग पर सुरक्षा पुख्ता

यात्रा मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था को भी पूरी तरह सुनिश्चित किया गया है। प्रशासन और श्राइन बोर्ड की टीमें मौसम की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त किया गया है। यात्रा शुरू होने के बाद कटड़ा में श्रद्धालुओं की आवाजाही बढ़ गई। बड़ी संख्या में भक्त माता के दर्शन के लिए भवन की ओर रवाना हुए। अधिकारियों ने श्रद्धालुओं से मौसम को देखते हुए सावधानी बरतने और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की है।

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में नागरिकता नियम बदले, अब डीसी करेंगे आवेदनों पर फैसला

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में नागरिकता से जुड़े मामलों को लेकर केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब योग्य आवेदकों को नागरिकता देने की प्रक्रिया में डिप्टी कमिश्नरों को अधिक अधिकार दिए गए हैं। नागरिकता (तीसरा संशोधन) नियम, 2026 की अधिसूचना के बाद नई व्यवस्था लागू की गई है। इसके साथ ही नागरिकता मामलों के निपटारे के लिए पहले से चली आ रही समिति आधारित व्यवस्था समाप्त हो गई है।

नई व्यवस्था के तहत संबंधित जिले के डिप्टी कमिश्नर नागरिकता के लिए प्राप्त आवेदनों की जांच और प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभाएंगे। पात्र पाए जाने वाले आवेदकों को नागरिकता प्रदान करने का फैसला अब जिला स्तर पर लिया जा सकेगा। इससे नागरिकता से जुड़े मामलों के निपटारे की प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक सीधे और व्यवस्थित तरीके से संचालित होने की उम्मीद है। सरकार के इस बदलाव का असर उन आवेदनों पर भी पड़ेगा, जो पहले की व्यवस्था के तहत लंबित थे।

वंदे भारत ने रचा नया इतिहास, दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर पकड़ी 100 की स्पीड

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू

चिनाब पुल पर वंदे भारत की रफ्तार

रेल मंत्रालय से कटरा-बनिहाल रेलखंड पर अधिकतम गति बढ़ाने की मंजूरी मिलने के बाद वंदे भारत एक्सप्रेस ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब ब्रिज पर पहली बार करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ी। इससे जम्मू-कश्मीर में रेल कनेक्टिविटी को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। नॉर्दर्न रेलवे के जम्मू डिवीजन के तहत श्री माता वैष्णो देवी कटरा और बनिहाल के बीच 111 किलोमीटर लंबे नए ब्रॉड गेज रेलखंड पर अब ट्रेनें अधिकतम 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकेंगी। इससे पहले कटरा-संगालदान खंड पर गति सीमा 85 और संगालदान-बनिहाल खंड पर 75 किलोमीटर प्रति घंटा थी। रेलवे ने स्पष्ट किया कि गति बढ़ाने की मंजूरी सभी निर्धारित सुरक्षा मानकों को पूरा करने के बाद दी गई है। जम्मू के सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर उचित सिंघल ने कहा कि गति बढ़ने से यात्रा का समय कम होगा और यात्रियों को तेज, सुरक्षित और आरामदायक सफर मिलेगा। इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर में पर्यटन, व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की संभावना है।

बेटे को बचाने नाले में कूदा पिता, खुद डूबा; बच्चा सुरक्षित

मासूम बेटे को बचाने की कोशिश में पिता ने गंवाई अपनी जान

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर

दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में बुधवार को एक दर्दनाक हादसे में पांच साल के बच्चे की जान बचाने की कोशिश में उसके पिता की डूबने से मौत हो गई। घटना काजीगुंड इलाके की है, जहां पांच वर्षीय इमाद जहूर अचानक नाला सैंड्रन में गिर गया। बेटे को पानी में गिरता देख पिता जहूर अहमद गनई ने बिना देर किए उसे बचाने के लिए नाले में छलांग लगा दी।

जानकारी के अनुसार, जहूर अहमद गनई निवासी निगीनपोरा, कुलगाम अपने पांच वर्षीय बेटे के साथ एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए काजीगुंड इलाके में पहुंचे थे। इसी दौरान बच्चा अचानक पानी की तेज धारा में गिर गया। पिता ने बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना पानी में छलांग लगा दी।

काफी प्रयास के बाद बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन पिता खुद पानी की चपेट में आ गए। हादसे के बाद स्थानीय लोगों की मदद से पिता को बाहर निकालने का प्रयास किया गया। हालांकि, उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। वहीं, बच्चे इमाद जहूर को काजीगुंड के आपातकालीन अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार किया जा रहा है। चिकित्सकों के अनुसार उसकी हालत स्थिर है और वह निगरानी में है।

घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले का संज्ञान लिया। पुलिस ने घटना से जुड़े तथ्यों की जांच शुरू कर दी है। हादसे के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। स्थानीय लोगों के अनुसार, क्षेत्र में पानी का बहाव तेज होने के कारण नाले में जाना जोखिम भरा था। घटना ने एक बार फिर बरसात के दौरान नालों और जलधाराओं के आसपास सावधानी बरतने की जरूरत को सामने ला दिया है।

जलभराव के बाद बढ़ा डेंगू का खतरा, जम्मू में 3 दिन में 39 केस

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू

मानसून की बारिश के बाद जम्मू शहर में जगह-जगह जलभराव से मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है। इसके साथ ही डेंगू के मामलों में भी तेजी से वृद्धि दर्ज की गई है। पिछले तीन दिनों में डेंगू के 39 नए मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की चिंता बढ़ गई है। शहर में अब डेंगू के कुल मामले करीब 70 तक पहुंच चुके हैं। बारिश के बाद कई इलाकों में पानी जमा होने से मच्छरों को पनपने का अनुकूल वातावरण मिल रहा है। इससे डेंगू के साथ मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। निगम के अधीन क्षेत्रों में मच्छरों की बढ़ती संख्या को लेकर लोगों में रोष और चिंता देखी जा रही है। स्थिति को देखते हुए जम्मू नगर निगम ने मलेरिया विभाग के साथ मिलकर विशेष फागिंग अभियान शुरू किया है। यह अभियान 10 सितंबर तक चलाया जाएगा। इसके तहत शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में फागिंग कर मच्छरों की संख्या नियंत्रित करने का प्रयास किया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि जलभराव वाले स्थानों और मच्छरों के संभावित प्रजनन स्थलों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

सुरक्षा | तीर्थयात्रियों के जत्थों की आवाजाही से पहले संवेदनशील इलाकों की गहन जांच कर रही आरओपी टीमें

बुड्ढा अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर जम्मू-राजौरी-पूंछ राजमार्ग पर बढ़ी सुरक्षा

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू

बुड्ढा अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर जम्मू-राजौरी-पूंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया गया है। तीर्थयात्रियों के जत्थों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए जम्मू-कश्मीर पुलिस, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और सेना ने निगरानी बढ़ा दी है। अधिकारियों के अनुसार, राजमार्ग के संवेदनशील हिस्सों में सुरक्षा और क्षेत्र नियंत्रण के विशेष इंतजाम किए गए हैं।

यातायात को सुचारु बनाए रखने और यात्रियों की आवाजाही पर नजर रखने के लिए मार्ग पर दर्जनों अस्थायी चौकियां स्थापित की गई हैं। इन चौकियों के माध्यम से वाहनों की निगरानी और संदिग्ध गतिविधियों की जांच की जा रही है। वहीं, सेना की विभिन्न इकाइयां भी राजमार्ग के महत्वपूर्ण हिस्सों की सुरक्षा में तैनात हैं। यात्रा के दौरान किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए रोड ओपनिंग पार्टियों (आरओपी) को भी सक्रिय किया गया है। संभावित खतरे और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर।

जम्मू-राजौरी-पूंछ राजमार्ग पर बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था

संवेदनशील क्षेत्रों में बढ़ी निगरानी

सुरक्षा बलों की टीमें राजमार्ग के आसपास के क्षेत्रों में लगातार गश्त कर रही हैं। संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है और यात्रियों की आवाजाही के दौरान सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि यात्रा मार्ग पर किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए सुरक्षा एजेंसियां आपसी समन्वय से काम कर रही हैं।

यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता

यात्रा मार्ग पर तैनात जवानों को संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की गतिविधियों पर विशेष नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा प्रमुख पड़ावों और विश्राम स्थलों के आसपास भी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई है। पुलिस और सुरक्षाबलों की टीमें लगातार गश्त कर रही हैं। अधिकारियों के मुताबिक, यात्रियों की सुविधा के साथ उनकी सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए त्वरित प्रतिक्रिया दलों को भी तैयार रखा गया है।

यात्रियों से नियम पालन की अपील

यात्रा के दौरान राजमार्ग पर किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न न हो, इसके लिए यातायात पुलिस को भी विशेष दिशा-निर्देश दिए गए हैं। प्रमुख स्थानों पर जवानों की तैनाती के साथ वाहनों की आवाजाही पर नजर रखी जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां लगातार सूचनाओं का आदान-प्रदान कर रही हैं, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जा सके। प्रशासन ने यात्रियों से भी सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग करने और निर्धारित मार्ग एवं नियमों का पालन करने की अपील की है।

मां लक्ष्मी की आराधना से जुड़ा शुक्रवार क्यों माना जाता है विशेष?

डॉ. नितिका शर्मा
स्वतंत्र लेखक

सप्ताह के सात दिनों में शुक्रवार का अपना विशेष महत्व है। भारतीय जीवनशैली और धार्मिक परंपराओं में शुक्रवार को विशेष रूप से शुभ और महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। यह दिन मां लक्ष्मी की आराधना से जुड़ा हुआ है और अनेक परिवारों में शुक्रवार को सुख, समृद्धि और शांति की कामना के साथ पूजा-अर्चना की जाती है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ मां लक्ष्मी का पूजन करने से घर में धन-धान्य और समृद्धि का वास होता है। हालांकि शुक्रवार का महत्व केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी व्यापक है।

शुक्रवार का नाम शुक्र ग्रह के आधार पर पड़ा है। भारतीय ज्योतिष में शुक्र को सौंदर्य, प्रेम, कला, सुख-सुविधा, वैभव और रचनात्मकता का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि शुक्रवार को इन क्षेत्रों से जुड़े कार्यों के लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है। भारतीय परंपरा में शुक्र ग्रह का संबंध भौतिक सुखों के साथ-साथ जीवन में आकर्षण और सौंदर्य से भी जोड़ा जाता है। इस दिन लोग अपने घरों में स्वच्छता पर विशेष ध्यान देते हैं और वातावरण को सकारात्मक बनाए रखने का प्रयास करते हैं।

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी को समर्पित माना जाता है। कई लोग इस दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं और घर में मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं। पूजा के दौरान दीप जलाकर सुख-समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना की जाती है। कई घरों में शुक्रवार को विशेष व्रत भी रखा जाता है। श्रद्धालु अपनी आस्था के अनुसार मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं और जरूरतमंद लोगों को दान देते हैं। मान्यता है कि दान, सेवा और सद्भावना से जीवन में सकारात्मकता बढ़ती है।

शुक्रवार का संबंध केवल धार्मिक आस्था से नहीं बल्कि परिवार और सामाजिक जीवन से भी है। यह सप्ताह के अंतिम कार्यदिवसों में से एक होने के कारण लोगों में विशेष उत्साह लेकर आता है। पूरे सप्ताह काम और जिम्मेदारियों में व्यस्त रहने के बाद शुक्रवार को लोग अपने परिवार और मित्रों के साथ समय बिताने की योजना बनाते हैं। बच्चों के लिए भी शुक्रवार के बाद आने वाला अवकाश उत्साह का कारण होता है। इस तरह शुक्रवार काम और आराम के बीच एक सेतु की तरह भी दिखाई देता है।

आधुनिक जीवन में शुक्रवार मनोरंजन और सामाजिक गतिविधियों के लिए भी विशेष दिन बन चुका है। लोग सप्ताहभर के तनाव को कम करने के लिए परिवार के साथ बाहर घूमने, फिल्म देखने, भोजन करने या मित्रों से मिलने की योजना बनाते हैं। कार्यालयों और संस्थानों में भी शुक्रवार को सप्ताह के कामकाज को समेटने और अगले सप्ताह की तैयारियों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। हालांकि मनोरंजन के साथ यह भी जरूरी है कि व्यक्ति अपने स्वास्थ्य, परिवार और मानसिक शांति के लिए पर्याप्त समय निकाले।

शुक्रवार हमें यह संदेश भी देता है कि जीवन में केवल धन और भौतिक सुख ही महत्वपूर्ण नहीं हैं। वास्तविक समृद्धि तभी आती है जब व्यक्ति के जीवन में संतोष, प्रेम, स्वास्थ्य, परिवार और मानसिक शांति भी हो। मां लक्ष्मी की आराधना के पीछे भी यही व्यापक भावना दिखाई देती है कि धन का उपयोग सही कार्यों में हो और समाज में जरूरतमंद लोगों की सहायता की जाए। इसलिए शुक्रवार को दान और सेवा से जोड़ना भी भारतीय परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

शुक्रवार का एक और महत्वपूर्ण पहलू कला और रचनात्मकता से जुड़ा हुआ है। शुक्र को कला, संगीत, सौंदर्य और रचनात्मकता का कारक माना जाता है। इसलिए यह दिन कलाकारों, संगीतकारों और रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए भी विशेष महत्व रखता है।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

जब व्यक्ति स्वयं पर भरोसा करना सीखता है तो कोई राह मुश्किल नहीं रहती

सुभाष चंद काशव
स्वतंत्र लेखक

आज के समय में हर व्यक्ति किसी न किसी के सहारे की तलाश में रहता है। कोई दोस्तों पर भरोसा करता है, कोई परिवार पर और कोई समाज पर। लेकिन जीवन का सबसे बड़ा सच यह है कि इंसान का सबसे अच्छा दोस्त उसका अपना आप होता है। जब व्यक्ति खुद का साथ देना सीख जाता है, तब वह हर परिस्थिति का सामना मजबूती से कर सकता है। जीवन में ऐसे कई अवसर आते हैं जब हमारे आसपास के लोग हमारा साथ छोड़ देते हैं, लेकिन यदि हमारा आत्मविश्वास मजबूत है तो हम कठिन परिस्थितियों से भी बाहर निकल सकते हैं।

मेरे विचार से यदि इंसान खुद को समझ ले, खुद पर विश्वास करना सीख ले, तो उसे जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आज की युवा पीढ़ी एक ऐसी दुनिया में जी रही है जहां दिखावा, तुलना और दूसरों की राय बहुत मायने रखने लगी है। सोशल मीडिया पर लोग अपनी जिंदगी का केवल अच्छा हिस्सा दिखाते हैं, जिसे देखकर कई युवा खुद को कम समझने लगते हैं। वे दूसरों जैसी जिंदगी पाने की दौड़ में अपनी असली पहचान खोने लगते हैं। मुझे लगता है कि यही आज की सबसे बड़ी समस्या है। युवा दूसरों को खुश करने में इतने व्यस्त हो गए हैं कि वे खुद की खुशी को भूलते जा रहे हैं।

मेरे अनुसार हर व्यक्ति अपने आप में खास होता है। किसी की सफलता देखकर खुद को कमजोर समझना सही नहीं है। हर इंसान की अपनी क्षमता और अपनी पहचान होती है। जरूरत केवल इस बात की है कि हम खुद को स्वीकार करें और अपनी कमियों को सुधारते हुए आगे बढ़ें। जब इंसान खुद से प्यार करना सीख जाता है, तब उसे दूसरों की स्वीकृति की जरूरत कम पड़ने लगती है। वह अपनी खुशियों और फैसलों के लिए दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय अपने भीतर विश्वास पैदा करता है।

कठिन समय में कई बार लोग साथ छोड़ देते हैं, लेकिन यदि व्यक्ति का आत्मविश्वास मजबूत हो तो वह कभी टूटता नहीं। मैंने हमेशा यही महसूस किया है कि जीवन में सबसे ज्यादा जरूरत खुद के भरोसे की होती है। जब हम खुद को समझते हैं, अपने मन की सुनते हैं और अपनी भावनाओं का सम्मान करते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में खुश रह सकते हैं। आज के युवाओं को यह समझने की जरूरत है कि असली खुशी दूसरों जैसा बनने में नहीं, बल्कि अपने वास्तविक व्यक्तित्व को अपनाने में है।

हर समय दूसरों से तुलना करना केवल तनाव और निराशा बढ़ाता है। किसी व्यक्ति की सफलता के पीछे कितनी मेहनत, संघर्ष और कठिनाइयां रही हैं, यह अक्सर दिखाई नहीं देता। सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाली चमकदार जिंदगी वास्तविक जीवन की पूरी तस्वीर नहीं होती। इसलिए युवाओं को दूसरों की उपलब्धियों से प्रेरणा लेनी चाहिए, लेकिन अपनी जिंदगी को उनके साथ तौलना नहीं चाहिए। यदि युवा अपनी ऊर्जा, अपनी प्रतिभा और अपने सपनों को पहचानने में लगाएंगे तो वे जीवन में कहीं ज्यादा सफल और संतुष्ट रह सकते हैं।

मेरे विचार से आत्मविश्वास इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है। जब व्यक्ति स्वयं का मित्र बन जाता है, तब वह अकेले रहकर भी कभी कमजोर महसूस नहीं करता। उसे अपने निर्णयों पर भरोसा होने लगता है और वह जीवन की कठिन परिस्थितियों का सामना साहस के साथ करना सीख जाता है। आत्मविश्वास का अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति अपनी कमियों को नजरअंदाज करे। बल्कि सच्चा आत्मविश्वास अपनी खूबियों को पहचानने, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने और उन्हें सुधारने की निरंतर कोशिश करने से पैदा होता है।

आत्मविश्वासी व्यक्ति दूसरों पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहता, बल्कि अपनी क्षमताओं को पहचानकर आगे बढ़ता है। जीवन में कई बार लोग बदल जाते हैं, रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं और परिस्थितियां भी साथ नहीं देतीं, लेकिन एक रिश्ता ऐसा होता है जो हमेशा हमारे साथ रहता है—हमारा अपने आप से रिश्ता। इसलिए हमें सबसे पहले स्वयं को समझना चाहिए, अपनी अच्छाइयों और कमियों को स्वीकार करना चाहिए और खुद का सम्मान करना सीखना चाहिए।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

संपादकीय

राष्ट्रीय गीत पर सियासत

राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् को लेकर उभरा विवाद जिस सीमा तक बढ़ रहा है, वह चिंताजनक ही नहीं दुर्भाग्यपूर्ण भी है। राष्ट्रीय गीत किसी एक दल, संगठन या विचारधारा की संपत्ति नहीं होता, बल्कि वह देश के स्वतंत्रता संघर्ष, राष्ट्रीय भावना और सामूहिक चेतना से जुड़ा प्रतीक होता है। इसलिए उसके गायन को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा होना निश्चित रूप से गंभीर प्रश्न पैदा करता है। कांग्रेस के दिल्ली स्थित केंद्रीय कार्यालय पर वंदे मातरम् गायन के समय का दृश्य भी इसी संदर्भ में चर्चा का विषय बना है। कांग्रेस के कार्यालय में वंदे मातरम् पूरा गया, किंतु सामने आए वीडियो को लेकर यह सवाल उठे कि गायन के दौरान कुछ नेताओं की असहजता का कारण क्या था।

कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने इस संबंध में कहा कि 28 अक्टूबर, 1937 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में तय किया गया था कि वंदे मातरम् के केवल प्रारंभिक छंद गाए जाएंगे और तबसे कांग्रेस की यही परंपरा रही है। उनका यह तर्क ऐतिहासिक परंपरा के संदर्भ में अपनी जगह रखता है, लेकिन आज इस मुद्दे पर उठ रहे सवाल केवल परंपरा तक सीमित नहीं हैं। देश में राष्ट्रीय प्रतीकों और उनके सम्मान को लेकर राजनीतिक दलों की भूमिका पर लगातार चर्चा होती रही है। ऐसे में आवश्यकता इस बात की है कि किसी भी राष्ट्रीय गीत या प्रतीक को राजनीतिक विवाद का कारण बनाने के बजाय उसके ऐतिहासिक महत्व और राष्ट्रीय भावना को प्राथमिकता दी जाए।

वंदे मातरम् का इतिहास भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से गहराई से जुड़ा हुआ है। 1896 से लेकर 1936 तक कांग्रेस के अनेक अधिवेशनों में इसका गायन हुआ और स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इस गीत ने लोगों में राष्ट्रीय चेतना पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समय के साथ इसके कुछ अंशों को लेकर विवाद सामने आया और 1937 में इसके गायन को सीमित करने का निर्णय लिया गया। इसके पीछे उस समय की राजनीतिक परिस्थितियां और हिंदू-मुस्लिम एकता को लेकर कांग्रेस नेतृत्व की चिंताएं भी बताई जाती हैं। यह इतिहास आज भी राजनीतिक विमर्श का हिस्सा है और अलग-अलग पक्ष इसे अपने दृष्टिकोण के अनुसार प्रस्तुत करते हैं।

विभाजन से पहले की राजनीति में सांप्रदायिक तनाव लगातार बढ़ रहा था। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच मतभेद गहराते जा रहे थे और देश के राजनीतिक भविष्य को लेकर भी गंभीर असहमति सामने आ रही थी। ऐसे समय में कांग्रेस नेतृत्व के सामने राष्ट्रीय आंदोलन को एकजुट रखने की चुनौती थी। वंदे मातरम् के कुछ अंशों को लेकर मुस्लिम समुदाय के एक वर्ग की आपत्तियों के बाद इसके सीमित गायन का निर्णय लिया गया। आज जब इस निर्णय को देखा जाता है तो यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि क्या उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों में लिया गया फैसला वर्तमान समय में भी उसी रूप में जारी रहना चाहिए।

वंदे मातरम् को लेकर बहस का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि राष्ट्रीय गीत के सम्मान को किसी धार्मिक या राजनीतिक विवाद के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में अलग-अलग धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों के लोग रहते हैं। राष्ट्रीय प्रतीकों की स्वीकार्यता और सम्मान इसी विविधता के बीच राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करते हैं। इसलिए किसी भी राजनीतिक दल की जिम्मेदारी बनती है कि वह राष्ट्रीय प्रतीकों के संबंध में संवेदनशीलता और संतुलन का परिचय दे।

कांग्रेस पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि वह अल्पसंख्यक समुदाय के एक वर्ग को ध्यान में रखते हुए वंदे मातरम् के पूरे स्वरूप से दूरी बनाए हुए है। दूसरी ओर कांग्रेस का तर्क है कि वह लंबे समय से चली आ रही अपनी परंपरा का पालन कर रही है। दोनों पक्षों के बीच इस मतभेद को राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से आगे ले जाकर ऐतिहासिक तथ्यों और संवैधानिक मूल्यों के आधार पर समझने की जरूरत है। राष्ट्रीय गीत को लेकर किसी भी प्रकार का विवाद समाज में अनावश्यक विभाजन पैदा न करे, यह जिम्मेदारी राजनीतिक नेतृत्व की भी है।

यह भी महत्वपूर्ण है कि वंदे मातरम् को लेकर चर्चा केवल राजनीतिक दलों तक सीमित न रहे। युवाओं और नई पीढ़ी को यह बताया जाना चाहिए कि स्वतंत्रता आंदोलन में इस गीत की क्या भूमिका रही और किस प्रकार इसने लोगों में देशभक्ति और स्वतंत्रता की भावना को मजबूत किया। इतिहास को समझे बिना राष्ट्रीय प्रतीकों के महत्व को पूरी तरह समझ पाना संभव नहीं है। साथ ही यह भी जरूरी है कि इतिहास के विवादित प्रसंगों को वर्तमान सामाजिक संबंधों को प्रभावित करने का माध्यम न बनाया जाए।

राष्ट्रीय गीत के सम्मान का अर्थ केवल किसी समारोह में उसे गाना नहीं है। इसका वास्तविक अर्थ देश की स्वतंत्रता, लोकतंत्र, विविधता और नागरिक जिम्मेदारियों का सम्मान करना भी है। राजनीतिक दलों को अपने मतभेदों के बावजूद यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राष्ट्रीय प्रतीकों को लेकर समाज में अनावश्यक तनाव न पैदा हो। वंदे मातरम् का सम्मान तभी सार्थक होगा जब इसे राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का हथियार बनाने के बजाय भारत की स्वतंत्रता यात्रा और राष्ट्रीय चेतना के महत्वपूर्ण प्रतीक के रूप में देखा जाए।

-शिवांश धाकड़

कविता

बचपन पर मोबाइल का साया

संजय एम तराणेकर
(कवि, लेखक व समीक्षक)

यूं किताबें हैं सामने खुली पड़ी,
पर नजरें स्क्रीन में अटकी हैं,
वो बचपन की मीठी किलकारी,
आजकल मोबाइल में सिमटी है।
अब न मैदानों की वह दौड़ रही,
न पेड़ों वाली ठंडी-सी छांव रही,
न मिट्टी में खेलों की मस्ती है,
न बारिश में भीगने की बात रही।
उन उंगलियों के छोटे स्पर्शों में,
अब सारी दुनिया ही सिमट गई,
मां की बातें आधी सुनते बच्चे,
पापा की सीख भी कम लगती गई।
खेल और वीडियो की दुनिया में,
हर पल उन्हें सब प्रिय लगता है,
आभासी दुनिया की चमक देखकर,
असल जीवन फीका लगता है।
यह तकनीक ज्ञान दे तो वरदान है,
सही उपयोग हो तो महान है,
पर मोबाइल की अंधी आदत से,
बचपन का छिनना नुकसान है।
आओ चलो फिर खेल सजाएं,
खुले आंगन में धूप बुलाएं,
कागज की नाव बनाकर फिर से,
बारिश के पानी में उसे बहाएं।
चलकर मिट्टी में सपने बोएं,
पेड़ों की छांव में पल दो पल सोएं,
दोस्तों संग खुलकर हंसे और गाएं,
बचपन के वे दिन फिर से संजोएं।

शिक्षा ऋण की कठिन शर्तें और ऊंची ब्याज दरें विद्यार्थियों के सपनों में बाधा

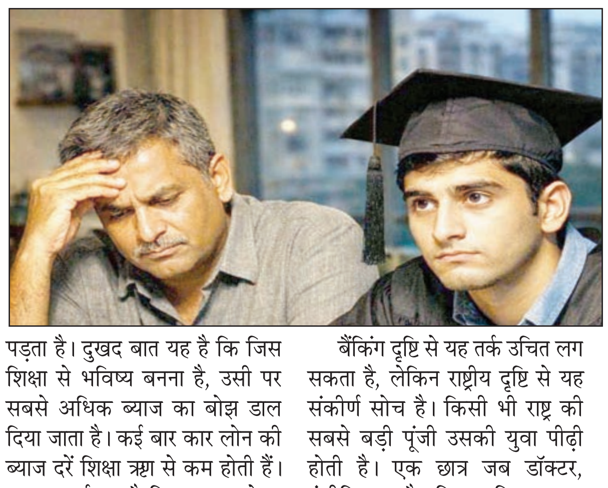

डॉ. तारा देवी
स्वतंत्र लेखक

भारत जैसे विकासशील देश में शिक्षा को हमेशा राष्ट्र निर्माण का सबसे बड़ा माध्यम माना गया है। हम अक्सर कहते हैं कि युवा देश का भविष्य हैं, शिक्षा समाज की रीढ़ है और ज्ञान ही विकास का आधार है लेकिन जब व्यवहारिक व्यवस्था को देखा जाता है, तो स्थिति कुछ अलग दिखाई देती है।

आज भारत में कार खरीदना अपेक्षाकृत आसान होता जा रहा है, जबकि उच्च शिक्षा प्राप्त करना लगातार महंगा और कठिन बनता जा रहा है। बैंक नई कार खरीदने के लिए कम ब्याज दरों पर तुरंत ऋण देने को तैयार रहते हैं, परंतु शिक्षा ऋण के मामले में ब्याज दरें अधिक, नियम कठोर और प्रक्रिया जटिल हो जाती है। यह केवल बैंकिंग व्यवस्था की तकनीकी समस्या नहीं, बल्कि हमारी सामाजिक और आर्थिक प्राथमिकताओं पर गंभीर प्रश्नचिन्ह है। वर्तमान समय में उच्च शिक्षा का खर्च सामान्य परिवारों की क्षमता से बाहर होता जा रहा है। मेडिकल, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, लॉ और निजी विश्वविद्यालयों की फीस लाखों रुपए तक पहुंच चुकी है। मध्यमवर्गीय परिवार बच्चों की पढ़ाई के लिए वर्षों की बचत खर्च कर देते हैं, फिर भी उन्हें शिक्षा ऋण लेना पड़ता है। दुखद बात यह है कि जिस शिक्षा से भविष्य बनना है, उसी पर सबसे अधिक ब्याज का बोझ डाल दिया जाता है। कई बार कार लोन की ब्याज दरें शिक्षा ऋण से कम होती हैं। इसका अर्थ यह है कि एक उपभोक्ता वस्तु खरीदना शिक्षा प्राप्त करने से सस्ता पड़ रहा है। यह केवल आर्थिक असंतुलन नहीं, बल्कि सामाजिक सोच की भी विडंबना है।

बैंकों का तर्क होता है कि कार लोन सुरक्षित होता है, क्योंकि वाहन गिरवी संपत्ति की तरह काम करता है। यदि ऋण चुकाया न जाए तो बैंक वाहन जब्त कर सकते हैं। इसके विपरीत शिक्षा ऋण में कोई भौतिक संपत्ति नहीं होती, वहां केवल छात्र की योग्यता और उसका भविष्य होता है। इसलिए बैंक इसे जोखिमपूर्ण निवेश मानते हैं।

बैंकिंग दृष्टि से यह तर्क उचित लग सकता है, लेकिन राष्ट्रीय दृष्टि से यह संकीर्ण सोच है। किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी उसकी युवा पीढ़ी होती है। एक छात्र जब डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, शिक्षक या प्रशासक बनता है, तो उसका लाभ केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि पूरे समाज को मिलता है। इसलिए शिक्षा ऋण को केवल व्यापारिक दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए।

शिक्षा ऋण आज आर्थिक सहायता के साथ-साथ मानसिक दबाव का कारण भी बन चुका है। विद्यार्थी पढ़ाई पूरी होने से पहले ही ईएमआई और ब्याज की चिंता में घिर जाते हैं। नौकरी मिलने से पहले कर्ज का भय उनके आत्मविश्वास को प्रभावित करता है। भारत में उच्च शिक्षा लगातार महंगी होती जा रही है, जबकि शिक्षा ऋण पर ब्याज दरें अब भी अधिक हैं। इसके विपरीत कार लोन आसानी से और कम ब्याज पर मिल जाते हैं।

यह स्थिति हमारी सामाजिक और आर्थिक प्राथमिकताओं पर प्रश्न खड़े करती है। मध्यमवर्गीय परिवार सबसे अधिक प्रभावित होते हैं, क्योंकि वे न तो सरकारी सहायता के पात्र बन पाते हैं और न ही भारी फीस आसानी से चुका सकते हैं। परिणामस्वरूप उन्हें शिक्षा ऋण लेना पड़ता है, जो बाद में मानसिक और आर्थिक बोझ बन जाता है। कई छात्र अपनी रुचि छोड़कर केवल अधिक वेतन वाली नौकरियों की ओर जाते हैं ताकि ऋण जल्दी चुका सकें। इससे शोध, अध्यापन, साहित्य और सामाजिक सेवा जैसे क्षेत्रों में प्रतिभा कम हो रही है।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

जोहड़ से बावड़ी तक भारत की पुरानी जल संरक्षण परंपराओं में छिपा भविष्य का समाधान

दिनेश दमाथीआ
स्वतंत्र लेखक

भारत सदियों से विविध भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियों वाला देश रहा है। कहीं राजस्थान का तपता रेगिस्तान है, कहीं हिमालय की बर्फीली चोटियां, कहीं पूर्वोत्तर के वर्षा से समृद्ध पहाड़ हैं तो कहीं दक्षिण भारत का शुष्क पठारी क्षेत्र। ऐसी भिन्न परिस्थितियों में जीवन को सुचारु बनाए रखने के लिए भारतीय समाज ने प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए अनेक स्वदेशी जल संरक्षण तकनीकों का विकास किया। इन तकनीकों में स्थानीय परिस्थितियों, उपलब्ध संसाधनों और सामुदायिक भागीदारी का विशेष ध्यान रखा जाता था। आज जब देश जल संकट, भूजल स्तर में गिरावट, अनियमित मानसून और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है, तब पारंपरिक जल संरक्षण प्रणालियां एक बार फिर प्रासंगिक होती दिखाई दे रही हैं।

ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो भारत में जल संरक्षण की परंपरा अत्यंत प्राचीन रही है। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित जल निकासी प्रणाली और विशाल जलाशय इस बात के प्रमाण हैं कि प्राचीन भारतीय जल प्रबंधन को लेकर अत्यंत दक्ष थे। मौर्य एवं चोल शासकों ने तालाबों, नहरों और जलाशयों का विस्तृत नेटवर्क विकसित किया। मध्यकालीन बावड़ियां स्थापत्य कला और जल संरक्षण का अद्भुत उदाहरण बनकर उभरीं। इन संरचनाओं का उद्देश्य केवल पानी को सुरक्षित रखना नहीं था, बल्कि लंबे समय तक लोगों की घरेलू और कृषि संबंधी जरूरतों को पूरा करना भी था।

स्वदेशी जल संरक्षण तकनीकें स्थानीय समुदायों की जरूरतों के अनुसार विकसित हुईं। वर्षा जल का संग्रह, भूजल पुनर्भरण और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराना इनका मुख्य उद्देश्य था। इन प्रणालियों में मिट्टी, पत्थर, लकड़ी और बांस जैसी स्थानीय सामग्री का उपयोग होता था। इनके निर्माण और रखरखाव में समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका रहती थी। यही कारण था कि लोग जलस्रोतों को केवल सरकारी संपत्ति नहीं बल्कि अपनी सामूहिक जिम्मेदारी मानते थे।

भारत के अलग-अलग क्षेत्रों में जल संरक्षण की अलग-अलग परंपराएं विकसित हुईं। राजस्थान के जोहड़ और खड़ीन वर्षा जल संचयन तथा भूजल पुनर्भरण के प्रभावी साधन रहे हैं। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इन प्रणालियों ने कृषि और पेयजल की उपलब्धता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तमिलनाडु की एरी प्रणाली तालाबों के माध्यम से सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण दोनों में सहायक रही। गुजरात और राजस्थान की बावड़ियां जल संरक्षण के साथ सामाजिक जीवन का भी महत्वपूर्ण केंद्र थीं। मेघालय की बांस आधारित बूंद सिंचाई तकनीक स्थानीय संसाधनों के बेहतर उपयोग का उदाहरण है। हिमाचल प्रदेश में कुल्ह, बावड़ी और चश्मे जैसी पारंपरिक संरचनाओं ने पहाड़ी क्षेत्रों में जल उपलब्धता बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

बिहार की आहर-पाइन प्रणाली और नागालैंड की जाबो प्रणाली भी सामुदायिक और पर्यावरण संतुलित जल प्रबंधन की अनूठी मिसाल हैं। इन प्रणालियों में स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने और वर्षा जल का उपयोग करने की व्यवस्था विकसित की गई थी। यह ज्ञान केवल तकनीकी नहीं था, बल्कि पीढ़ी-दर-पीढ़ी समुदायों के अनुभव से विकसित हुआ था।

आज बढ़ते जल संकट और भूजल स्तर में गिरावट के दौर में इन पारंपरिक तकनीकों का महत्व और अधिक बढ़ गया है। कई क्षेत्रों में भूजल का अत्यधिक दोहन हो रहा है। अनियमित मानसून के कारण कहीं सूखे की स्थिति बनती है तो कहीं अचानक भारी बारिश से बाढ़ आती है। ऐसे में वर्षा जल को बह जाने देने के बजाय उसे स्थानीय स्तर पर संग्रहित करना और जमीन में पहुंचाना बेहद जरूरी है। पारंपरिक जल संरचनाएं इस दिशा में प्रभावी समाधान प्रस्तुत कर सकती हैं।

इन तकनीकों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनमें लागत अपेक्षाकृत कम होती है और स्थानीय संसाधनों का उपयोग किया जाता है। इनका रखरखाव भी समुदाय की भागीदारी से संभव है। आधुनिक जल परियोजनाओं की तुलना में कई पारंपरिक प्रणालियां कम ऊर्जा पर आधारित होती हैं। गुरुत्वाकर्षण के आधार पर पानी के प्रवाह का उपयोग होने के कारण इनमें ऊर्जा की खपत भी कम होती है। इसके साथ ही तालाब, बावड़ी और अन्य जल संरचनाएं स्थानीय जैव विविधता को भी बढ़ावा देती हैं और मिट्टी के कटाव को कम करने में सहायता करती हैं।

हालांकि अनेक पारंपरिक जल स्रोत आज अतिक्रमण, उपेक्षा और शहरीकरण के कारण समाप्त होते जा रहे हैं। कई तालाबों पर निर्माण हो गया है, बावड़ियां कचरे से भर गई हैं और पुराने जलस्रोतों का रखरखाव बंद हो गया है। इसके परिणामस्वरूप वर्षा का पानी तेजी से बहकर निकल जाता है और भूजल का पुनर्भरण कम होता जाता है। यह स्थिति आने वाले समय के लिए गंभीर चेतावनी है।

इसलिए आवश्यकता है कि सरकार, शोधकर्ता, गैर-सरकारी संस्थाएं और स्थानीय समुदाय मिलकर पारंपरिक जल प्रणालियों का पुनर्जीवन करें। केवल पुरानी संरचनाओं को बचाना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि उन्हें आधुनिक तकनीक के साथ जोड़ना भी जरूरी है। उदाहरण के लिए जोहड़ों के साथ भूजल की वैज्ञानिक निगरानी, एरी प्रणाली के साथ आधुनिक जल प्रबंधन और बांस आधारित सिंचाई तकनीकों के साथ वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों को जोड़ा जा सकता है।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

व्यक्तित्व विशेष

इंडियन आइडल से मिली लोकप्रियता

मिनी माथुर
जन्म : 21 अगस्त 1975

मिनी माथुर का जन्म **21 अगस्त** 1975 को नई दिल्ली में हुआ था। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज से पढ़ाई की और इसके बाद संचार एवं प्रसारण के क्षेत्र में अपनी रुचि को आगे बढ़ाया। शुरुआती दौर में उन्होंने मॉडलिंग और टेलीविजन प्रस्तुति के माध्यम से मनोरंजन की दुनिया में कदम रखा। अपनी स्पष्ट बोलने की शैली और सहज अंदाज के कारण वह जल्द ही दर्शकों के बीच लोकप्रिय हो गईं।

मिनी को सबसे अधिक प्रसिद्धि संगीत आधारित कार्यक्रम इंडियन आइडल की मेजबानी से मिली। कार्यक्रम के शुरुआती कई सत्रों में उनकी प्रस्तुति ने शो को एक अलग आकर्षण दिया। प्रतियोगियों के साथ उनका आत्मीय व्यवहार और दर्शकों से जुड़ने की क्षमता उनकी खासियत रही। उन्होंने विभिन्न टेलीविजन कार्यक्रमों और मनोरंजन से जुड़े आयोजनों की मेजबानी भी की।

मिनी माथुर ने टेलीविजन के साथ अभिनय और डिजिटल मनोरंजन के क्षेत्र में भी काम किया। बदलते समय के साथ उन्होंने स्वयं को नए माध्यमों के अनुरूप ढाला और अपनी रचनात्मकता को अलग-अलग मंचों पर प्रस्तुत किया। उनका व्यक्तित्व आधुनिक सोच, आत्मविश्वास और रचनात्मक ऊर्जा का उदाहरण माना जाता है।

व्यक्तिगत जीवन में भी मिनी माथुर अपने परिवार और रचनात्मक गतिविधियों के लिए जानी जाती हैं। वह सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहती हैं और अपने विचारों, अनुभवों तथा जीवन से जुड़े विभिन्न पहलुओं को प्रशंसकों के साथ साझा करती हैं। उनकी यात्रा यह दिखाती है कि मनोरंजन की दुनिया में लंबे समय तक अपनी पहचान बनाए रखने के लिए प्रतिभा के साथ निरंतर सीखने और बदलते दौर के साथ आगे बढ़ने की क्षमता भी जरूरी है। जन्मदिन के अवसर पर उनके प्रशंसक और शुभचिंतक उन्हें स्वस्थ, खुशहाल और सफल जीवन की शुभकामनाएं देते हैं। मिनी माथुर की उपलब्धियां आज भी उन युवाओं के लिए प्रेरणा हैं जो टेलीविजन, प्रस्तुति और मनोरंजन के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं।

'भारतेन्दु शिखर

प्रकाशक, मुद्रक, संपादक एवं स्वामी शिवांश धाकड़ द्वारा शर्मा भवन, न्यू रणजीत नगर, एप्पल फ्रूट मंडी, नजदीक ढली टनल, शिमला (हि.प्र.) 171006 से प्रकाशित एवं बायोसर्ट इंटरनेशनल प्रा. लि. प्लॉट नंबर 8, फेज-2 इंडस्ट्रियल एरिया, नगरोटा बगवां, जिला कांगड़ा (हि.प्र.), पिन नंबर-176047 से मुद्रित। समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन के लिए पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी तथा इनसे उत्पन्न समस्त विवाद शिमला न्यायालय के अधीन होंगे।

आरएनआई संदर्भ संख्या-HPHIN/2000/02437
ई-मेल : bhartendunewsmedia@gmail.com, फोन नंबर : 88946-77702

न्यूज ब्रीफ

माफी के बाद फिर पलटे बाल योगी, विधायक बाबूलाल को दी खुली चुनौती

एजेंसी, आगरा। शहर की समस्याओं को लेकर आवाज उठाने वाले बाल योगी और फतेहपुर सीकरी से भाजपा विधायक चौधरी बाबूलाल के बीच विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। बाल योगी ने पहले विधायक के जयपुर हाउस स्थित आवास पर पहुंचकर अपने बयान को लेकर माफी मांगी थी। इसके बाद शाम को उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर फिर विधायक को चुनौती दे दी। बाल योगी ने वीडियो में कहा कि उन्हें कमजोर समझने की गलती न की जाए। उन्होंने विधायक को चेतावनी देते हुए कहा कि वह किसी दबाव में झुकने वाले नहीं हैं। इससे पहले बाल योगी के दो वीडियो सामने आए थे, जिनमें उन्होंने उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और विधायक बाबूलाल पर निशाना साधा था। विधायक ने उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की बात कही थी। माफी के बाद दोबारा सामने आए वीडियो से विवाद और गहरा गया है।

गोरखपुर में डेढ़ करोड़ का प्रीमियम गांजा बरामद, पांच आरोपित गिरफ्तार

एजेंसी, गोरखपुर। रामगढ़ताल क्षेत्र में एएनटीएफ ने गुरुवार सुबह बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन किलो प्रीमियम 'ओजी गांजा' के साथ पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया। बरामद गांजे की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब डेढ़ करोड़ रुपये बताई जा रही है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि गांजे की यह खेप थाईलैंड से भारत पहुंची थी। पुलिस और एएनटीएफ अब इसके सप्लायर तथा पूरे नेटवर्क की जानकारी जुटाने में लगी है। कार्रवाई के दौरान गांजा अर्टिगा कार से बरामद किया गया। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान सूरज सिंह, सत्यम सिंह, रत्नम त्रिवेदी, भाविन और प्रिंस पटेल के रूप में हुई है। इनमें सूरज और सत्यम प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं, जबकि रत्नम, भाविन और प्रिंस गुजरात के अलग-अलग जिलों के निवासी बताए गए हैं। जांच एजेंसियों को आशंका है कि आरोपी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संचालित नशे के नेटवर्क से जुड़े हो सकते हैं। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि थाईलैंड से गांजे की खेप किस माध्यम से भारत लाई गई और इसे आगे किन लोगों तक पहुंचाया जाना था। अधिकारियों के अनुसार, पूछताछ के आधार पर नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की गिरफ्तारी भी हो सकती है।

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए मौका, रेलवे में बढ़ीं रिक्तियां

एजेंसी, प्रयागराज। रेलवे में तकनीकी पदों पर नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए राहत की खबर है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने कनिष्ठ अभियंता, डिपो सामग्री अधीक्षक और रासायनिक एवं धातुकर्म सहायक भर्ती में 36 नए पद जोड़ दिए हैं। इसके बाद कुल रिक्तियों की संख्या 3,993 से बढ़कर 4,029 हो गई है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर इस संबंध में शुद्धिपत्र जारी किया है। संशोधन के तहत रासायनिक एवं धातुकर्म सहायक के 35 पद और सिकंदराबाद बोर्ड के अंतर्गत कनिष्ठ अभियंता विद्युत/टीआरएस का एक अतिरिक्त पद शामिल किया गया है। अब भर्ती का नाम भी संशोधित कर कनिष्ठ अभियंता, डिपो सामग्री अधीक्षक और रासायनिक एवं धातुकर्म सहायक भर्ती कर दिया गया है। भर्ती में शुरुआती मूल वेतन 35,400 रुपये निर्धारित है। भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान में स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थी संबंधित पद के लिए आवेदन कर सकेंगे।

हत्या के प्रयास व लूट के मामले में वांछित दो घायल समेत चार आरोपित गिरफ्तार

एजेंसी, झांसी। रक्सा थाना पुलिस और स्वाट सर्विलांस टीम ने हत्या के प्रयास व लूट के मामले में वांछित चार आरोपितों को पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ रक्सा टोल के आगे नयाखेड़ा रोड पर हुई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मंगल सिंह और लोकेन्द्र साहू के पैर में गोली लगी, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान मंगल सिंह जाट, लोकेन्द्र साहू उर्फ लिटिल, भूपेन्द्र सिंह और ब्रिजकिशोर धाकड़ के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके कब्जे से दो देशी तमंचे, तीन खोखा कारतूस, दो जिंदा कारतूस, 11 हजार रुपये नकद और एक चार पहिया वाहन बरामद किया।

केशव मौर्य का कांग्रेस पर हमला, पूछा- मां दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती से परहेज क्यों?

केशव मौर्य ने वंदे मातरम् को लेकर कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया

एजेंसी, लखनऊ

उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने गुरुवार को 'वंदे मातरम्' के छंदों को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस के फैसले को तुष्टीकरण और वोटबैंक की राजनीति से प्रेरित बताते हुए सवाल किया कि कांग्रेस को मां दुर्गा, मां लक्ष्मी और मां सरस्वती के उल्लेख से परहेज क्यों है। मौर्य ने कहा कि कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए कि वह राष्ट्रगीत के चार छंदों को छोड़ने पर क्यों अड़ी हुई है।

केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि 'रस्सी जल गई, पर ऐंठन नहीं गई।' उन्होंने गांधी परिवार और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने 'वंदे मातरम्' के केवल दो छंद गाने के अपने करीब 90 वर्ष पुराने निर्णय पर एक बार फिर मुहर लगा दी है। उनके मुताबिक, राष्ट्रगीत को अधूरा रखने की यह जिद कांग्रेस को लगातार जनभावनाओं से दूर कर रही है। उप मुख्यमंत्री ने कांग्रेस से सवाल किया कि आखिर उसे मां दुर्गा, मां लक्ष्मी और मां सरस्वती के उल्लेख से परेशानी क्यों है।

उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस किसी वर्ग को खुश करने के लिए राष्ट्रगीत के अन्य छंदों को स्वीकार नहीं कर रही है। मौर्य ने कहा कि कांग्रेस का यह रुख उसकी कथित छद्म धर्मनिरपेक्षता और वोटबैंक की राजनीति को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार के इशारों पर चलने वाली कांग्रेस का यह निर्णय किसी वैचारिक सिद्धांत से प्रेरित नहीं है, बल्कि इसके पीछे वोटबैंक और तुष्टीकरण की राजनीति है।

मौर्य ने कहा कि देश धर्म के आधार पर की गई राजनीति की भयावह कीमत पहले ही विभाजन के रूप में चुका चुका है। इसके बावजूद कांग्रेस राष्ट्रीय एकता के प्रतीक 'वंदे मातरम्' को धार्मिक वोटों के तराजू पर तौलने का प्रयास कर रही है। मौर्य ने कहा कि आज देश की जनता तुष्टीकरण और संकीर्ण वोटबैंक की राजनीति से आगे बढ़ चुकी है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि राष्ट्रगीत को लेकर जनता की भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में पूरे देश में 'वंदे मातरम्' अधूरा नहीं, बल्कि उसके सभी छह छंदों के साथ गूंजेगा।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि 'वंदे मातरम्' केवल एक गीत नहीं, बल्कि देश की राष्ट्रीय चेतना और स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी महत्वपूर्ण भावना है। उन्होंने कांग्रेस से इस विषय पर अपना रुख स्पष्ट करने की मांग की। मौर्य ने कहा कि राष्ट्रगीत को लेकर किसी भी प्रकार की राजनीति देश की भावनाओं के अनुरूप नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अब यह समझ लेना चाहिए कि देश की जनता विकास, राष्ट्रीय एकता और समान अवसर की राजनीति चाहती है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस आज भी पुराने वोटबैंक आधारित राजनीतिक दृष्टिकोण से बाहर नहीं निकल पाई है। मौर्य ने कहा कि राष्ट्रगीत से जुड़े विषय को राजनीतिक विवाद का रूप देने के बजाय सभी दलों को राष्ट्रीय भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस का रुख देश की एकता और अखंडता से जुड़े मुद्दों पर उसके दोहरे रवैये को दर्शाता है।

30 सितंबर तक राम मंदिर परिसर के अधिकांश निर्माण कार्य पूरे होने की उम्मीद

एजेंसी, अयोध्या

श्रीराम मंदिर भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने गुरुवार को कहा कि अयोध्या में राम मंदिर परिसर के अधिकांश निर्माण कार्य आगामी 30 सितंबर तक पूरे होने की उम्मीद है। नृपेंद्र मिश्रा बुधवार को अयोध्या पहुंचे और तीन दिनों तक रहकर मंदिर निर्माण से जुड़े कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। बुधवार शाम निर्माण समिति की बैठक हुई। इसके बाद गुरुवार सुबह सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी दी।

राम मंदिर परिसर के निर्माण कार्यों को समय पर पूरा करने पर जोर।

नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि 30 अक्टूबर तक एल एंड टी और टाटा के कर्मचारी निर्माण कार्यों से हट जाएंगे। इसके बाद मुख्य रूप से ऑडिटोरियम और संग्रहालय से जुड़े कार्य जारी रहेंगे। उन्होंने बताया कि संग्रहालय में कुल 20 गैलरियां बनाई जा रही हैं। इनमें आधुनिक तकनीक के माध्यम से राम मंदिर और भगवान राम से जुड़े प्रसंगों को प्रदर्शित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि संग्रहालय की सातवीं गैलरी में इमर्सिव तकनीक के जरिए मंदिर परिसर के दिव्य दर्शन कराने की तैयारी है। वहीं 17वीं गैलरी में भगवान राम के वनगमन और नदियों से जुड़े प्रसंगों को तकनीक के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। संग्रहालय निर्माण में आईआईटी मद्रास के तकनीकी विशेषज्ञ भी सहयोग कर रहे हैं। नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि मंदिर परिसर की चहारदीवारी का निर्माण दिसंबर तक पूरा होने की उम्मीद है।

इसके बाद सुरक्षा उपकरण लगाने में करीब दो महीने अतिरिक्त लग सकते हैं। समीक्षा बैठक में एल एंड टी, टाटा और सोमपुरा समेत विभिन्न निर्माण एजेंसियों के भुगतान तथा लंबित कार्यों पर भी चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि प्रयास है कि वर्ष के अंत तक निर्माण से संबंधित कोई प्रमुख कार्य अधूरा न रहे। उन्होंने कहा कि सभी एजेंसियों के लंबित कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

राजीव गांधी ने देश को 21वीं सदी में ले जाने का सपना देखा था : राजेश्वर पटेल

एजेंसी, वाराणसी

पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती गुरुवार को वाराणसी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सद्भावना दिवस के रूप में मनाई। महानगर कांग्रेस अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे के नेतृत्व में मैदागिन चौराहे पर कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की।

वाराणसी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी की जयंती पर प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की।

कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं ने राजीव गांधी के योगदान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने आधुनिक भारत के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की। विज्ञान, तकनीक, शिक्षा, संचार और पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने में उनका योगदान उल्लेखनीय रहा। नेताओं ने कहा कि राजीव गांधी ने युवाओं को राष्ट्र निर्माण से जोड़ने के साथ देश को 21वीं सदी की ओर ले जाने का सपना देखा था। वक्ताओं ने कहा कि राजीव गांधी के विचार आज भी युवाओं को प्रेरणा देते हैं और देश की दिशा तय करते हैं।

कानपुर में गंगा में डूबे दो युवकों की तलाश जारी, तेज बहाव बना चुनौती

एजेंसी, कानपुर। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के बिठूर थाना क्षेत्र स्थित गुजारा गंगा घाट पर सोमवार को डूबे दो मौसेरे भाइयों का गुरुवार को भी कोई सुराग नहीं मिल सका। पुलिस और जल पुलिस की टीमें गोताखोरों की मदद से लगातार दोनों युवकों की तलाश कर रही हैं। गंगा में तेज बहाव के कारण बचाव अभियान में कठिनाई आ रही है। सचेण्डी थाना क्षेत्र के चकरपुर मंडी निवासी अभिषेक सोनकर सोमवार को अपने चचेरे भाई आशिक सोनकर (16) और मौसेरे भाई सतीश सोनकर (18) के साथ बाइक से गुजारा गंगा घाट पहुंचे थे। तीनों गंगा में स्नान कर रहे थे। इसी दौरान आशिक और सतीश चेतावनी रस्सी पार कर गहरे पानी में चले गए और तेज बहाव की चपेट में आकर डूब गए। हादसे के बाद पुलिस और जल पुलिस ने तलाश शुरू की। घटनास्थल से सरसैया घाट तक करीब 15 किलोमीटर क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चलाया गया।

जौनपुर में तेज रफ्तार बस की टक्कर से स्कूल वैन पलटी, सात बच्चे घायल, तीन अस्पताल रेफर

एजेंसी, जौनपुर

उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में गुरुवार को बड़ा सड़क हादसा सामने आया। मुंगराबादशाहपुर थाना क्षेत्र के सुजानगंज मार्ग पर उकनी गांव के पास तेज रफ्तार निजी बस ने डीआरएम पब्लिक स्कूल मधुपुर की स्कूल वैन में टक्कर मार दी। टक्कर के बाद वैन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई।

हादसे में वैन में सवार सात बच्चे घायल हो गए। इनमें तीन बच्चों की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया, हालांकि चिकित्सकों ने उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई है। जानकारी के अनुसार, स्कूल वैन मुंगराबादशाहपुर की ओर से सुजानगंज जा रही थी। इसी दौरान पीछे से आ रही बस ने वैन को ओवरटेक करने का प्रयास किया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, इसी दौरान वैन चालक ने बिना संकेत दिए वाहन को अचानक दाईं ओर मोड़ दिया।

तेज गति में होने के कारण बस चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और बस ने वैन के साइड में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही वैन सड़क किनारे पलट गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। आसपास मौजूद ग्रामीणों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर वैन में फंसे बच्चों को बाहर निकाला।

तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार परिवार को रौंदा, बच्चे व दादी समेत तीन की मौत

एजेंसी, झांसी

उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के बबीना थाना क्षेत्र में बुधवार रात तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार परिवार को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में चार वर्षीय बच्चे, उसकी दादी समेत तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि बच्चे के दादा गंभीर रूप से घायल हैं। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि ट्रक बाइक को करीब 200 मीटर तक घसीटता ले गया।

हादसा रात करीब 8:30 बजे बीएचईएल स्थित महिमा ढाबे के पास हुआ। चंदौली गांव निवासी आनंद रजक अपनी पत्नी उर्मिला और चार वर्षीय पोते संस्कार उर्फ भानू के साथ बाइक से घर लौट रहे थे। बाइक पड़ोसी गांव सुकुवां निवासी 21 वर्षीय रविंद्र पाल चला रहा था। इसी दौरान पीछे से आए तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक पर सबसे आगे बैठे भानू की मौके पर ही मौत हो गई। उसकी दादी उर्मिला भी गंभीर रूप से घायल हुईं और उनकी भी मौत हो गई।

घायल आनंद और रविंद्र को मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान रात करीब 12 बजे रविंद्र ने दम तोड़ दिया। हादसे की सूचना मिलते ही परिवारों में कोहराम मच गया। बताया गया कि आनंद की बेटी शिवानी ने बुधवार को अस्पताल में बेटी को जन्म दिया था। आनंद और उर्मिला नवजात नातिन को देखने अस्पताल गए थे। लौटते समय भानू भी दादी के साथ जाने की जिद करने लगा था। सीओ सदर प्रिया सिंह ने बताया कि ट्रक झांसी से ललितपुर की ओर जा रहा था। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। घायल आनंद का उपचार जारी है।

तीन गांवों में कच्चे मकान ढहने से पति पत्नी समेत चार की मौत, एक गंभीर

एजेंसी, मीरजापुर

उत्तर प्रदेश के मीरजापुर जिले में लगातार हो रही बारिश कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों के लिए आफत बन गई है। मड़िहान थाना क्षेत्र में बुधवार रात अलग-अलग स्थानों पर कच्चे मकान और दीवार गिरने की घटनाओं में चार लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। हादसों के बाद गांवों में मातम पसरा हुआ है।

लगातार बारिश से मीरजापुर में कच्चे मकान ढहे, चार लोगों की मौत, ग्रामीणों में दहशत।

पटेहरा पुलिस चौकी क्षेत्र के रजौहां गांव में बारिश के बीच कच्चा मकान अचानक भरभराकर गिर गया। मलबे में दबने से 70 वर्षीय रमाशंकर और उनकी 65 वर्षीय पत्नी अशोक कुमारी की मौत हो गई। दोनों खाना खाने के बाद मकान में सो रहे थे। ग्रामीणों ने करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद उन्हें बाहर निकाला, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। बभनी थपनवा गांव में भी कच्चा मकान गिरने से 62 वर्षीय केवला देवी की मौत हो गई, जबकि उनके 65 वर्षीय पति हीरा गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है।

वहीं निबावल गांव में कच्ची दीवार गिरने से आशा देवी मलबे में दब गईं। उपचार के लिए अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उनकी मौत हो गई। लगातार बारिश से ग्रामीणों में दहशत है। जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार ने अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर पीड़ित परिवारों को नियमानुसार सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्य तेज कर, जर्जर मकानों को चिन्हित करने के निर्देश दिए।

गोरखपुर में पुलिसकर्मियों को मिली सेवा भाव और बेहतर व्यवहार की सीख

एजेंसी, गोरखपुर। डीआइजी ट्रेनिंग देव रंजन वर्मा ने गोरखपुर में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान करीब 450 पुलिसकर्मियों को बेहतर व्यवहार और सेवा भावना का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों को जनता के साथ हमेशा संवेदनशील और सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए। जो व्यवहार स्वयं को पसंद नहीं है, वैसा दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। देव रंजन वर्मा ने कहा कि किसी व्यक्ति पर पहली छाप उसके चेहरे की भाव-भंगिमा और व्यवहार से बनती है। यह प्रभाव महज सात सेकेंड में बन जाता है। ऐसे में पुलिसकर्मियों का जनता से मुस्कुराकर मिलना बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि किसी परेशान व्यक्ति से आत्मीयता और मुस्कान के साथ बात करने से उसकी आधी समस्या वहीं कम हो सकती है।

प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने कार्यशैली में सुधार के लिए टोका-टोकी के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि सही समय पर किसी की गलती बताने और उसे सुधारने का अवसर देने से कार्य और व्यवहार दोनों में सकारात्मक बदलाव आता है। उन्होंने अपने अनुभवों और उदाहरणों के माध्यम से पुलिसकर्मियों को समझाया कि छोटी-छोटी आदतों में सुधार से सेवा की गुणवत्ता बेहतर हो सकती है। डीआइजी ने प्रशिक्षण के दौरान पुलिसकर्मियों से संवाद भी किया और उनकी बातों को सुना। उन्होंने कहा कि पुलिस की जिम्मेदारी केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखना नहीं, बल्कि आम लोगों में सुरक्षा और भरोसे की भावना पैदा करना भी है। जनता के साथ अच्छा व्यवहार पुलिस की छवि को मजबूत करता है। उन्होंने पुलिसकर्मियों से सेवा भाव, अनुशासन और संवेदनशीलता के साथ कार्य करने का आह्वान किया।

आयुषी हत्याकांड में माता-पिता को उम्रकैद, चार साल बाद आया फैसला

एजेंसी, मथुरा

करीब चार साल पुराने आयुषी यादव हत्याकांड में अदालत ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए युवती के माता-पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट अरविंद कुमार द्वितीय की अदालत ने दोनों को बेटी की हत्या का दोषी ठहराया। अदालत ने पिता पर सात हजार रुपये और मां पर छह हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।

मामला वर्ष 2022 का है, जब मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे के लिंक रोड के पास एक युवती का शव लाल रंग के ट्रॉली बैग में मिला था। शव मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। पड़ताल के दौरान मृतका की पहचान आयुषी यादव के रूप में हुई। जांच आगे बढ़ने पर पुलिस ने आयुषी के माता-पिता को हत्या के मामले में आरोपी बनाया था। पुलिस के अनुसार, आयुषी की गोली मारकर हत्या की गई थी। इसके बाद शव को ट्रॉली बैग में रखकर यमुना एक्सप्रेसवे के लिंक रोड के पास फेंक दिया गया था। मामले में पुलिस ने साक्ष्य जुटाने के साथ आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया।

करीब चार वर्ष तक चली न्यायिक प्रक्रिया के बाद अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद माता-पिता को हत्या का दोषी माना। इसके बाद दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। फैसले के बाद पुराने चर्चित हत्याकांड में पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की बात सामने आई है। आयुषी की हत्या और शव को ट्रॉली बैग में फेंके जाने की घटना ने उस समय लोगों को झकझोर दिया था। अदालत के फैसले से मामले में न्यायिक प्रक्रिया पूरी हुई और पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद जगी।

चिंता | बसपा प्रमुख ने बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की

सरकारी स्कूलों की बदहाली पर मायावती चिंतित, सरकारों से ठोस कदम उठाने की अपील

एजेंसी, लखनऊ

बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने उत्तर प्रदेश समेत देश के सरकारी स्कूलों की स्थिति पर चिंता जताई है। उन्होंने बच्चों की शिक्षा को लेकर सरकारों से गंभीरता दिखाने और स्कूलों में जरूरी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की अपील की। मायावती ने देशभर में चल रहे 'स्कूल ठीक करो' अभियान का समर्थन करते हुए कहा कि बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए सरकारों को तत्काल ठोस कदम उठाने चाहिए।

मायावती ने गुरुवार को सोशल मीडिया मंच पर पोस्ट कर कहा कि वर्ष 2013 के बाद जन्मे जेन-अल्फा वर्ग के बच्चे बेहतर शिक्षा की उम्मीद लगाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों के साथ उनके माता-पिता भी उनके उज्ज्वल भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं। अभिभावक अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं, ताकि उनके बच्चों को उन परेशानियों से न गुजरना पड़े, जिनका सामना उन्हें स्वयं करना पड़ा है। बसपा प्रमुख ने कहा कि देशभर में, विशेषकर उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत के कई राज्यों में सरकारी स्कूलों की बदहाल स्थिति की जमीनी तस्वीर चिंता पैदा करने वाली है।

इसी कारण बच्चे और उनके अभिभावक अपनी आवाज उठाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह दुखद है कि जिन बच्चों के खेलने, पढ़ने और सीखने के दिन हैं, उन्हें प्रारंभिक शिक्षा के लिए जरूरी सुविधाओं की मांग को लेकर सड़कों पर संघर्ष करना पड़ रहा है। उन्होंने सरकारी स्कूलों में भवन, शिक्षक, पेयजल, शौचालय और साफ-सफाई जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी का मुद्दा उठाया। मायावती ने कहा कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए केवल योजनाएं बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनका प्रभावी ढंग से धरातल पर लागू होना भी जरूरी है। स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध होना चाहिए, ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो।

बसपा प्रमुख ने शिक्षा के संदर्भ में बाबा साहेब डा. भीमराव आंबेडकर के 'शिक्षित बनो' आह्वान का उल्लेख करते हुए कहा कि बहुजन समाज के लिए स्कूली शिक्षा हमेशा महत्वपूर्ण विषय रही है। उन्होंने दावा किया कि उनके नेतृत्व वाली बसपा सरकारों के दौरान शिक्षा और वंचित वर्गों के कल्याण पर विशेष ध्यान दिया गया। मायावती ने आरोप लगाया कि सरकारी स्कूलों की व्यवस्था सुधारने के बजाय विभिन्न सरकारों ने इसकी पर्याप्त अनदेखी की।

उन्होंने सरकारी स्कूलों को बंद किए जाने के मुद्दे पर भी चिंता जताई और कहा कि बसपा इसका लगातार विरोध करती रही है। उनके अनुसार, सरकारी शिक्षा व्यवस्था कमजोर होने का सीधा असर गरीब और वंचित परिवारों के बच्चों पर पड़ता है। उन्होंने कहा कि अब बच्चे और युवा भी स्कूलों की बुनियादी समस्याओं को लेकर आवाज उठा रहे हैं। ऐसे में सरकारों को उनकी मांगों को गंभीरता से सुनना चाहिए। मायावती ने उत्तर प्रदेश समेत सभी राज्यों की सरकारों से अपील की कि बच्चों की शिक्षा से जुड़ी जरूरतों पर सही नीति और नीयत के साथ तत्काल काम शुरू किया जाए। मायावती ने यह भी कहा कि शिक्षा से जुड़ी मांगों को लेकर आवाज उठाने वाले बच्चों के साथ संवेदनशीलता बरती जानी चाहिए।

लखनऊ में निजी बैंक की महिला कर्मचारी की गोली मारकर हत्या, हमलावर फरार

एजेंसी, लखनऊ

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के गोमतीनगर थाना क्षेत्र में गुरुवार को एक निजी बैंक की महिला कर्मचारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल भेजा, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है।

फोन कर बैंक से बाहर बुलाया, महिला कर्मचारी की गोली मारकर हत्या।

लखनऊ में बैंक कर्मचारी दिव्या मिश्रा की हत्या से मचा हड़कंप।

जानकारी के अनुसार, घटना गोमतीनगर के विवेकखंड स्थित एक निजी बैंक के पास हुई। मृतका की पहचान आलमबाग निवासी दिव्या मिश्रा के रूप में हुई है। वह निजी बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर कार्यरत थीं। बताया जा रहा है कि किसी व्यक्ति ने उन्हें फोन करके बैंक के बाहर बुलाया था। महिला फोन करने वाले व्यक्ति से बातचीत कर रही थीं, इसी दौरान आरोपी ने उन्हें गोली मार दी और मौके से फरार हो गया।

गोली लगने के बाद दिव्या गंभीर रूप से घायल होकर गिर गईं। आसपास मौजूद लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और उन्हें लोहिया अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दिव्या का पिछले करीब एक साल से अपने पति के साथ विवाद चल रहा था। उन्होंने पति से तलाक के लिए अदालत में याचिका भी दायर कर रखी थी। इसी वजह से पुलिस को महिला के पति पर भी शक है। हालांकि अभी तक हत्या के कारण और हमलावर की पहचान को लेकर पुलिस की जांच जारी है।

घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया। फोरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और महिला के मोबाइल फोन की जानकारी भी जुटाई जा रही है। गोमतीनगर थाना प्रभारी के अनुसार, हमलावर की तलाश के लिए पुलिस की कई टीमें लगाई गई हैं। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच विभिन्न पहलुओं से की जा रही है और जल्द ही वारदात का खुलासा करने का प्रयास किया जा रहा है।

हरियाणा के विद्यार्थियों को विदेश में पढ़ाई का अवसर, यूके की यूनिवर्सिटीज से जुड़ेगा प्रदेश

मुख्यमंत्री ने विदेशी विद्यार्थियों से संवाद कर उनके शोध और हरियाणा में अध्ययन के अनुभव की ली जानकारी

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

हरियाणा के विद्यार्थियों को विदेश में उच्च शिक्षा और शोध के अधिक अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में अब हरियाणा के विद्यार्थी यूके की यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई कर सकेंगे। इसके लिए विदेश सहयोग विभाग की ओर से जल्द ही एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।

इस पहल से विद्यार्थियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा हासिल करने और नई तकनीकों से जुड़ने के अवसर मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को संत कबीर कुटीर में प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत 14 देशों के विद्यार्थियों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से उनकी पढ़ाई, शोध और

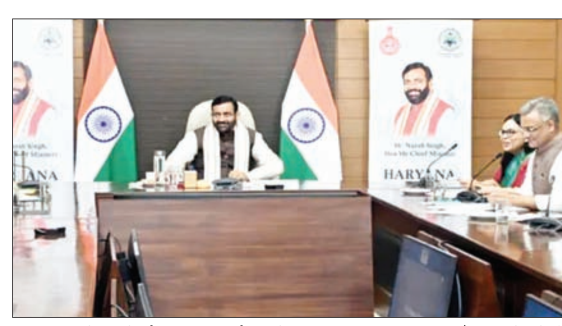

हरियाणा में रहने के अनुभव के बारे में जानकारी ली।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अवसर बढ़ाने की दिशा में काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और अन्य आधुनिक तकनीकों का महत्व तेजी से बढ़ रहा है। इन तकनीकों ने शिक्षा, चिकित्सा, कृषि और दूसरे क्षेत्रों में नए अवसर पैदा किए हैं।

ऐसे में युवाओं के लिए जरूरी है कि वे बदलती तकनीक के अनुरूप अपने ज्ञान और कौशल को लगातार विकसित करते रहें। उन्होंने युवाओं से नई तकनीकों को अपनाने और दुनिया में हो रहे बदलावों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को सीमित दायरे में नहीं रहना चाहिए, बल्कि वैश्विक स्तर पर उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने 'गो ग्लोबल' दृष्टिकोण के साथ शिक्षा और कौशल विकास को आगे बढ़ाने पर जोर दिया।

विदेश सहयोग विभाग की ओर से शुरू किए जाने वाले कार्यक्रम के माध्यम से हरियाणा के विद्यार्थियों को यूके की यूनिवर्सिटीज में अध्ययन और शोध के अवसर मिल सकेंगे। इससे विद्यार्थियों को अंतरराष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों के वातावरण को समझने और वहां उपलब्ध आधुनिक संसाधनों का लाभ उठाने का मौका मिलेगा। हालांकि कार्यक्रम के तहत चयन, पाठ्यक्रम और अन्य प्रक्रियाओं का विस्तृत स्वरूप बाद में सामने आएगा।

जॉर्जिया भेजने के नाम पर लाखों की ठगी का आरोपी राजस्थान से दबोचा

भारतेन्दु संवाददाता, फतेहाबाद

विदेश भेजने और वर्क वीजा दिलवाने का झांसा देकर लाखों रुपये की ठगी करने के मामले में थाना सदर फतेहाबाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के गांव महराना निवासी गुरप्रीत पुत्र राजेश के रूप में हुई है। पुलिस ने यह कार्रवाई 7 लाख 35 हजार 500 रुपये की धोखाधड़ी के मामले में की है।

आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा, फतेहाबाद के प्रभारी निरीक्षक जसकांत ने बताया कि गांव भुथन खुर्द निवासी सुरजीत ने पुलिस को शिकायत दी थी। शिकायत के अनुसार उनका बेटा पंकज विदेश जाने की तैयारी कर रहा था। इसी दौरान उसकी मुलाकात गुरप्रीत से हुई। आरोपी ने उसे विश्वास में लेकर बताया कि उसके जानकार विदेश भेजने और वर्क वीजा लगवाने का काम करते हैं। आरोपी ने पंकज को जॉर्जिया में वर्क वीजा दिलाने और अच्छा रोजगार उपलब्ध करवाने का भरोसा दिया। इसके लिए एयर टिकट सहित करीब साढ़े चार लाख रुपये खर्च होने की बात कही गई। शिकायतकर्ता के अनुसार, आरोपी की बातों पर विश्वास कर उन्होंने अलग-अलग तारीखों में ऑनलाइन माध्यम से उसके खातों में कुल 7 लाख 35 हजार 500 रुपये ट्रांसफर कर दिए।

रुपये लेने के बाद आरोपियों ने न तो पंकज को विदेश भेजा और न ही उसका वर्क वीजा लगवाया। इसके बाद पीड़ित परिवार को ठगी का पता चला और पुलिस में शिकायत दी गई। आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा ने मामले की जांच की। जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद थाना सदर फतेहाबाद में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया। पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए गुरप्रीत को गिरफ्तार कर लिया। मामले में पुलिस आगे की जांच कर रही है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर ठगी के अन्य मामलों की जानकारी जुटा रही है।

न्यूज ब्रीफ

फतेहाबाद में रेलवे ट्रैक पर मिला युवक का शव, ट्रेन की चपेट में आने से मौत

भारतेन्दु संवाददाता, फतेहाबाद। भट्टू क्षेत्र के खाबड़ा लाइन पर गुरुवार तड़के रेलवे ट्रैक पर एक युवक का शव मिला। मृतक की पहचान हिसार जिले के आदमपुर क्षेत्र के गांव चूली बागड़ियां निवासी जयवीर के रूप में हुई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार रात में वह हिसार-जींद पैसेंजर ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। सुबह रेलवे कर्मचारी लाइन का निरीक्षण कर रहे थे। खाबड़ा फाटक के पास शव देखकर उन्होंने रेलवे पुलिस और स्थानीय पुलिस को सूचना दी। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। घटनास्थल के पास मृतक की मोटरसाइकिल भी खड़ी मिली, जिसे पुलिस ने कब्जे में ले लिया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल, फतेहाबाद भेज दिया है। युवक वहां कैसे पहुंचा और हादसा किन परिस्थितियों में हुआ, इसकी जांच जारी है।

फरीदाबाद में युवती को बंधक बनाकर खौलते पानी से जलाया, दिल्ली रेफर

भारतेन्दु संवाददाता, फरीदाबाद। गांव कुरेशीपुर में 23 वर्षीय युवती को कथित तौर पर कमरे में बंधक बनाकर खौलते पानी से जलाने का मामला सामने आया है। युवती के मौसा पंकज के अनुसार, प्रीति को तीन लाख रुपये में एक बुजुर्ग से शादी कराने का दबाव बनाया जा रहा था। विरोध करने पर 16 अगस्त की सुबह करीब चार बजे उस पर खौलता पानी डाल दिया गया। इससे उसके सीने और शरीर के निजी हिस्सों में गंभीर चोटें आईं। आरोप है कि घटना के बाद युवती को इलाज के लिए बाहर नहीं जाने दिया गया और कमरे में ताला लगाकर रखा गया। उसका मोबाइल भी अपने पास रख लिया गया। जानकारी मिलने पर मौसा 18 अगस्त को गांव पहुंचे, लेकिन दरवाजा नहीं खोला गया। 19 अगस्त को पुलिस के साथ पहुंचकर कमरे का ताला तोड़कर युवती को बाहर निकाला गया। उसे पहले स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां से दिल्ली रेफर किया गया। पुलिस अब अस्पताल में युवती के बयान दर्ज करेगी।

पलवल में दहेज के लिए विवाहिता और डेढ़ माह के बच्चे की हत्या, 11 पर केस

भारतेन्दु संवाददाता, पलवल। पलवल जिले के रजपुरा गांव में दहेज के लिए विवाहिता और उसके डेढ़ माह के बच्चे की हत्या का मामला सामने आया है। मृतका के पिता की शिकायत पर सदर थाना पुलिस ने पति सहित 11 लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। शिकायत के अनुसार, विवाहिता को ससुराल पक्ष की ओर से दहेज के लिए परेशान किया जा रहा था। आरोप है कि ससुराल वाले कार की मांग कर रहे थे। मांग पूरी नहीं होने पर विवाहिता और उसके मासूम बच्चे के साथ कथित रूप से मारपीट की गई। दोनों के शवों पर गर्दन के पास निशान मिलने की बात सामने आई है, जिससे मामला संदिग्ध हो गया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने मृतका के पिता के बयान के आधार पर पति समेत 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

करनाल में 17 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म तीन युवक गिरफ्तार

भारतेन्दु संवाददाता, करनाल। करनाल जिले के जुंडला चौकी क्षेत्र के एक गांव में 17 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले में तीन युवकों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार, नाबालिग लड़की घर से बिना बताए चली गई थी। आरोप है कि इसके बाद दो युवक उसे होटल में लेकर गए, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया। मामले में तीसरे युवक की भूमिका भी सामने आने पर पुलिस ने उसे भी आरोपी बनाया। घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजनों ने पुलिस से संपर्क किया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

हर्ष एनकाउंटर पर रोड़ समाज का आक्रोश 24 अगस्त को करनाल में होगा प्रदर्शन

भारतेन्दु संवाददाता, करनाल

हर्ष एनकाउंटर मामले को लेकर रोड़ समाज और सरकार के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से मामले की जांच क्राइम ब्रांच के एडीजीपी को सौंपे जाने के बावजूद समाज इस जांच से संतुष्ट नहीं है। रोड़ महासभा के प्रधान बलकार सिंह ने कहा कि समाज ने मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआइ और सेवानिवृत्त नहीं बल्कि कार्यरत न्यायाधीश से जांच कराने की मांग रखी थी।

ऐसे में केवल क्राइम ब्रांच से जांच कराने का निर्णय उनकी मांग के अनुरूप नहीं है। रोड़ समाज ने सरकार के सामने दो अन्य प्रमुख मांगें भी रखी हैं। इनमें संबंधित पुलिस अधीक्षक को निलंबित करने के साथ उनका तबादला करना और करनाल के विधायक जगमोहन

सरकार के खिलाफ विरोध जताते रोड़ समाज के पदाधिकारी।

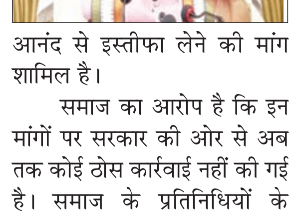

आनंद से इस्तीफा लेने की मांग शामिल है।

समाज का आरोप है कि इन मांगों पर सरकार की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। समाज के प्रतिनिधियों के अनुसार सरकार ने उनकी मांगों पर विचार करने के लिए दो दिन का समय मांगा था, लेकिन चार दिन बीतने के बाद भी सरकार की ओर से कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। इससे समाज में नाराजगी बढ़ गई है।

एचकेआरएन के मुद्दे पर भाजपा ने कांग्रेस पर किया पलटवार

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़। हरियाणा में युवाओं को रोजगार देने के मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गया है। कांग्रेस ने बुधवार को पंचकूला स्थित हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कार्यालय का घेराव किया था। इसके बाद भाजपा ने कांग्रेस को ठेकेदारी प्रथा का जनक बताते हुए सोशल मीडिया पर अभियान शुरू किया। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और इनेलो शासन में ठेकेदारों के माध्यम से युवाओं की मेहनत की कमाई में कटौती और नौकरियों में सिफारिश का रास्ता चलता था। भाजपा के अनुसार, शिकायतों के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पहल करते हुए 13 अक्टूबर 2021 को हरियाणा कौशल रोजगार निगम का पंजीकरण कराया और एक नवंबर 2021 को पोर्टल शुरू किया।

झज्जर में दर्दनाक हादसा, सल्फ्यूरिक एसिड से भरा टैंकर गिरा; चालक ने तोड़ा दम

भारतेन्दु संवाददाता, झज्जर

हरियाणा के झज्जर जिले में केएमपी के पुल पर गुरुवार को दर्दनाक हादसा हो गया। बादली-बुपनिया के पास केएमपी पुल से सल्फ्यूरिक एसिड से भरा एक टैंकर करीब 20 फीट नीचे जा गिरा। हादसे में टैंकर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे फायर-रेस्क्यू टीम ने टैंकर से बाहर निकाला और एंबुलेंस की मदद से झज्जर के अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।

मृतक चालक की पहचान करनाल क्षेत्र के गुरनाम सिंह के रूप में बताई जा रही है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंच गए। दुर्घटना के बाद टैंकर से सल्फ्यूरिक एसिड का रिसाव शुरू हो गया, जिससे आसपास के क्षेत्र में भी खतरा पैदा हो गया। रसायन सड़क

के साथ आसपास के खेतों में भी फैल गया। रिसाव की सूचना के बाद मौके पर सुरक्षा और बचाव के इंतजाम किए गए।

संबंधित फायर-रेस्क्यू टीम ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए। घटनास्थल पर मौजूद टीम लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। खतरनाक रसायन होने के कारण आसपास के क्षेत्र में विशेष सावधानी बरती जा रही है। हादसे के कारणों का अभी स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। दुर्घटना किस वजह से हुई, इसकी जांच की जा रही है। टैंकर के पुल से नीचे गिरने के बाद सड़क और खेतों में फैले एसिड के कारण राहत एवं बचाव कार्य भी चुनौतीपूर्ण रहा।

घटना की जानकारी मिलने के बाद मृतक के स्वजन भी झज्जर पहुंचने की तैयारी में हैं। पुलिस की ओर से हादसे से संबंधित जानकारी जुटाई जा रही है। वहीं, प्रशासन और बचाव दल की प्राथमिकता रसायन के रिसाव को नियंत्रित करना और आसपास के क्षेत्र में किसी तरह की अतिरिक्त घटना को रोकना है। इस हादसे ने एक बार फिर खतरनाक रसायनों का परिवहन करने वाले वाहनों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं।

सिरसा के सीडीएल पॉलिटेक्निक में वेतन संकट लेक्चरर्स और स्टाफ 3-4 महीने से परेशान

भारतेन्दु संवाददाता, सिरसा

नाथूसरी चौपटा स्थित चौधरी देवी लाल (सीडीएल) गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक एजुकेशन सोसायटी के लेक्चरर्स और स्टाफ को समय पर वेतन नहीं मिलने के कारण आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें कई बार तीन से चार महीने तक वेतन का इंतजार करना पड़ता है। लंबे समय से चली आ रही इस समस्या के कारण कर्मचारियों में रोष है।

वेतन में देरी का सीधा असर कर्मचारियों के घरेलू बजट पर पड़ रहा है। समय पर आय नहीं मिलने से घर का किराया, बच्चों की पढ़ाई, रोजमर्रा की जरूरतों और अन्य जरूरी खर्चों को पूरा करना मुश्किल हो रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि नियमित रूप से काम करने के बावजूद वेतन के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता है। इससे आर्थिक परेशानी के साथ मानसिक तनाव भी बढ़ रहा है। कर्मचारियों के अनुसार, यह समस्या पिछले कई वर्षों से बनी हुई

समय पर वेतन की मांग को लेकर सीडीएल पॉलिटेक्निक स्टाफ ने सौंपा ज्ञापन।

है। कई बार वेतन जारी होने में देरी के कारण उन्हें उधार लेकर अथवा अन्य माध्यमों से जरूरी खर्च चलाने पड़ते हैं। उनका कहना है कि वेतन किसी भी कर्मचारी की मूल जरूरत है और इसे निर्धारित समय पर मिलना चाहिए।

अपनी समस्या को अधिकारियों के सामने रखने के लिए लेक्चरर्स और स्टाफ ने वीरवार को प्राचार्य विवेक वोहरा को ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने मांग की कि वेतन जारी करने की प्रक्रिया को व्यवस्थित किया जाए, ताकि भविष्य में उन्हें तीन-चार महीने तक भुगतान का इंतजार न करना पड़े। कर्मचारियों ने कहा कि समय पर वेतन मिलने से वे आर्थिक रूप से राहत महसूस करेंगे और अपने कार्य पर भी बेहतर तरीके से ध्यान दे सकेंगे। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से मामले का स्थायी समाधान निकालने और नियमित रूप से वेतन जारी करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है।

स्टाफ का कहना है कि यदि समस्या का जल्द समाधान नहीं हुआ तो उनकी परेशानियां और बढ़ सकती हैं। कर्मचारियों को उम्मीद है कि ज्ञापन के बाद उनकी मांग पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और समय पर वेतन उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। कर्मचारियों ने कहा कि समय पर वेतन मिलने से आर्थिक स्थिति सुधरेगी और मानसिक तनाव कम होगा। उन्होंने अधिकारियों से जल्द कार्रवाई कर लंबित वेतन जारी करने तथा भविष्य में देरी रोकने की स्थायी व्यवस्था की मांग की।

सांप के डसने के बाद झाड़ा लगवाने पहुंचे बुजुर्ग की अस्पताल में मौत

भारतेन्दु संवाददाता, डबवाली

गांव अबूबशहर में सांप के डसने से 89 वर्षीय बुजुर्ग मदन लाल की मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब वह रोजाना की तरह सुबह करीब 6:30 बजे भांभूओं की ढाणी के पास स्थित भाखड़ा नहर पर मछलियों को आटा डालने गए थे। मृतक के पौत्र सुनील ने बताया कि मछलियों को आटा डालने के बाद दादा वापस घर लौट रहे थे। रास्ते में उन्हें एक लकड़ी पड़ी दिखाई दी। जब वह लकड़ी को हटाने लगे तो पास की झाड़ियों से अचानक एक सांप निकल आया और उनकी कलाई पर डस लिया।

सांप के काटने के बाद मदन लाल पहले गांव में झाड़ा लगवाने के लिए चले गए। इसके बाद वह घर पहुंचे और परिजनों को सांप के काटने की जानकारी दी। उनकी हालत बिगड़ती देख पौत्र सुनील उन्हें तुरंत डबवाली के सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचा। अस्पताल में चिकित्सकों ने उनका प्राथमिक उपचार किया। हालत गंभीर होने के कारण डॉक्टरों ने उन्हें बठिंडा रेफर कर दिया। परिजन उन्हें बठिंडा ले जाने की तैयारी में जुट गए और

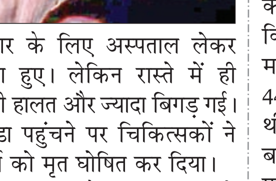

उपचार के लिए अस्पताल लेकर रवाना हुए। लेकिन रास्ते में ही उनकी हालत और ज्यादा बिगड़ गई। बठिंडा पहुंचने पर चिकित्सकों ने बुजुर्ग को मृत घोषित कर दिया।

घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। ग्रामीणों ने भी घटना पर दुख जताया। लोगों का कहना है कि सांप के काटने की स्थिति में समय गंवाने के बजाय पीड़ित को तुरंत अस्पताल पहुंचाना चाहिए, ताकि समय रहते उचित उपचार मिल सके। ग्रामीणों ने कहा कि सांप के काटने के बाद झाड़-फूंक में समय गंवाने के बजाय तुरंत चिकित्सकीय सहायता लेनी चाहिए। समय पर अस्पताल पहुंचने से कई मामलों में पीड़ित की जान बचाई जा सकती है। घटना के बाद गांव में भी लोगों को सांप के काटने पर तत्काल अस्पताल जाने के लिए जागरूक किया गया।

हरियाणा में चीनी के दामों ने बढ़ाई मिठास की चिंता, एक माह में 1840 प्रति क्विंटल महंगी

भारतेन्दु संवाददाता, सीवन

हरियाणा में चीनी के लगातार बढ़ते दामों ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। पिछले एक महीने में चीनी के थोक भाव में 1840 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है। एक महीने पहले जहां चीनी करीब 4400 रुपये प्रति क्विंटल बिक रही थी, वहीं अब इसका थोक भाव बढ़कर 6240 रुपये प्रति क्विंटल पहुंच गया है। बाजार में कीमतों में अचानक आई तेजी का सीधा असर खुदरा ग्राहकों पर भी दिखाई दे रहा है।

छोटे दुकानदारों के अनुसार, खुदरा बाजार में चीनी 64 से 65 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रही है। कुछ स्थानों पर इसकी कीमत 67 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई है। कुछ दिन पहले तक यही चीनी 50 से 52 रुपये प्रति किलो के आसपास उपलब्ध थी। इस तरह करीब एक सप्ताह में ही खुदरा कीमत में लगभग 15 रुपये प्रति किलो तक की बढ़ोतरी हुई है। चीनी की बढ़ती कीमतों का असर घरों के मासिक बजट पर पड़ रहा

हरियाणा में बढ़े चीनी के दाम, बाजार में खरीदारी करते ग्राहक।

है। आम परिवारों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए पहले की तुलना में अधिक खर्च करना पड़ रहा है।

वहीं, त्योहारों और शादी-विवाह का मौसम नजदीक होने के कारण मिठाई कारोबारियों की चिंता भी बढ़ गई है। मिठाई तैयार करने में चीनी प्रमुख सामग्री है। ऐसे में इसकी कीमत बढ़ने से मिठाइयों की लागत भी बढ़ने की संभावना है। दुकानदारों का कहना है कि पिछले एक सप्ताह से चीनी खरीदने वाले ग्राहकों की संख्या में कमी आई है। कैथल के मुख्य बाजार में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। बढ़ी कीमतों के कारण कुछ ग्राहक कम मात्रा में चीनी खरीद रहे हैं, जबकि कुछ लोग खरीदारी टाल रहे हैं। व्यापारियों के अनुसार, यदि चीनी के दाम इसी तरह बढ़ते रहे तो आने वाले त्योहारों में मिठाइयों और अन्य खाद्य पदार्थों की कीमतों पर भी इसका असर पड़ सकता है।

फिलहाल बढ़ती कीमतों ने उपभोक्ताओं के साथ-साथ कारोबारियों के सामने भी नई चुनौती खड़ी कर दी है। मिठाई कारोबारियों का कहना है कि यदि कीमतों में तेजी जारी रही तो उन्हें लागत बढ़ने के कारण मिठाइयों के दाम बढ़ाने पड़ सकते हैं। इससे त्योहारों के दौरान ग्राहकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा।

सौर ऊर्जा में अंबाला की छलांग, 6891 घरों की छतों पर लगे सोलर संयंत्र

जिले ने रूफटॉप सौर संयंत्र स्थापना के लक्ष्य का 71.68 प्रतिशत हिस्सा किया हासिल

भारतेन्दु संवाददाता, अंबाला

बिजली की बढ़ती मांग और परंपरागत ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम करने की दिशा में अंबाला तेजी से सौर ऊर्जा की ओर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत जिले में अब तक 6,891 घरों की छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जा चुके हैं। जिले को कुल 9,614 रूफटॉप सोलर संयंत्र लगाने का लक्ष्य दिया गया है। इस लिहाज से अंबाला ने अपने लक्ष्य का 71.68 प्रतिशत हिस्सा हासिल कर लिया है।

सौर ऊर्जा को लेकर जिले में लोगों का रुझान लगातार बढ़ रहा है। घरों की छतों पर सौर संयंत्र लगने से लोग अपनी बिजली की जरूरत का एक हिस्सा स्वयं पूरा कर सकेंगे। इसके साथ ही परंपरागत बिजली स्रोतों पर निर्भरता कम करने में भी मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत मिलने वाली सहायता और सब्सिडी के कारण भी लोगों में सौर ऊर्जा संयंत्र लगवाने को लेकर रुचि बढ़ी है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के अधीन आने वाले जिलों में अंबाला रूफटॉप सोलर संयंत्र लगाने के मामले में दूसरे स्थान पर है। अंबाला से आगे कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र को

8,495 सौर कनेक्शन लगाने का लक्ष्य दिया गया था, जिसके मुकाबले वहां अब तक 7,130 कनेक्शन लगाए जा चुके हैं। इस तरह कुरुक्षेत्र ने अपने लक्ष्य का 83.93 प्रतिशत हासिल कर लिया है।

अंबाला में भी सौर ऊर्जा संयंत्रों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जिले में 9,614 घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें से 6,891 घरों पर संयंत्र लगाए जा चुके हैं। अभी लक्ष्य पूरा करने के लिए करीब 2,723 और घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ना बाकी है। विभाग की ओर से योजना को आगे बढ़ाने के लिए लोगों को इसके लाभों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। उत्तर हरियाणा के 10 जिलों में एक लाख घरेलू रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने का लक्ष्य रखा गया है। यह लक्ष्य 31 मार्च 2027 तक पूरा किया जाना है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक अब तक क्षेत्र में 51,940 सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जा चुके हैं। इस तरह उत्तर हरियाणा ने निर्धारित लक्ष्य का करीब 52 प्रतिशत हासिल कर लिया है।

सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के पीछे बिजली की जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ स्वच्छ ऊर्जा को प्रोत्साहित करना भी प्रमुख उद्देश्य है। घरों की छतों पर सौर संयंत्र लगाने से उपभोक्ताओं को बिजली उत्पादन का विकल्प मिलता है। इससे भविष्य में बिजली के खर्च को नियंत्रित करने में भी सहायता मिल सकती है। अंबाला की 71.68 प्रतिशत उपलब्धि बताती है कि जिले में लोग सौर ऊर्जा को तेजी से अपना रहे हैं। कुरुक्षेत्र के बाद अंबाला का दूसरे स्थान पर पहुंचना भी जिले के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। विभाग का लक्ष्य आने वाले समय में बाकी बचे घरों को भी योजना से जोड़ना है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सौर ऊर्जा को घर-घर तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है।

इसके लिए लोगों को योजना की प्रक्रिया, आर्थिक सहायता और सौर संयंत्रों से मिलने वाले लाभों की जानकारी दी जा रही है। यदि मौजूदा रफ्तार बनी रहती है तो अंबाला निर्धारित लक्ष्य के करीब पहुंच सकता है। वहीं उत्तर हरियाणा के 10 जिलों में एक लाख घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ने का लक्ष्य भी तय समयसीमा में पूरा करने की दिशा में क्षेत्र लगातार आगे बढ़ रहा है।

विभागीय अधिकारियों के अनुसार, योजना के प्रति लोगों की बढ़ती रुचि को देखते हुए शेष घरों को भी जल्द सौर ऊर्जा से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने और उपभोक्ताओं को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है। सौर संयंत्रों के विस्तार से बिजली बचत के साथ स्वच्छ ऊर्जा को भी बढ़ावा मिलेगा।

दार्जिलिंग घूमने की चाह में घर से निकलीं तीन छात्राएं, पुलिस ने न्यू जलपाईगुड़ी से तलाशा

भारतेन्दु संवाददाता, फरीदाबाद

फरीदाबाद के एक कॉलेज से लापता हुई बीएससी अंतिम वर्ष की तीन छात्राओं को पुलिस ने सुरक्षित तलाश कर लिया। तीनों छात्राएं इंटरनेट पर दार्जिलिंग की खूबसूरत वादियों के वीडियो देखकर वहां घूमने की योजना बनाकर घर से निकली थीं। छात्राओं के अचानक लापता होने से परिजन परेशान हो गए थे और उन्होंने पुलिस से मदद मांगी।

जानकारी के अनुसार, तीनों छात्राएं 14 अगस्त को कॉलेज की छुट्टी के बाद घर जाने के बजाय नमस्ते चौक पहुंचीं। वहां बिरयानी खाने के बाद उन्होंने अपने मोबाइल फोन बंद कर दिए। इसके बाद मेट्रो से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचीं। दार्जिलिंग के लिए सीधी ट्रेन नहीं मिलने पर वे ऑटो से पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन गईं और वहां से डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस में सवार हो गईं। यात्रा के दौरान तीनों दानापुर रेलवे स्टेशन पर उतर गईं। वहां से ऑटो लेकर वाराणसी पहुंचीं और गंगा घाट पर स्नान किया। इसके बाद 15 अगस्त की सुबह दानापुर से न्यू जलपाईगुड़ी के लिए ट्रेन पकड़ी। उनका इरादा वहां से दार्जिलिंग जाने का था।

इधर, देर रात तक छात्राओं के घर नहीं पहुंचने पर परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की। पुलिस ने मोबाइल की आखिरी लोकेशन और कॉल विवरण खंगाला। जांच के दौरान एक छात्रा के मोबाइल से हुई अंतिम बातचीत के आधार पर पुलिस को एक युवक का नंबर मिला। युवक से पूछताछ में पता चला कि

तीनों दार्जिलिंग घूमने के लिए निकली हैं। पुलिस टीम ने पहले दार्जिलिंग में तलाश की, लेकिन वहां छात्राएं नहीं मिलीं। इसके बाद मोबाइल लोकेशन दोबारा जांची गई तो न्यू जलपाईगुड़ी की जानकारी मिली। पुलिस और परिजन वहां पहुंचे और 16 अगस्त की सुबह तीनों छात्राएं रेलवे स्टेशन पर सुरक्षित मिल गईं। पूछताछ में उन्होंने बताया कि इंटरनेट पर दार्जिलिंग के वीडियो देखकर उन्होंने घूमने का मन बनाया था। सुरक्षित मिलने के बाद परिजन उन्हें वापस फरीदाबाद ले आए।

पुलिस ने तीनों छात्राओं को समझाते हुए भविष्य में बिना बताए इस तरह घर से बाहर नहीं जाने की हिदायत दी। छात्राओं ने भी परिजनों को भरोसा दिलाया कि वे आगे ऐसी गलती नहीं करेंगी। तीनों के सकुशल मिलने पर परिजनों ने राहत की सांस ली। पुलिस ने बताया कि मामले में किसी अनहोनी की बात सामने नहीं आई है। छात्राओं की यात्रा के दौरान उन्होंने बिना टिकट सफर भी किया था।

न्यूज ब्रीफ

टिकरी कलां सीएनजी धमाके में अतिरिक्त सिलिंडर बने हादसे की वजह

एजेंसी, नई दिल्ली । टिकरी कलां मेट्रो स्टेशन के पास स्थित सीएनजी पंप पर हुए भीषण धमाके की प्राथमिक वजह सामने आई है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड की जांच में संकेत मिला है कि ट्रक में लगे अनधिकृत अतिरिक्त सिलिंडर हादसे का कारण बने। दुर्घटना में पंप के तीन कर्मचारियों की मौत हो गई थी, जबकि तीन अन्य लोग घायल हुए थे। आईजीएल की जांच टीम के अनुसार, सीएनजी भरवाने के लिए आया ट्रक केवल छह सिलिंडर ले जाने के लिए अधिकृत था। प्राथमिक जांच में वाहन में निर्धारित संख्या से अधिक अतिरिक्त सिलिंडर लगे मिले। इन्हीं अतिरिक्त सिलिंडरों की वैधता और उनकी भूमिका को लेकर जांच की जा रही है। यह स्टेशन आध्या एनर्जीज की डीलरशिप के तहत संचालित होता है। सीएनजी भरने के दौरान अचानक जोरदार धमाका हुआ, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई। हादसे में तीन कर्मचारियों की जान चली गई और तीन लोग घायल हो गए। आईजीएल की प्राथमिक रिपोर्ट सामने आने के बाद प्रशासनिक और तकनीकी एजेंसियां दुर्घटना के सटीक कारणों की विस्तृत जांच कर रही हैं। अतिरिक्त सिलिंडर वाहन में किस तरह लगाए गए और इसके लिए जिम्मेदारी किसकी थी, इसकी भी पड़ताल जारी है। जांच पूरी होने के बाद हादसे की जिम्मेदारी तय होने की उम्मीद है।

पाकिस्तानी उच्चायोग के बाहर अवैध ढांचे पर चला प्रशासन का बुलडोजर

एजेंसी, नई दिल्ली । राजधानी में पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर गुरुवार को प्रशासनिक एजेंसियों ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए स्वीकृत सीमा से बाहर बने अवैध ढांचों और सुरक्षा बैरिकेड्स को हटा दिया। जेसीबी मशीनों की मदद से सड़क और सर्विस लेन पर बने अतिरिक्त ढांचों को ध्वस्त किया गया। कार्रवाई के दौरान उच्चायोग के वीजा अनुभाग के पास लोगों की कतार व्यवस्थित करने के लिए लगाए गए अस्थायी इंतजाम भी हटा दिए गए। अधिकारियों ने परिसर के बाहर लगाए गए टायर रोधी अवरोधक, धातु की रेलिंग और अन्य बैरिकेड्स को भी हटाया। कार्रवाई के बाद मौके पर टूटे हुए लोहे के ढांचे, कंक्रीट के टुकड़े और निर्माण सामग्री बिखरी नजर आई। सर्विस विंडो के आसपास बने कुछ हिस्सों को भी हटाया गया। यह कार्रवाई ऐसे समय हुई है जब तीन दिन पहले इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग के बाहर सुरक्षा बैरिकेडिंग हटाए जाने की खबर सामने आई थी। हालांकि दिल्ली में हुई कार्रवाई का उद्देश्य सड़क और सर्विस लेन पर किए गए कथित अतिक्रमण को हटाना बताया गया है। अधिकारियों ने क्षेत्र में यातायात और आवागमन को सुचारु रखने के लिए कार्रवाई की।

गांधीनगर में संक्रामक रोग विशेषज्ञों का महामंथन

एजेंसी, गांधीनगर। गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर कन्वेंशन एवं प्रदर्शनी केंद्र में 20 से 23 अगस्त तक संक्रामक रोग सोसाइटी का 16वां वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन का उद्घाटन स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रफुल पानशेरिया करेंगे। इस दौरान रोगाणुरोधी प्रतिरोध और उसके उचित नियंत्रण से संबंधित विशेषज्ञों द्वारा तैयार पुस्तक का विमोचन भी किया जाएगा। सम्मेलन में देश-विदेश के संक्रामक रोग विशेषज्ञ, चिकित्सक, शोधकर्ता, सूक्ष्मजीव विज्ञानी और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञ भाग लेंगे। इसमें 950 से अधिक प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है। कार्यक्रम में संक्रामक रोगों के निदान, बचाव और उपचार से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। सम्मेलन में क्षय रोग, एचआईवी, फंगल संक्रमण, विषाणुजनित रोग, संक्रमण नियंत्रण और रोगाणुरोधी दवाओं के बढ़ते प्रतिरोध जैसे विषय प्रमुख रहेंगे। गुजरात में रोगाणुरोधी प्रतिरोध की निगरानी और नियंत्रण के प्रयासों पर भी विशेष चर्चा होगी। इसके साथ ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता और आधुनिक चिकित्सा तकनीकों के उपयोग पर विशेषज्ञ विचार साझा करेंगे।

सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर केजरीवाल ने शाह पर लगाए आरोप

एजेंसी, नई दिल्ली

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है। केजरीवाल ने गिरफ्तारी के समय और परिस्थितियों पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि जैन की गिरफ्तारी केंद्रीय गृह मंत्री के कथित निर्देश पर की गई।

केजरीवाल ने बुधवार को इंटरनेट मीडिया मंच एक्स पर दावा किया कि एक एसीबी अधिकारी ने उन्हें बताया था कि बुधवार सुबह तक सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार करने की कोई योजना नहीं थी। उनके अनुसार दोपहर में अचानक जैन को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया गया। केजरीवाल ने जांच एजेंसी पर कथित दबाव को लेकर भी सवाल उठाए और पूछा कि आखिर गिरफ्तारी की योजना में अचानक बदलाव क्यों किया गया।

गिरफ्तारी के तरीके पर भी सवाल : केजरीवाल ने जैन की गिरफ्तारी को लेकर सरकार और जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि अब गिरफ्तारी केवल अपराध की जांच के आधार पर नहीं हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक दबाव के कारण लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि ये आरोप केजरीवाल की ओर से लगाए गए हैं।

केजरीवाल ने कहा कि पुलिस किसी व्यक्ति को तब गिरफ्तार करती है, जब उससे पूछताछ या जांच की आवश्यकता होती है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि सुबह तक गिरफ्तारी की कोई योजना नहीं थी तो कुछ घंटों के भीतर ऐसा क्या बदल गया कि जैन को गिरफ्तार करने का निर्देश दे दिया गया।

हिमालय की बढ़ती गर्मी से बर्फ पर संकट पश्चिमी क्षेत्र सबसे अधिक संवेदनशील

एजेंसी, नई दिल्ली

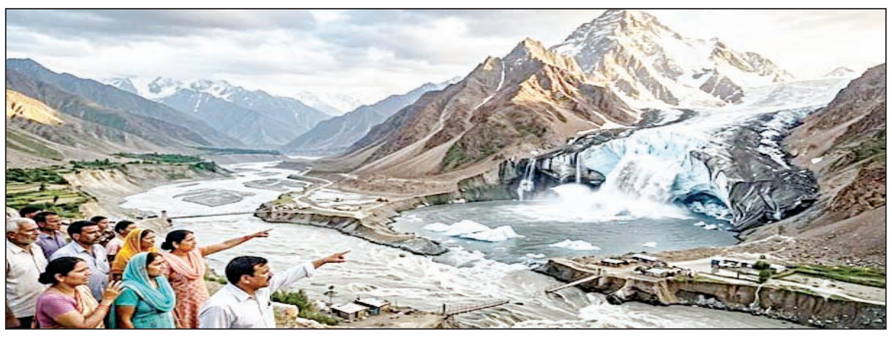

जलवायु परिवर्तन का असर भारतीय हिमालयी क्षेत्रों में तेजी से दिखाई देने लगा है। हाल ही में जर्नल ऑफ अर्थ सिस्टम साइंस में प्रकाशित एक शोध अध्ययन में पश्चिमी हिमालय को लेकर गंभीर चेतावनी सामने आई है। अध्ययन के मुताबिक मध्य और पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय अधिक तेजी से गर्म हो रहा है। लद्दाख, जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश इस बदलाव से सबसे अधिक प्रभावित हो सकते हैं। यदि वैश्विक स्तर पर कार्बन उत्सर्जन में प्रभावी कमी नहीं की गई तो सदी के अंत तक पश्चिमी हिमालय अपनी मौसमी बर्फ का बड़ा हिस्सा खो सकता है।

120 वर्षों के आंकड़ों का किया अध्ययन : यह अध्ययन बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान मेसरा, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे और अशोका विश्वविद्यालय के विज्ञानियों ने संयुक्त रूप से किया है। शोधकर्ताओं ने वर्ष 1901 से 2020 तक के 120 वर्षों के तापमान आंकड़ों का विश्लेषण किया। इसके साथ ही आठ वैश्विक जलवायु मॉडलों की मदद से वर्ष 2100 तक संभावित जलवायु परिस्थितियों का आकलन किया गया।

अध्ययन के लिए पूरे भारतीय हिमालयी क्षेत्र को पश्चिमी, मध्य और पूर्वी हिस्सों में बांटा गया। पश्चिमी क्षेत्र में लद्दाख, जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, मध्य क्षेत्र में उत्तराखंड तथा पूर्वी क्षेत्र में सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर के हिस्सों को शामिल किया गया।

दिन से ज्यादा तेजी से बढ़ रहा रात का तापमान : अध्ययन में सबसे चिंताजनक बदलाव न्यूनतम तापमान यानी रात के तापमान में सामने आया है। पश्चिमी और मध्य हिमालय में सर्दियों तथा बसंत के दौरान रातें पहले की तुलना में तेजी से गर्म हो रही हैं। विज्ञानियों के अनुसार रात में पर्याप्त ठंड नहीं पड़ने से बर्फ को दोबारा जमने का समय कम मिल रहा है। इससे बर्फ पिघलने की प्रक्रिया तेज हो सकती है और नदियों में पानी पहुंचने का प्राकृतिक चक्र प्रभावित हो सकता है।

सात डिग्री तक बढ़ सकता है सर्दियों का तापमान : शोध में अनुमान लगाया गया है कि यदि कोयला और पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधनों का इस्तेमाल मौजूदा गति से जारी रहा तो वर्ष 2081 से 2100 के बीच पश्चिमी हिमालय में सर्दियों का तापमान बीसवीं सदी की शुरुआत की तुलना में 7.18 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है।

फर्जी सीबीआई बनकर घर पहुंचे ठग, महिला की सूझबूझ से टली लूट

एजेंसी, नई दिल्ली

राजधानी दिल्ली के रोहिणी इलाके में फिल्म स्पेशल 26 की तर्ज पर ठगी और लूट की कोशिश का मामला सामने आया है। करीब आठ से दस लोगों का एक समूह खुद को केंद्रीय जांच एजेंसी के अधिकारी बताकर एक व्यापारी के घर पहुंचा। आरोपितों ने घर में छापा मारने का दावा करते हुए प्रवेश करने का प्रयास किया, लेकिन व्यापारी की पत्नी की सतर्कता और पड़ोसियों के हस्तक्षेप से बड़ी वारदात टल गई।

पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार, संदिग्ध लोग जांच एजेंसी के निशान वाले कपड़े पहने हुए थे और उनके पास पहचान पत्र भी थे। घर पहुंचने के बाद उन्होंने खुद को अधिकारी बताते हुए छापेमारी की बात कही और गेट खोलने का दबाव बनाया।

दस्तावेज और वारंट मांगकर रोका : व्यापारी की पत्नी को आरोपितों के व्यवहार पर संदेह हुआ। उन्होंने बिना घबराए उनसे पहचान पत्र दिखाने के साथ छापेमारी से संबंधित आवश्यक दस्तावेज और तलाशी वारंट दिखाने को कहा। महिला ने गेट खोलने से इनकार कर दिया। इसके बाद संदिग्ध लोगों ने कुछ देर तक दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन महिला अपनी मांग पर अड़ी रही।

महिला की सतर्कता के कारण आरोपितों को अपनी योजना सफल होती नजर नहीं आई। इसी दौरान आसपास के लोगों को भी घटना की जानकारी हो गई। पड़ोसियों के हस्तक्षेप के बाद संदिग्ध लोग वहां से भाग निकले।

सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस : घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि संदिग्धों की पहचान की जा सके। उनके आने और वहां से निकलने के रास्तों की भी जांच की जा रही है।

पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आरोपितों ने व्यापारी को ही निशाना क्यों बनाया और उन्हें परिवार तथा कारोबारी गतिविधियों के बारे में पहले से कोई जानकारी थी या नहीं।

पांच रुपए में गरीबों को मिलेगा पौष्टिक भोजन, दिल्ली में बढ़ेगा अटल कैंटीन का नेटवर्क

एजेंसी, नई दिल्ली

जरूरतमंदों को सस्ता भोजन उपलब्ध कराने के लिए नई कैंटीन शुरू

दिल्ली सरकार की अंत्योदय योजना के तहत राजधानी में अटल कैंटीन का विस्तार किया जा रहा है। इसी क्रम में जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक एवं शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने जेजे कॉलोनी, ओल्ड पंखा रोड स्थित मदर डेयरी के सामने नई अटल कैंटीन का उद्घाटन किया। कैंटीन शुरू होने से क्षेत्र के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों, दिहाड़ी मजदूरों और जरूरतमंद लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

सरकार की इस पहल का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को मात्र पांच रुपये में स्वच्छ, संतुलित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है। कैंटीन में मिलने वाला सस्ता भोजन विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी होगा, जो रोजाना काम की तलाश में घर से बाहर रहते हैं और कम आय के कारण भोजन पर अधिक खर्च नहीं कर पाते।

उद्घाटन के दौरान आशीष सूद ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि राजधानी में कोई भी गरीब व्यक्ति भूखा न सोए। उन्होंने कहा कि अटल कैंटीन योजना के माध्यम से जरूरतमंदों को कम कीमत पर सम्मानजनक और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास के संकल्प और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में चल रही जनकल्याणकारी पहल का हिस्सा बताया।

राजधानी में तेजी से बढ़ाया जा रहा कैंटीन का नेटवर्क : शहरी विकास मंत्री ने बताया कि दिल्ली के अलग-अलग क्षेत्रों में अटल कैंटीन की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। इसके तहत दो दिन पहले ही राजधानी में 25 नई अटल कैंटीन शुरू की गई थीं। सरकार का लक्ष्य आने वाले समय में झुग्गी-बस्तियों और श्रमिक आबादी वाले इलाकों में कैंटीन का विस्तार करना है।

सरकार का मानना है कि इन कैंटीन के माध्यम से कम आय वाले लोगों को सस्ती दर पर भोजन उपलब्ध कराने के साथ उनके घरेलू खर्च का बोझ भी कम किया जा सकेगा।

यमुना की गाद से बढ़ रहा अमोनिया दिल्ली की जलापूर्ति पर गहरा संकट

एजेंसी, नई दिल्ली

दिल्ली में यमुना के पानी में बार-बार बढ़ने वाले अमोनिया के स्तर को लेकर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रारंभिक अध्ययन में अहम संकेत सामने आए हैं। अध्ययन के अनुसार वजीराबाद क्षेत्र में यमुना की तलहटी में लंबे समय से जमा गाद कच्चे पानी में अमोनिया की मात्रा बढ़ने की एक प्रमुख वजह हो सकती है। हालांकि अभी नमूनों की विस्तृत जांच जारी है और अंतिम निष्कर्ष सामने आना बाकी है।

अपर यमुना रिवर बोर्ड के निर्देश पर किए जा रहे अध्ययन के दौरान अमोनिया का स्तर बढ़ने के समय वजीराबाद पोंडेज क्षेत्र से पानी और गाद के नमूने लिए गए थे। इन नमूनों की जांच के जरिए यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि अमोनिया की मात्रा बढ़ने के पीछे कौन-कौन से कारण जिम्मेदार हैं और इसका दिल्ली की जलापूर्ति पर कितना प्रभाव पड़ रहा है।

अब तक यमुना में अमोनिया की मात्रा बढ़ने के लिए मुख्य रूप से हरियाणा से आने वाले पानी में औद्योगिक रसायनों की मौजूदगी को जिम्मेदार माना जाता रहा है। इसके चलते जब भी अमोनिया का स्तर बढ़ता है तो दिल्ली में जलशोधन संयंत्रों के संचालन पर असर पड़ता है। नए अध्ययन में नदी की तलहटी में जमा गाद को भी संभावित कारण के रूप में देखा जा रहा है।

दिल्ली जल बोर्ड के अनुसार उसके जलशोधन संयंत्र अधिकतम एक पीपीएम तक अमोनिया का शोधन करने में सक्षम हैं। जब पानी में अमोनिया का स्तर इससे अधिक हो जाता है तो वजीराबाद और चंद्रावल जलशोधन संयंत्रों के संचालन में परेशानी आने लगती है। इसके कारण राजधानी के कई इलाकों में पानी की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। अमोनिया की समस्या सामने आने पर जलशोधन प्रक्रिया को नियंत्रित करना पड़ता है। इसका सीधा असर पानी के उत्पादन और आपूर्ति पर पड़ता है। ऐसे में अध्ययन के अंतिम निष्कर्ष दिल्ली के लिए महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।

गोविंदपुरी कैब चालक हत्याकांड में पांच आरोपित गिरफ्तार

एजेंसी, नई दिल्ली

गोविंदपुरी थाना क्षेत्र में चार दिन पहले हुई कैब चालक राजू की हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपित किरण समेत पांच लोगों को पकड़ा है। पकड़े गए आरोपितों में एक नाबालिग भी शामिल है। हालांकि पुलिस की ओर से गिरफ्तारी की आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है।

पुलिस के अनुसार, 30 वर्षीय कैब चालक राजू की ईएसआईसी अस्पताल के सामने बस स्टाप के पीछे जंगल क्षेत्र में चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद पुलिस ने आरोपितों की तलाश शुरू की और जांच के दौरान कई संदिग्धों से पूछताछ की गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, मामले का मुख्य आरोपित किरण गोविंदपुरी थाना क्षेत्र के अलग-अलग इलाकों में स्मैक और अन्य नशीले पदार्थों की अवैध बिक्री से जुड़ा हुआ है।

निर्माण कार्य से आउटर रिंग रोड पर लगा जाम चार्जिंग केंद्रों ने बढ़ाई वाहन चालकों की परेशानी

एजेंसी, नई दिल्ली

व्यावसायिक वाहनों के लिए मार्ग बदलने पर भी विचार किया जा रहा है।

आउटर रिंग रोड पर कालकाजी फ्लाईओवर से मोदी मिल तक चल रहे निर्माण कार्य के कारण यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है। ओखला एनएसआईसी मेट्रो स्टेशन के सामने पिलर निर्माण के लिए सड़क के एक हिस्से में बैरिकेडिंग कर खोदाई की जा रही है। इससे सड़क की चौड़ाई कम हो गई है और नेहरू प्लेस से मोदी मिल की ओर जाने वाली लेन में वाहनों का दबाव लगातार बना रहता है। सुबह और शाम व्यस्त समय में जाम की स्थिति और गंभीर हो जाती है।

निर्माण स्थल के आसपास इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग और बैटरी बदलने के केंद्र भी बने हुए हैं। इन केंद्रों पर वाहन खड़े होने से सड़क पर उपलब्ध जगह और कम हो जाती है। चार्जिंग के दौरान वाहनों के रुकने से पीछे से आने वाले वाहनों को निकलने में परेशानी होती है और धीरे-धीरे वाहनों की लंबी कतार लग जाती है।

गलत दिशा में वाहन चलाने से भी परेशानी : यातायात प्रभावित होने की एक बड़ी वजह गलत दिशा में आने वाले वाहन भी हैं। मोदी मिल की ओर से ओखला फेज-3 जाने वाले कुछ वाहन चालक गलत दिशा से आते हैं। इसी तरह ओखला मंडी की ओर से कालकाजी जाने वाली लेन में भी कई वाहन विपरीत दिशा में दिखाई देते हैं। इससे सड़क पर आमने-सामने की स्थिति बनती है और दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है।

सड़क पहले ही निर्माण कार्य के कारण संकरी हो चुकी है। ऐसे में गलत दिशा से आने वाले वाहनों के कारण चालकों को अचानक ब्रेक लगाना पड़ता है। इसका असर पीछे चल रहे वाहनों पर भी पड़ता है और यातायात की रफ्तार धीमी हो जाती है।

यातायात पुलिस बढ़ाने की जरूरत : निर्माण स्थल के आसपास यातायात पुलिस की पर्याप्त तैनाती नहीं होने से भी समस्या बढ़ रही है। वाहन चालक अपनी सुविधा के अनुसार लेन बदलते हैं, जिससे यातायात व्यवस्था और उलझ जाती है। यातायात पुलिस के अनुसार गलत दिशा में चलने वाले वाहनों को रोकने के लिए कर्मी तैनात हैं। जरूरत के अनुसार कुछ स्थानों पर पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ाने की योजना है।

सीवर काम ने बढ़ाई मुश्किलें कमला मार्केट में जाम से लोग हुए बेहाल

एजेंसी, नई दिल्ली

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर पिछले कई महीनों से चल रहे सीवर लाइन बदलने के काम के कारण कमला मार्केट के व्यापारियों, राहगीरों और वाहन चालकों की परेशानी बढ़ गई है। सड़क की खुदाई और जगह-जगह बने गड्ढों के कारण यातायात बेहद धीमा हो गया है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन आने-जाने वाले यात्रियों के साथ अजमेरी गेट, खारी बावली और नया बाजार की ओर जाने वाले लोगों को भी जाम का सामना करना पड़ रहा है।

निर्माण कार्य के कारण सड़क का बड़ा हिस्सा घिर गया है, जिससे पैदल यात्रियों के लिए केवल एक संकरी पट्टी बची है। वाहन चालकों को भी सीमित जगह में निकलना पड़ रहा है। व्यस्त समय में यहां वाहनों की लंबी कतार लग जाती है।

गहरे गड्ढों से हादसे का खतरा : सीवर लाइन डालने के लिए करीब 10 फीट तक गहरी खुदाई की गई है। वर्षा के कारण कई जगह पानी और कीचड़ जमा होने से स्थिति और गंभीर हो गई है। निर्माण स्थल पर सुरक्षा इंतजाम पर्याप्त नहीं होने से हादसे का खतरा बना हुआ है। व्यापारियों ने कार्यस्थल पर मजबूत बैरिकेडिंग, पर्याप्त रोशनी और चेतावनी संकेत लगाने की मांग की है।

कमला मार्केट ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने लोक निर्माण विभाग को पत्र भेजकर काम में तेजी लाने और यातायात व्यवस्था सुधारने की मांग की है। एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र कपूर के अनुसार मुख्य सड़क का 100 मीटर से अधिक हिस्सा करीब तीन महीने से खुदा हुआ है। इससे धूल, जाम और आवाजाही में परेशानी के कारण बाजार में ग्राहकों की संख्या घट गई है और सैकड़ों व्यापारियों का कारोबार प्रभावित हो रहा है।

अगस्त अंत तक काम पूरा करने का लक्ष्य : व्यापारियों का कहना है कि जहां खुदाई पूरी हो चुकी है वहां भी मलबा हटाया नहीं गया है। इससे धूल उड़ने के साथ बारिश में जलभराव की समस्या बढ़ सकती है।

लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के अनुसार कई सड़कों के एक स्थान पर मिलने के कारण काम सावधानी से करना पड़ रहा है। बारिश और स्वतंत्रता दिवस की छुट्टियों के कारण भी काम की गति प्रभावित हुई। विभाग ने व्यापारियों की शिकायत मिलने की पुष्टि करते हुए कहा कि काम में तेजी लाई जा रही है। कमला मार्केट वाले हिस्से को अगस्त के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य है, जबकि पूरी परियोजना में करीब दो महीने और लग सकते हैं।

नकली कैंसर दवाओं के अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश, 17 आरोपी गिरफ्तार

कैंसर मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़, नौ करोड़ की नकली दवाएं हुई जब्त

एजेंसी, नई दिल्ली

आशंका है कि इस नेटवर्क के तार कई अन्य शहरों और लोगों से जुड़े हो सकते हैं।

दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली महंगी दवाओं के कथित अवैध कारोबार का बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने दिल्ली-एनसीआर, मुंबई, हैदराबाद और हरियाणा समेत कई क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए अब तक 17 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों पर नकली दवाएं तैयार करने, अस्पतालों से महंगी दवाएं चोरी करने और उन्हें बिना वैध बिल के बाजार में बेचने का आरोप है।

पुलिस के अनुसार आरोपितों के कब्जे से करीब नौ करोड़ रुपये कीमत की दवाएं बरामद की गई हैं। इनमें 588 भरी हुई शीशियां, छह खाली शीशियां, सात खाली डिब्बे और तीन हजार से अधिक अन्य दवाएं शामिल हैं। इसके अलावा 50 लाख रुपये नकद, पैकेजिंग सामग्री, रसायन, हिसाब-किताब से जुड़े रजिस्टर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी बरामद किए गए हैं।

विशेष पुलिस आयुक्त एचजीएस धालीवाल के मुताबिक 22 जून को अपराध शाखा की टीम को इस अवैध गिरोह के बारे में सूचना मिली थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए सहायक पुलिस आयुक्त रमेश लांबा की देखरेख में सात टीमों का गठन किया गया। इसके बाद पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर जांच और छापामारी की।

अस्पतालों से चोरी कर बेचते थे दवाएं : पुलिस की जांच में सामने आया कि गिरोह कथित तौर पर तीन तरीकों से दवाएं हासिल करता था। एक तरफ अनधिकृत स्रोतों से नकली दवाएं खरीदी जाती थीं, वहीं दूसरी ओर नामी अस्पतालों के कुछ कर्मचारियों और नर्सिंग स्टाफ की मदद से मरीजों की महंगी दवाएं चोरी की जाती थीं। इसके अलावा सरकारी संस्थानों और दवा भंडारों से मिलने वाली दवाओं की भी कथित तौर पर हेराफेरी की जाती थी।

आरोपित दवाओं की पहचान छिपाने के लिए रसायन का इस्तेमाल करते थे। पुलिस के अनुसार दवाओं की शीशियों और डिब्बों से असली बैच संख्या तथा अधिकतम खुदरा मूल्य हटाकर उन्हें दोबारा पैक किया जाता था। इसके बाद बिना वैध लाइसेंस और बिल के इन्हें विभिन्न राज्यों में भेजा जाता था।

कई शहरों में एक साथ कार्रवाई: 11 जुलाई को पुलिस ने औषधि विभाग और स्थानीय पुलिस के सहयोग से दिल्ली तथा नवी मुंबई में एक साथ कई ठिकानों पर छापामारी की। इस दौरान कैंसर के उपचार में इस्तेमाल होने वाली कई महंगी दवाएं जब्त की गईं। जांच में अलग-अलग शहरों में सक्रिय कथित बिचौलियों, थोक दवा कारोबारियों और अस्पताल कर्मचारियों की भूमिका सामने आई। पुलिस ने बताया कि एक आरोपित के ठिकाने से 337 कैंसर इंजेक्शन बरामद किए गए, जबकि एक अन्य आरोपित के घर से 55 शीशियां और दूसरे स्थान से 108 शीशियां मिलीं। कुछ आरोपितों के पास से लाखों रुपये की नकदी भी बरामद हुई।

वित्तीय लेन-देन की भी जांच : पुलिस अब गिरोह के वित्तीय लेन-देन, कथित फर्जी कंपनियों और दवाओं की आपूर्ति से जुड़े नेटवर्क की जांच कर रही है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि नकली और चोरी की दवाएं किन अस्पतालों, कारोबारियों और बाजारों तक पहुंचाई जाती थीं।

अपराध शाखा को आशंका है कि इस नेटवर्क के तार कई अन्य शहरों और लोगों से जुड़े हो सकते हैं। पुलिस गिरोह से जुड़े अन्य संदिग्धों की तलाश कर रही है। अधिकारियों के अनुसार जांच आगे बढ़ने पर और गिरफ्तारियां तथा बरामदगी हो सकती है।

चंपावत केवल विधानसभा क्षेत्र नहीं, कर्मभूमि है: सीएम धामी

चंपावत में ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट शुरू, स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगी नई मजबूती

भारतेंदु संवाददाता, चंपावत

जिला चिकित्सालय चंपावत में करीब 50 लाख रुपये की लागत से स्थापित ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट का गुरुवार को लोकार्पण करते हुए कहा कि यह सुविधा जिले में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि चंपावत उनके लिए केवल विधानसभा क्षेत्र नहीं, बल्कि कर्मभूमि है। जिले में पहली बार ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन की सुविधा उपलब्ध हुई है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि चंपावत उनके लिए केवल विधानसभा क्षेत्र नहीं, बल्कि कर्मभूमि है। जिले में पहली बार ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन की सुविधा उपलब्ध हुई है। इससे आपातकालीन परिस्थितियों में मरीजों को आवश्यक जीवनरक्षक रक्त घटक स्थानीय स्तर पर समय पर उपलब्ध हो सकेंगे। इससे पहले कुमाऊं मंडल के जिला चिकित्सालयों में यह सुविधा रुद्रपुर और पिथौरागढ़ में उपलब्ध थी।

उन्होंने कहा कि चंपावत को आदर्श जिला बनाने के संकल्प के तहत स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जिला चिकित्सालय में करीब 20 करोड़ रुपये की लागत से 50 बेड का अत्याधुनिक क्रिटिकल केयर ब्लॉक तैयार किया गया है। इसके अलावा सीटी स्कैन, एमआरआई और डायलिसिस यूनिट जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा चुकी हैं। करीब 11.71 करोड़ रुपये की लागत से पार्किंग, डायग्नोस्टिक विंग और ऑपरेशन थिएटर का निर्माण कार्य जारी है।

धामी ने कहा कि जिले में सड़क, पार्किंग, पेयजल और ड्रेनेज जैसी आधारभूत सुविधाओं को भी मजबूत किया जा रहा है। चंपावत रोडवेज स्टेशन पर 62 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से आधुनिक बहुमंजिला पार्किंग एवं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण प्रस्तावित है। वहीं 66 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से आधुनिक सिटी ड्रेनेज सिस्टम तथा 240 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से पेयजल व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है।

आपातकाल में मरीजों को स्थानीय स्तर पर मिलेंगे जीवनरक्षक रक्त घटक।

चंपावत बनेगा प्रदेश का आदर्श मॉडल

मुख्यमंत्री ने कहा कि साइंस सेंटर, महिला स्पोर्ट्स कॉलेज और आधुनिक आईएसबीटी जैसी परियोजनाएं जिले के विकास को नई दिशा देंगी। सरकार चंपावत को स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, रोजगार और आधारभूत सुविधाओं के क्षेत्र में उत्तराखंड का आदर्श मॉडल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक, सुलभ और जन-केंद्रित बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। जिला चिकित्सालय चंपावत में ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट की स्थापना से गंभीर एवं आपातकालीन परिस्थितियों में मरीजों को आवश्यक रक्त घटक स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो सकेंगे। इससे मरीजों को समय पर उपचार मिलने के साथ ही अन्य जिलों के अस्पतालों पर निर्भरता भी कम होगी।

दून में भारत-नेपाल सीमा प्रबंधन पर मंथन शुरू

अनिल थपलियाल

देहरादून में भारत और नेपाल के बीच सीमा प्रबंधन को प्रभावी बनाने के लिए 14वीं संयुक्त कार्य समूह की दो दिवसीय बैठक शुरू हो गई। 20 और 21 अगस्त को आयोजित इस बैठक में दोनों देशों के अधिकारी सीमा सुरक्षा, सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास और आपसी समन्वय को मजबूत करने सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव पौसुमी बसु कर रही हैं, जबकि नेपाली प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव आनंद काफ्ले कर रहे हैं। बैठक को दोनों देशों के बीच नियमित संवाद और सहयोग बढ़ाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। खुली और मैत्रीपूर्ण सीमा को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल और प्रभावी सीमा प्रबंधन पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

सत्यनिष्ठा से समझौता नहीं : उपराष्ट्रपति

उपराष्ट्रपति बोले- पद नहीं विरासत बने सफलता का पैमाना

अनिल थपलियाल

देहरादून में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में भारतीय वन सेवा के 2025-27 बैच के परिवीक्षार्थियों और प्रशिक्षण ले रहे रॉयल भूटान वन सेवा के अधिकारियों को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने राष्ट्रहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि लोक सेवा का मूल उद्देश्य राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करना है। उन्होंने प्रशिक्षु अधिकारियों को पर्यावरण संरक्षण, विकास और जनहित के बीच संतुलन बनाते हुए देश के सतत भविष्य के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए प्रेरित किया।

उपराष्ट्रपति ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए आने वाले दशकों में वन अधिकारियों के कंधों पर देश के वनों, वन्यजीवों, जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण एवं प्रबंधन की बड़ी जिम्मेदारी होगी। उन्होंने कहा कि भारत की पारिस्थितिक सुरक्षा को मजबूत करने और वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने में भारतीय वन सेवा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। वन केवल पर्यावरण के संरक्षण का माध्यम नहीं हैं बल्कि करोड़ों लोगों की आजीविका और देश की प्राकृतिक सुरक्षा से भी जुड़े हैं सी.पी. राधाकृष्णन ने कहा कि विकास और पर्यावरण संरक्षण को एक-दूसरे का विरोधी नहीं माना जाना चाहिए।

रक्षा में आईएफएस की भूमिका अहम

उन्होंने नई पीढ़ी के वन अधिकारियों से इन तकनीकों का उपयोग क्षेत्रीय अनुभव, विवेकपूर्ण निर्णय क्षमता और जनसंवेदनशीलता के साथ करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारत के सतत भविष्य के लिए आधुनिक वैज्ञानिक वानिकी और देश के पारंपरिक एवं सभ्यतागत ज्ञान को एक-दूसरे का पूरक बनाना होगा।

सामूहिक प्रयास ही मजबूत राष्ट्र की नींव तैयार करते हैं : उपराष्ट्रपति

उन्होंने प्रशिक्षु अधिकारियों से व्यक्तिगत उपलब्धियों के बजाय टीम की सफलता को प्राथमिकता देने की अपील की। उपराष्ट्रपति ने कहा कि निरंतर सामूहिक प्रयास ही मजबूत संस्थानों और मजबूत राष्ट्र की नींव तैयार करते हैं। लोक सेवा में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा को सर्वोच्च महत्व देते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी परिस्थिति में सत्यनिष्ठा से समझौता नहीं किया जा सकता। कठिन परिस्थितियों में अधिकारियों को संविधान, कानून, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और व्यापक जनहित को अपने निर्णयों का आधार बनाना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने आधुनिक तकनीक के बढ़ते महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि रिमोट सेंसिंग, भौगोलिक सूचना प्रणाली, ड्रोन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और आंकड़ा आधारित प्रणालियां वानिकी क्षेत्र को नई दिशा दे रही हैं।

आईआईटी रुड़की में राष्ट्रीय भवन निर्माण मानकों पर बीआईएस की कार्यशाला आयोजित

◆ एनबीसीएस 2026 के प्रभावी क्रियान्वयन पर बीआईएस और आईआईटी रुड़की ने बढ़ाया जोर

अनिल थपलियाल

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की में भारतीय मानक ब्यूरो के सहयोग से राष्ट्रीय भवन निर्माण मानक 2026 पर कार्यशाला आयोजित की गई। इसका उद्देश्य भवन निर्माण के नए राष्ट्रीय मानकों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और उनके प्रभावी क्रियान्वयन को मजबूत करना रहा। कार्यक्रम में बीआईएस, आईआईटी रुड़की और पेशेवर समुदाय के विशेषज्ञों ने सुरक्षित, मजबूत और गुणवत्तापूर्ण निर्माण पद्धतियों पर चर्चा की। बीआईएस के उप महानिदेशक संजय पंत ने अद्यतन मानकों को देशभर में प्रभावी ढंग से लागू करने की आवश्यकता पर जोर दिया। आईआईटी रुड़की के निदेशक प्रो. के.के. पंत ने सुरक्षित और सतत अवसंरचना के विकास में राष्ट्रीय मानकों की महत्वपूर्ण भूमिका बताई। कार्यशाला में एनबीसीएस 2026 के प्रमुख संशोधनों, अग्नि एवं जीवन सुरक्षा तथा मानकीकरण में शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका पर तकनीकी सत्र आयोजित हुए। इसके बाद खुले संवाद में छात्रों, शिक्षकों, शोधकर्ताओं और पेशेवरों ने विशेषज्ञों से सवाल पूछे तथा व्यावहारिक पहलुओं पर चर्चा की। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यशाला ने मानकों की समझ बढ़ाने और सुरक्षित भवन निर्माण को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

भटियाणा से देश के बाजारों तक पहुंची 'तपोवन' की खुशबू

◆ भटियाणा की नंदी देवी ने अगरबत्ती कारोबार से लिखी आत्मनिर्भरता की नई कहानी

उदित नैनवाल। चमोली के थराली विकासखंड की भटियाणा गांव निवासी नंदी देवी ने सीमित संसाधनों के बीच नवंबर 2020 में अगरबत्ती और धूपबत्ती निर्माण का काम शुरू किया। मेहनत, निरंतर प्रयास और उचित मार्गदर्शन से उनका छोटा प्रयास आज 'तपौवन' ब्रांड के रूप में कई बाजारों तक पहुंच चुका है। ग्रामोत्थान परियोजना, स्वयं सहायता समूह और आजीविका स्वायत्त सहकारिता से मिले सहयोग ने उनके कारोबार को विस्तार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2024 में उन्हें 75 हजार रुपये की वित्तीय सहायता मिली, जबकि व्यवसाय बढ़ाने के लिए उन्होंने 1.50 लाख रुपये का ऋण भी लिया। आज उनका कारोबार करीब एक लाख रुपये प्रतिमाह तक पहुंच चुका है। उनके उत्पाद चमोली के अलावा पौड़ी, देहरादून और ऋषिकेश समेत कई बाजारों में बिक रहे हैं। नंदी देवी के उद्यम से चार से पांच ग्रामीण महिलाओं को प्रत्यक्ष रोजगार भी मिल रहा है। अब उनका लक्ष्य 'तपौवन' को देश के अन्य बाजारों तक पहुंचाना है।

उत्तराखंड के विकास को लेकर महाराज ने केंद्र के सामने रखे प्रस्ताव

अनिल थपलियाल

उत्तराखंड के सिंचाई, लोक निर्माण, ग्रामीण निर्माण, पर्यटन, धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने नई दिल्ली में आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में प्रदेश की सड़क और बाढ़ सुरक्षा से जुड़े कई मुद्दे उठाए। परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय तथा जल शक्ति मंत्रालय की संयुक्त बैठक में प्रमुख नदियों में वैज्ञानिक तरीके से ड्रेजिंग और बाढ़ सुरक्षा के लिए संयुक्त कार्ययोजना पर चर्चा हुई। महाराज ने उत्तरकाशी से गंगोत्री के बीच करीब 100 किलोमीटर क्षेत्र को पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदनशील बताते हुए नदी तल में बोल्डर और मलबा जमा होने से जलस्तर बढ़ने तथा झील बनने की आशंका जताई।

◆ महाराज ने तिलवाड़ा-मायली-गुप्तकाशी मार्ग को दो लेन बनाने का उठाया मुद्दा

उन्होंने नदी किनारे स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग की ऊंचाई बढ़ाने का सुझाव दिया। हर्षिल के पास भी राजमार्ग के करीब 600 मीटर हिस्से को एक से डेढ़ मीटर ऊंचा करने की आवश्यकता बताई। उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पत्र सौंपकर प्रस्तावित रेल परियोजनाओं की सुरंगों को न्यूनतम दो लेन यातायात के लिए उपयोगी बनाने का अनुरोध किया।

ज्योतिष के राष्ट्रीय मंच पर चमका चमोली का सितारा

उदित नैनवाल। चमोली के ग्राम स्वर्का, लंगासू निवासी डॉ. प्रदीप मैखुरी ने राष्ट्रीय ज्योतिष कार्यशाला में मुख्य वक्ता के रूप में प्रतिभाग किया। उन्होंने 'मानव जीवन पर चंद्रमा का प्रभाव' विषय पर सारगर्भित व्याख्यान दिया। उन्होंने कहा कि ज्योतिषीय मान्यताओं में चंद्रमा को मन का कारक माना गया है। युवाओं को लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने और सकारात्मक सोच अपनाने का संदेश दिया। उनके विचारों की सराहना हुई।

न्यूज ब्रीफ

रुद्रप्रयाग पुलिस ने छात्रों को बताए नशे के दुष्प्रभाव और साइबर ठगी से बचने के उपाय

अनिल थपलियाल। रुद्रप्रयाग पुलिस ने राजकीय इंटर कॉलेज मनसूना में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर करीब 120 छात्र-छात्राओं को नशे के दुष्प्रभाव और साइबर अपराध से बचाव की जानकारी दी। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली ऊखीमठ मनोज नेगी ने विद्यार्थियों को सोशल मीडिया फ्रॉड, फर्जी लिंक, फिशिंग, ऑनलाइन गेमिंग और डिजिटल ठगी के खतरों से सावधान रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि किसी अनजान व्यक्ति से निजी जानकारी और ओटीपी साझा न करें। साथ ही नशे से होने वाले शारीरिक, मानसिक और कानूनी नुकसान बताए। छात्रों को साइबर सुरक्षा संबंधी पुस्तिकाएं भी वितरित की गईं। विद्यालय प्रबंधन ने पुलिस की पहल की सराहना की।

सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना समय की जरूरत: प्रेमचंद अग्रवाल

अनिल थपलियाल। भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस पर ऋषिकेश विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ. प्रेमचंद अग्रवाल ने अपने कैंप कार्यालय में ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े लोगों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि अक्षय ऊर्जा वर्तमान जरूरत के साथ आने वाली पीढ़ियों के स्वच्छ और सुरक्षित भविष्य की आधारशिला है। सौर ऊर्जा समेत अन्य अक्षय स्रोतों को बढ़ावा देकर पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा जरूरतों की पूर्ति साथ-साथ की जा सकती है। कार्यक्रम में संदीप सुरियाल, आशीष भारद्वाज और राहुल भारद्वाज को सम्मानित किया गया। इस दौरान चंद्र मोहन पोखरियाल, रविंद्र रमोला और अरविंद चौधरी समेत अन्य लोग मौजूद रहे।

देहरादून में दिनदहाड़े फायरिंग से हड़कंप छात्र को लगी गोली

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून। देहरादून के पटेलनगर इंडस्ट्री एरिया में एक निजी संस्थान के बाहर दिनदहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि बाइक सवार युवकों और कार सवार युवकों के बीच विवाद के बाद गोलियां चलाई गईं। फायरिंग में साहिल नामक युवक के कंधे पर गोली लग गई। घायल को महंत इंदिरेश अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। बताया गया कि दोनों पक्ष हरियाणा के रहने वाले हैं। विवाद के दौरान बाइक सवारों ने कार का पीछा किया और सेंट ज्यूड्स चौक तक पहुंचे। इसी दौरान दोबारा फायरिंग हुई। पुलिस आरोपितों की तलाश में जुटी है।

उत्तराखंड में 15 हजार परिवारों का घर का सपना होगा पूरा

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 15 हजार से अधिक परिवारों को जल्द पक्की छत मिलने जा रही है। आवास विभाग ने लंबित आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 30 सितंबर की समय सीमा तय की है। प्रदेश में कुल 18 परियोजनाओं के तहत 15496 आवासीय इकाइयों का निर्माण किया जा रहा है। इनमें 12948 यानी करीब 84 प्रतिशत आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है। अब तक 1271 आवासों की चाबियां लाभार्थियों को सौंपी जा चुकी हैं। इनमें 768 लाभार्थी रुड़की और 503 हरिद्वार के हैं। सबसे अधिक 10200 आवास ऊधमसिंह नगर जिले में बनाए जा रहे हैं। हरिद्वार में 4528, नैनीताल में 528 और देहरादून में 240 आवास निर्माणाधीन हैं। विभाग ने शेष कार्य तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। सभी पात्र परिवारों को दिसंबर तक घर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य सरकार ने योजना में अपनी हिस्सेदारी भी 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार रुपये करने का निर्णय लिया है।

गोपेश्वर में पीआईबी की क्षेत्रीय मीडिया कार्यशाला 'वार्तालाप' आयोजित

'वार्तालाप' में पत्रकारों ने योजनाओं के क्रियान्वयन पर उठाए सवाल

उदित नैनवाल

गोपेश्वर में पत्र सूचना कार्यालय, देहरादून की ओर से जिला पंचायत सभागार में क्षेत्रीय मीडिया कार्यशाला 'वार्तालाप' का आयोजन किया गया। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं, विकासपरक पहलों और जनहितकारी कार्यक्रमों की जानकारी मीडिया प्रतिनिधियों तक पहुंचाने के साथ इनके प्रभावी प्रचार-प्रसार में मीडिया की भूमिका पर सार्थक संवाद स्थापित करना था। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष दौलत सिंह बिष्ट, नगर पालिका अध्यक्ष संदीप रावत, जिलाधिकारी गौरव कुमार और पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पंवार सहित विभिन्न अधिकारी एवं पत्रकार मौजूद रहे।

जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक तभी पहुंच सकता है, जब पात्र लोगों को उनकी सही और समयबद्ध जानकारी मिले। उन्होंने स्थानीय मीडिया को ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में जागरूकता बढ़ाने का महत्वपूर्ण माध्यम बताया। जिलाधिकारी गौरव कुमार ने कहा कि योजनाओं की जानकारी जिला मुख्यालय तक सीमित न रहकर ब्लॉक और ग्राम स्तर तक पहुंचनी चाहिए।

कार्यशाला में आयुष्मान भारत, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, महिला स्वयं सहायता समूह, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, नशा मुक्त भारत अभियान, जीआई टैगिंग और एक जिला एक उत्पाद जैसी योजनाओं की जानकारी दी गई। विशेषज्ञों ने योजनाओं की पात्रता, लाभ, आवेदन प्रक्रिया और क्रियान्वयन की जानकारी साझा की तथा पत्रकारों के सवालों का समाधान किया। इस दौरान मीडिया और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय तथा तथ्यपरक पत्रकारिता को मजबूत बनाने पर भी जोर दिया गया।

◆ दूरस्थ क्षेत्रों तक योजनाओं की जानकारी पहुंचाएगा स्थानीय मीडिया

थराली पुलिस की लगातार तलाश से गुमशुदा युवती बरामद

उदित नैनवाल

थराली पुलिस ने लंबे समय से गुमशुदा युवती को लगातार खोजबीन, सुरागरसी और पतारसी के बाद सकुशल बरामद कर लिया। युवती के परिजनों ने उसके बिना बताए घर से चले जाने के बाद गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस टीम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए लगातार युवती की तलाश जारी रखी और अथक प्रयासों के बाद उसे बरामद किया। पूछताछ में युवती ने बताया कि वह अपनी इच्छा से घर से गई थी और बाद में अपनी मर्जी से विवाह कर लिया। उसका एक बच्चा भी है। न्यायालय में बयान के दौरान उसने पति के साथ रहने की इच्छा जताई। इसके बाद उसे उसकी स्वतंत्र इच्छा के अनुसार पति के सुपुर्द कर दिया गया।

फील्ड में जाकर जमीनी हकीकत समझें अधिकारी : राज्यपाल

अनिल थपलियाल

देहरादून में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में आईएएस 2024 बैच के अधिकारी प्रशिक्षुओं को संबोधित किया। उन्होंने प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने पर सभी प्रशिक्षुओं को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल और राष्ट्रसेवा को समर्पित सेवाकाल की शुभकामनाएं दीं। राज्यपाल ने कहा कि अकादमी में प्रशिक्षण का एक अध्याय पूरा हुआ है, लेकिन राष्ट्रसेवा की वास्तविक यात्रा अब शुरू हो रही है।

◆ कहा- प्रशासन की असली परीक्षा चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में होती है, अधिकारी विवेक से लें निर्णय

उन्होंने कहा कि प्रशासन की असली परीक्षा चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में होती है। ऐसे समय में नियम और अनुभव के साथ विवेक, निष्पक्षता और दूरदृष्टि भी जरूरी होती है। विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए अधिकारियों को नीतियों के साथ जमीनी वास्तविकताओं और नागरिकों की आकांक्षाओं को समझना होगा।

राज्यपाल ने प्रशिक्षुओं से गांवों, कस्बों और शहरों में जाकर लोगों की समस्याओं को समझने तथा उनकी बात ध्यान से सुनने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि फाइलें तथ्य उपलब्ध कराती हैं, लेकिन फील्ड वास्तविक स्थिति से परिचित कराता है। प्रशासन का पहला धर्म जनता की बात सुनना और उसका विश्वास बनाए रखना है। उन्होंने अधिकारियों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आंकड़ा विज्ञान और नई तकनीकों को अपनाने की सलाह दी। राज्यपाल ने कहा कि अधिकारी पारदर्शिता, संवेदनशीलता और दृढ़ता के साथ कार्य करें तथा हर परिस्थिति में राष्ट्र को सर्वोपरि रखें।

नारायणबगड़ में 20 से अधिक कुत्तों को एआरवी वैक्सीन

उदित नैनवाल। नारायणबगड़ में आवारा और आक्रामक कुत्तों द्वारा लोगों को काटे जाने की घटनाओं के बाद प्रशासन ने रेस्क्यू और वैक्सीनेशन अभियान तेज कर दिया है। जिलाधिकारी गौरव कुमार के निर्देश पर पशुपालन, राजस्व, वन, पुलिस, जिला पंचायत और डीडीआरएफ की टीमें संयुक्त रूप से काम कर रही हैं। अब तक 20 से अधिक कुत्तों को एआरवी वैक्सीन लगाया जा चुका है। दो वैक्सीनेशन एवं राहत शिविर संचालित हैं। घर-घर जाकर पशुओं का भी टीकाकरण किया जा रहा है।

जवाबदेही उत्तराखंड में मतदाता सूचियों की जांच को लेकर सियासत तेज, भाजपा ने कांग्रेस पर साधा निशाना

एसआईआर पर सियासत कर रही कांग्रेस : तरुण बंसल

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून

भारतीय जनता पार्टी ने विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए इसे राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाया है। भाजपा प्रदेश महामंत्री तरुण बंसल ने कहा कि एसआईआर निर्वाचन प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसका उद्देश्य मतदाता सूचियों को अधिक पारदर्शी, सही और अद्यतन बनाना है। उनके अनुसार कांग्रेस द्वारा भाजपा पर फर्जी आपत्तियां लगवाने का आरोप निराधार है। जांच की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि कौन-सी आपत्तियां सही हैं और कौन-सी गलत।

मतदाता सूची किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की बुनियाद होती है। चुनाव में प्रत्येक पात्र नागरिक को मतदान का अधिकार मिले और अपात्र या दोहरे नाम सूची में शामिल न रहें, यह निष्पक्ष चुनाव के लिए आवश्यक है। ऐसे में मतदाता सूचियों का समय-समय पर पुनरीक्षण केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने का माध्यम भी है। राजनीतिक दलों को इस प्रक्रिया को संदेह की नजर से देखने के बजाय तथ्यों के आधार पर अपनी बात रखनी चाहिए।

◆ दोहरे मतदाता नामों की जांच से लेकर वोट बैंक की राजनीति तक, एसआईआर पर बढ़ा सियासी विवाद

भाजपा नेता ने उत्तराखंड से लगे उत्तर प्रदेश के जिलों की मतदाता सूचियों में दर्ज ऐसे नामों का मुद्दा उठाया, जो कथित तौर पर उत्तराखंड की मतदाता सूचियों में भी शामिल हैं। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और वहां यदि दोहरे नामों की पहचान हुई है तो उत्तराखंड में भी ऐसे मामलों की गंभीरता से जांच होनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति का नाम दो अलग-अलग राज्यों की मतदाता सूचियों में दर्ज है तो निर्वाचन अधिकारियों को नियमानुसार इसकी जांच कर वास्तविक स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। भाजपा की ओर से दावा किया गया है कि हरिद्वार, नैनीताल, ऊधम सिंह नगर, देहरादून और पौड़ी गढ़वाल जिलों में निर्वाचन अधिकारियों की जांच के दौरान ऐसे हजारों नाम सामने आए हैं, जो कथित रूप से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों की मतदाता सूचियों में दर्ज हैं।

लोकतंत्र की मजबूती के लिए शुद्ध मतदाता सूची जरूरी

एसआईआर को लेकर राजनीतिक दलों के बीच मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन इस प्रक्रिया को लेकर समाज में अनावश्यक भ्रम पैदा नहीं होना चाहिए। निर्वाचन अधिकारियों को स्वतंत्र रूप से जांच करने का अवसर मिलना चाहिए और राजनीतिक दलों को भी यदि कोई वास्तविक आपत्ति है तो उसे प्रमाणों के साथ संबंधित अधिकारियों के सामने रखना चाहिए।

भाजपा ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि उसने ऐसे मामलों को लेकर प्रशासन या निर्वाचन अधिकारियों को ज्ञापन नहीं दिया। पार्टी का कहना है कि कांग्रेस एसआईआर से जुड़े मुद्दे को एक वर्ग विशेष की सहानुभूति हासिल करने के लिए राजनीतिक विषय बना रही है। इसके विपरीत कांग्रेस का पक्ष यह रहा है कि मतदाता पुनरीक्षण की प्रक्रिया में वास्तविक मतदाताओं के अधिकार प्रभावित नहीं होने चाहिए। ऐसे में पूरे विवाद को राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से आगे ले जाकर तथ्यों और नियमों के आधार पर देखने की आवश्यकता है।

न्यूज ब्रीफ

विधायक त्रिलोक जम्वाल ने आईटीआई में 3 शिफ्ट का फैसला बताया तुगलकी फरमान

अमर सिंह ठाकुर, भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। सदर विधायक त्रिलोक जम्वाल ने प्रदेश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में लागू की गई तीन-शिफ्ट व्यवस्था को लेकर प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने इस निर्णय को अव्यावहारिक बताते हुए इसे तत्काल वापस लेने की मांग की है। विधायक ने कहा कि तकनीकी शिक्षा विभाग के नए प्रोस्पेक्टस के अनुसार आईटीआई सुबह 7:30 बजे से रात 8:30 बजे तक तीन शिफ्टों में संचालित किए जाएंगे, जो विद्यार्थियों और कर्मचारियों के हित में नहीं है। जमवाल ने कहा कि ग्रामीण व दूरदराज क्षेत्रों से आने वाले विद्यार्थियों के लिए परिवहन सुविधा पहले ही सीमित है। कई एचआरटीसी रूट बंद होने के कारण सुबह जल्दी संस्थान पहुंचना और रात को घर लौटना, विशेषकर छात्राओं के लिए, सुरक्षा की दृष्टि से गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि पर्याप्त स्टाफ और बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था किए बिना शिफ्ट व्यवस्था लागू करना उचित नहीं है। विधायक ने बिलासपुर गर्ल्स आईटीआई बंद किए जाने का मुद्दा उठाते हुए आशंका जताई कि नई व्यवस्था से छात्र संख्या घट सकती है और भविष्य में अन्य सरकारी आईटीआई भी बंद करने का रास्ता तैयार किया जा सकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि सरकार ने फैसला वापस नहीं लिया तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।

बिलासपुर जिले में बरसात से अब तक 46.17 करोड़ रुपए का नुकसान: उपायुक्त

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार ने कहा कि जिला में बरसात के कारण अब तक करीब 46.17 करोड़ रुपये का नुकसान आंका गया है। उन्होंने बताया कि सबसे अधिक क्षति लोक निर्माण विभाग को हुई है, जिसका नुकसान करीब 41 करोड़ रुपये आंका गया है। इसके अलावा जलशक्ति विभाग को लगभग 5 करोड़ रुपये, स्कूल शिक्षा विभाग को करीब 50 लाख रुपये, पशुपालन विभाग को 3 लाख रुपये तथा विद्युत बोर्ड को लगभग 5 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। उपायुक्त ने संबंधित विभागों को क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संपत्तियों का आकलन एवं आवश्यक मरम्मत कार्य प्राथमिकता के आधार पर करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बरसात के दौरान प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

पनारसा स्कूल में वैज्ञानिक चेतना पर मंथन पर्यावरणीय चुनौतियों पर हुई संगोष्ठी

भगत सिंह गुलेरिया, भारतेन्दु संवाददाता, मंडी। पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पनारसा में हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति एवं तकनीकी विकास समिति के संयुक्त तत्वावधान में 'पर्यावरणीय चुनौतियों के संदर्भ में वैज्ञानिक चेतना' विषय पर कार्यशाला एवं संगोष्ठी आयोजित की गई। इसमें छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों ने भाग लिया। समिति के जिला अध्यक्ष नवल किशोर शर्मा ने बताया कि संगठन वर्ष 1992 से शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और महिला-पुरुष समानता जैसे मुद्दों पर कार्य कर रहा है। समिति द्वारा पॉलीथिन हटाओ, बेटी बचाओ, खेती बचाओ और युवा बचाओ अभियान चलाए जा रहे हैं। सचिव गजेंद्र शर्मा ने युवाओं से नशे और गलत संगति से दूर रहने का आह्वान किया। तकनीकी विकास समिति के अध्यक्ष डॉ. विजय विशाल ने डॉ. नरेंद्र दाभोलकर के वैज्ञानिक चेतना के लिए किए योगदान पर प्रकाश डाला। जोगिंद्र वालिया ने कहा कि बढ़ता तापमान और अनियमित वर्षा हिमाचल के लिए गंभीर पर्यावरणीय चुनौती है। विद्यालय की प्रभारी रजनी शर्मा और प्रवक्ता दुर्गा सिंह ठाकुर ने भी विचार रखे।

शिलाई के बांदली-ढाढस मार्ग पर दर्दनाक सड़क हादसा, 35 वर्षीय युवक की मौत

भारतेन्दु संवाददाता, नाहन। शिलाई उपमंडल के बांदली-ढाढस क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में 35 वर्षीय युवक की अकाल मृत्यु का दुखद मामला सामने आया है। पेशे से टैक्सी चालक, ढाढस गांव के रहने वाले प्रदीप बीरसांटा पुत्र रतन सिंह वीरवार बीती देर रात अपनी बोलेरो गाड़ी से घर लौट रहे थे। उसी दौरान बांदली-ढाढस मार्ग पर उनका वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसा इतना भीषण था कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना देर रात की होने के कारण हादसे का तुरंत पता नहीं चल सका। शुक्रवार सुबह जब स्थानीय लोगों की नजर दुर्घटनाग्रस्त बोलेरो गाड़ी पर पड़ी, तो उन्होंने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और घटना से जुड़ी आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। परिश्रमी टैक्सी चालक प्रदीप के असमय निधन की खबर सामने आते ही पूरे शिलाई उपमंडल और ढाढस गांव में गहरा शोक छा गया है। महज 35 वर्ष की अल्पायु में हुए इस हादसे ने परिजनों और स्थानीय ग्रामीणों को झकझोर कर रख दिया है। मृतक अपने पीछे एक छोटा बच्चा और गर्भवती पत्नी को छोड़ गए हैं, जिससे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।

सीएम के पैकेज ने फिर खड़े कर दिए आपदा में ध्वस्त हुए मकान

आपदा राहत पैकेज से भोरंज के भ्याड़ गांव के करतार का मकान भी हो गया तैयार

अनिल कुमार, भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। प्रदेश में वर्ष 2023 और 2025 के दौरान कहर बरपाकर गई बरसात के गहरे जख्मों पर मरहम लगाने और पूरी तरह उजड़ चुके परिवारों को फिर से बसाने के लिए मुख्यमंत्री ने बेहद कठिन आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद विशेष आपदा राहत पैकेज जारी करके पूरे देश में एक अनुकर्णीय उदाहरण प्रस्तुत किया था और इसी पैकेज के कारण आज प्रदेश के हजारों परिवार न केवल आपदा से उबर चुके हैं, बल्कि उनके आशियाने भी फिर से बनकर तैयार हुए हैं।

वर्ष 2025 की बरसात जिला हमीरपुर के भोरंज उपमंडल के गांव भ्याड़ के करतार चंद के परिवार के लिए भी एक ऐसी भीषण आपदा लेकर आई कि पूरे परिवार को घनघोर अंधेरी रात में भारी बारिश के बीच जैसे-तैसे भागकर जान बचानी पड़ी और किसी दूसरे के घर में शरण लेनी पड़ी। सुबह लौटकर आए तो देखा कि मकान मलबे के ढेर में तबदील हो चुका था। मलबे के ढेर से थोड़ा-बहुत सामान निकालने के बाद करतार चंद और उनके परिजनों को रहने के लिए छत की तलाश थी। दिहाड़ी-मजदूरी से अपनी पत्नी, बेटे और बेटी का पालन-पोषण करने वाले करतार चंद को पुनर्वास की कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही थी।

ऐसे हालात में प्रदेश सरकार का विशेष आपदा राहत पैकेज करतार चंद के परिवार के लिए बहुत बड़ा सहारा साबित हुआ। इस पैकेज के तहत करतार चंद को न केवल फौरी राहत राशि और आवश्यक सामान मिला, बल्कि परिवार को किराये के मकान में रहने के लिए भी अलग से राशि मिली। इसके बाद मकान के पुनर्निर्माण के लिए भी सात लाख रुपये की राशि मंजूर हो गई। इस पैकेज की चार लाख रुपये की पहली किश्त और अपनी मेहनत की कमाई से करतार चंद ने मकान का निर्माण शुरू किया। कुछ महीनों में ही उनका मकान का ढांचा खड़ा हो गया। अब फीनिशिंग का कार्य चल रहा है।

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू का बार-बार आभार व्यक्त करते हुए करतार चंद ने बताया कि अगर विशेष आपदा राहत पैकेज न होता तो उनके परिवार की न जाने क्या हालत होती? करतार चंद की बेटी सीमा देवी ने बताया कि आपदा के उस बुरे वक्त की याद करते हुए वे आज भी सिहर उठते हैं। लेकिन, विशेष आपदा राहत पैकेज के कारण आज उनके मकान का पुनर्निर्माण संभव हुआ है और उन्हें छत नसीब हुई है।

ई-ऑफिस के इस्तेमाल में पूरे प्रदेश में बिलासपुर नंबर-वन

अमर सिंह ठाकुर, भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। उपायुक्त कार्यालय बिलासपुर ने ई-ऑफिस के प्रभावी एवं व्यापक उपयोग में प्रदेशभर में प्रथम स्थान हासिल किया है। ई-ऑफिस उपयोग के आंकड़ों के अनुसार उपायुक्त कार्यालय बिलासपुर में कुल 1,96,784 ई-ऑफिस गतिविधियां दर्ज की गईं, जिसके आधार पर बिलासपुर को प्रदेश के सभी जिला उपायुक्त कार्यालयों में ओवरऑल रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।

उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार इस अवधि में डीसी ऑफिस बिलासपुर में 148 ई-फाइलें बनाई गईं, जबकि 3,876 ई-फाइलें मूव की गईं। इसी अवधि में 1,545 ई-रसीदें बनाई गईं तथा 1,91,215 ई-रसीदें मूव की गईं। इस प्रकार कुल ई-ऑफिस गतिविधियों की संख्या 1,96,784 रही। ई-ऑफिस के उपयोग के मामले में बिलासपुर ने अन्य जिलों की तुलना में उल्लेखनीय बढ़त दर्ज की है। प्रदेश में डीसी ऑफिस शिमला 1,17,984 गतिविधियों के साथ दूसरे, डीसी ऑफिस मंडी 1,11,822 के साथ तीसरे, डीसी ऑफिस चंबा 59,522 के साथ चौथे तथा डीसी ऑफिस हमीरपुर 24,180 गतिविधियों के साथ पांचवें स्थान पर रहा। ई-ऑफिस प्रणाली के माध्यम से सरकारी कार्यालयों में फाइलों और पत्राचार की प्रक्रिया को अधिक तेज, पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने में सहायता मिल रही है। डिजिटल माध्यम से फाइलों एवं ई-रसीदों की आवाजाही से कार्यों की निगरानी, समयबद्ध निस्तारण तथा कार्यालयी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता को बढ़ावा मिलता है।

उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा ई-ऑफिस के प्रभावी उपयोग पर विशेष जोर दिया जा रहा है। उपलब्ध आंकड़ों में प्रथम स्थान प्राप्त करना जिला प्रशासन द्वारा डिजिटल कार्यप्रणाली को अपनाने तथा कार्यालयी कार्यों को अधिक दक्ष एवं पारदर्शी बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को दर्शाता है।

आल्टो कार का टायर चोरी करने वाला आरोपी टायर के साथ किया गिरफ्तार

अमर सिंह ठाकुर, भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। बिलासपुर के थाना सदर में आल्टो कार से ड्राइवर साइड का अगला टायर चोरी होने की शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। मामले की तफ्तीश के दौरान पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों को खंगाला।

जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपी शुभम पुत्र तेलू राम, निवासी पहलवामा, डाकघर रानीकोटला, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, उम्र 28 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चोरी किया गया टायर भी बरामद कर लिया है। पुलिस के अनुसार मामले में आगामी तफ्तीश जारी है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है तथा यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि कहीं उसका संबंध क्षेत्र में हुई अन्य संभावित चोरियों से तो नहीं है। पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

◆ **सीसीटीवी फुटेज से खुला टायर चोरी का राज**

मंडी को फोरलेन से जोड़ने वाला सड़क मार्ग होगा चकाचक

भगत सिंह गुलेरिया, भारतेन्दु संवाददाता, मंडी। मंडी शहर को फोरलेन (मलोरी टनल) से जोड़ने वाली सड़क के चौड़ीकरण, मेटलिंग और टारिंग के किए केंद्रीय सड़क और बुनियादी ढाँचा कोष (सीआरआईएफ) के अंतर्गत 6.50 करोड़ राशि की डीपीआर राज्य सरकार के माध्यम से सदर विधायक अनिल शर्मा द्वारा केंद्रीय मंत्री को सौंपी गई। जिस पर केंद्रीय मंत्री ने गंभीरता पूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया है।

ज्ञात रहे यही एक मात्र सड़क है जो फोर लेन से सीधा मंडी शहर को जोड़ती है। इस के लिए सदर विधायक ने राज्य सरकार से भी गुहार लगाई थी।अब केंद्र सरकार के माध्यम से इस सड़क के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध होने की उम्मीद जगी है, जिससे मंडी शहर से फोरलेन तक का सफर सुविधाजनक और सुगम होगा।

मंडी-कोटली सड़क की समस्याओं को लेकर नितिन गडकरी से मिले विधायक अनिल शर्मा

भगत सिंह गुलेरिया, भारतेन्दु संवाददाता, मंडी। सदर विधायक अनिल शर्मा ने दिल्ली में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर राष्ट्रीय राजमार्ग-003 के मंडी-कोटली/कडकोह खंड में चल रहे निर्माण कार्यों को लेकर विस्तार से चर्चा की। विधायक ने केंद्रीय मंत्री को निर्माण कार्यों की मौजूदा स्थिति से अवगत करवाते हुए कहा कि कई काम अभी अधूरे हैं। निर्माण की गुणवत्ता और कार्यान्वयन के तरीके के कारण स्थानीय लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।

विधायक ने मार्ग पर कई तीखे एवं खतरनाक मोड़ों के सुधार, अपर्याप्त जल निकासी व्यवस्था, संवेदनशील स्थानों पर रिटेनिंग व ब्रेस्ट वॉल का निर्माण न होने तथा प्रभावित घरों और संपत्तियों तक उचित संपर्क मार्ग नहीं होने का मुद्दा उठाया। इसके अलावा सड़क सुरक्षा के अपर्याप्त इंतजाम और प्रस्तावित बस शेल्टरों का निर्माण न होने की समस्या भी केंद्रीय मंत्री के समक्ष रखी। उन्होंने कहा कि ये समस्याएं लोगों की सुरक्षा और दैनिक आवागमन से सीधे जुड़ी हैं, इसलिए इनका समयबद्ध समाधान जरूरी है।

सड़क निर्माण के लिए 70 करोड़ की अतिरिक्त राशि जारी

विधायक अनिल शर्मा ने मंडी-कोटली खंड का निर्माण पूरा करने के लिए 70 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि जारी करने का अनुरोध किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस राशि को तत्काल जारी करने की बात कही। उन्होंने विधायक द्वारा उठाए गए सभी विषयों को धैर्यपूर्वक सुना और प्रभावित लोगों की समस्याओं की जांच करवाकर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया।

वंदे मातरम के पूर्ण गायन से कांग्रेस का इनकार राष्ट्र और संविधान का अपमान: अनुराग ठाकुर

अनिल कुमार, भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। कांग्रेस वर्किंग कमेटी द्वारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के पूर्ण गायन से परहेज करने के निर्णय पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस का यह फैसला पूरी तरह राष्ट्रविरोधी, संविधान विरोधी और संसद विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। तुष्टिकरण की राजनीति में डूबी कांग्रेस अब राष्ट्रीय गीत के सम्मान को भी राजनीतिक चश्मे से देखने लगी है।

अनुराग ठाकुर ने कहा कि वंदे मातरम् केवल एक गीत नहीं, बल्कि भारत की स्वतंत्रता, राष्ट्रभक्ति और करोड़ों देशवासियों की भावनाओं का प्रतीक है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इसी वंदे मातरम ने देशवासियों में राष्ट्रभावना और स्वाधीनता की चेतना जगाने का काम किया था। ऐसे राष्ट्रीय गीत के पूर्ण गायन से कांग्रेस का परहेज करना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और गांधी परिवार की तुष्टिकरण की राजनीति इतनी हावी हो चुकी है कि वे 140 करोड़ भारतीयों की भावनाओं और वंदे मातरम् के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी के योगदान का बार-बार अपमान करने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस को यह समझना चाहिए कि राष्ट्र के सम्मान और राष्ट्रीय प्रतीकों के साथ राजनीति नहीं की जा सकती। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस आज संविधान की दुहाई देती है, लेकिन उसे यह भी याद रखना चाहिए कि संविधान की मूल भावना राष्ट्र की एकता, अखंडता और नागरिकों में राष्ट्रीय चेतना को मजबूत करने की है। संसद में राष्ट्रीय गीत के सम्मान और उसके ऐतिहासिक महत्व को लेकर देश की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए, न कि वोट बैंक की राजनीति के लिए उसमें विभाजनकारी दृष्टिकोण तलाशा जाए। उन्होंने कहा कि जिस कांग्रेस ने सत्ता की राजनीति के लिए देश का विभाजन स्वीकार किया, आज उसके नेताओं और गांधी परिवार के ऐसे निर्णय यह सवाल खड़ा करते हैं कि आखिर कांग्रेस के आज के मंसूबे क्या हैं? क्या तुष्टिकरण के लिए कांग्रेस फिर से देश की एकता और राष्ट्रीय भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना चाहती है?

अनुराग ने कहा कि देश की जनता कांग्रेस की इस राजनीति को भली-भांति समझ चुकी है। वंदे मातरम् का सम्मान किसी दल, जाति या धर्म का विषय नहीं, बल्कि भारत माता और 140 करोड़ देशवासियों के सम्मान का विषय है। कांग्रेस को अपनी राजनीतिक मजबूरियों से ऊपर उठकर राष्ट्रहित और राष्ट्रीय भावनाओं का सम्मान करना चाहिए।

वोट विकास के दम पर मांगे, पैसे से नहीं: काकू

आशीष दमीर, भारतेन्दु संवाददाता, कांगड़ा। पूर्व मुख्य संसदीय सचिव एवं पूर्व विधायक चौधरी सुरेंद्र काकू ने कहा कि उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में कभी पैसे देकर वोट नहीं खरीदा, बल्कि जनता की सेवा और विकास के दम पर विश्वास अर्जित किया है। वह अपने कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र के दूसरे चरण के विकास संपर्क अभियान के तहत गांव अपर कोहाला पहुंचे। यहां उन्होंने महिला शक्ति नैना महिला मंडल की महिलाओं से मुलाकात की। इस दौरान ग्रामीणों, महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं ने उनका जोरदार स्वागत किया और अपनी समस्याएं एवं मांगे उनके समक्ष रखीं। काकू ने सभी मांगों को प्राथमिकता से पूरा करने का आश्वासन दिया।

कोहाला गांव में किए गए विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में क्षेत्र का नक्शा बदला है। बरसात के दौरान 25 लाख रुपये की लागत से कोहाला में पुल का निर्माण करवाया गया। नागनी माता मंदिर तक जाने वाली सड़क के लिए 50 लाख रुपये स्वीकृत करवाए। खोपू गांव की सड़क का निर्माण कार्य प्रगति पर है। सुरेंद्र काकू ने कहा कि कुछ हैंडपंप छूट गए थे, अब विरोधी लोग उन पर मोटर लगाकर राजनीति कर रहे हैं। जनता से आग्रह है कि वह ऐसे लोगों से सजग रहें। महिलाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सीएम सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। हर महिला को 1500 रुपये सम्मान राशि दी जाएगी।

सोलग जुरासी स्कूल से गैस सिलेंडर और डीवीआर चोरी

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। जिला बिलासपुर के राजकीय उच्च पाठशाला सोलग जुरासी में चोरी और तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। 20 अगस्त की सुबह स्कूल पहुंचे कर्मचारियों ने रसोईघर और मुख्याध्यापक कक्ष के दरवाजों के ताले टूटे हुए पाए। कमरों के अंदर सामान भी बिखरा पड़ा था। निरीक्षण करने पर रसोईघर से भरे हुए दो गैस सिलेंडर, एक इंडक्शन और सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर चोरी होने का पता चला। चोरों ने विद्युत व्यवस्था और कैमरों के तारों से भी छेड़छाड़ की।

घटना की सूचना राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला धार टटोह के प्रधानाचार्य डीडी सिमर को दी गई। प्रधानाचार्य ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और पुलिस व शिक्षा विभाग को जानकारी दी। स्कूल मुख्याध्यापक ने पंचायत, एसएमसी और पुलिस को भी मामले से अवगत करवाया है। गैस सिलेंडर चोरी होने से विद्यार्थियों के लिए मिड-डे मील तैयार करने में परेशानी आने की आशंका है।

स्कूल प्रबंधन ने रात को चौकीदार तैनात करने की उठाई मांग

स्कूल प्रबंधन ने शिक्षा विभाग से क्षतिग्रस्त दरवाजों, विद्युत व्यवस्था और सीसीटीवी सिस्टम को जल्द दुरुस्त करवाने की मांग की है। साथ ही चोरी हुए गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाने का आग्रह किया है, ताकि मिड-डे मील व्यवस्था प्रभावित न हो। प्रबंधन ने भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए स्कूल में रात के समय चौकीदार तैनात करने की भी मांग की है। प्रबंधन का कहना है कि रात्रि चौकीदार की व्यवस्था से स्कूल की संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सकेगा।

उपायुक्त ने की राजस्व मामलों की समीक्षा 3,615 इंतकाल सहित 919 मामले निपटाए

भगत सिंह गुलेरिया, भारतेन्दु संवाददाता, मंडी। उपायुक्त अपूर्व देवगन की अध्यक्षता में राजस्व अधिकारियों की बैठक का आयोजन जिला परिषद कार्यालय मंडी के कॉन्फ्रेंस कक्ष में किया गया। बैठक में उपायुक्त ने जिला मंडी के राजस्व अधिकारियों द्वारा 11 जुलाई से 14 अगस्त की अवधि में निपटाए गए राजस्व अदालत मामलों की समीक्षा की।

समीक्षा के दौरान पाया गया कि प्रभावी अवधि के दौरान जिला के सभी तहसील एवं उप तहसील कार्यालयों में तकसीम के 353, निशानदेही के 394 जिसमे एवं राजस्व दुरुस्ती के 172 मामलों का निपटारा किया गया। इसके अतिरिक्त प्रभावी अवधि के दौरान 3,615 इंतकाल भी किए गए।

उपायुक्त ने सभी अधिकारियों को मामलों का समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए, ताकि जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। उन्होंने विशेष रूप से सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए की एक वर्ष या उससे अधिक समय से लंबित तकसीम, निशानदेही एवं राजस्व दुरुस्ती से संबंधित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए।

इस अवसर पर स्वामित्व के कार्य में जिला भर की प्रगति की समीक्षा भी की गई एवं सभी तहसील एवं उप-तहसील कार्यालयों को निर्देश दिए गए की स्वामित्व का कार्य समयबद्ध ढंग से निपटाया जाए। जिला में पटवारखाना निर्माण से संबंधित प्रगति की भी समीक्षा की गई एवं सभी निर्माण कार्यों को समयबद्ध पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री सेवा संकल्प एवं सामान्य शिकायत, विशेष राहत पैकेज, देवी-देवता भूमि आबंटन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दो पर चर्चा की गई एवं दिशा-निर्देश दिए गए।

बैठक में अतिरिक्त जिला उपायुक्त प्रियांशु खाती, जिला राजस्व अधिकारी हरीश शर्मा सहित सभी उप-मण्डलाधिकारियों (एसडीएम), तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों ने भाग लिया।

◆ **डीसी ने लंबित राजस्व मामलों को प्राथमिकता से निपटाने के दिए निर्देश**

हैम रेडियो आपदा के समय वैकल्पिक संचार का विश्वसनीय माध्यम

भारतेन्दु संवाददाता, मंडी। प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मंडी के संयुक्त तत्वावधान में डीआरडीए सभागार मंडी में 'हैम रेडियो-आपातकालीन स्थितियों और आपदाओं के दौरान वैकल्पिक संचार' विषय पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आज शुरू हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ उपायुक्त एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मंडी के अध्यक्ष अपूर्व देवगन ने किया।

उपायुक्त ने कहा कि आपदा के समय संचार व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक होती है। हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण भूस्खलन, बाढ़, बादल फटने, भारी बर्फबारी जैसी आपदाओं के दौरान सड़क, बिजली और दूरसंचार सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। ऐसे में हैम रेडियो जैसे वैकल्पिक संचार माध्यम प्रशासन, राहत एवं बचाव एजेंसियों के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य में प्रशिक्षित हैम रेडियो ऑपरेटरों का मजबूत नेटवर्क तैयार करना आपदा प्रबंधन व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने में सहायक होगा।

आक्रोश नाहन में बेरोजगारी और लंबित भर्तियों को लेकर भाजयुमो ने किया प्रदर्शन

युवाओं को ठगा, गारंटियां भूली कांग्रेस: बिंदल

भारतेन्दु संवाददाता, नाहन। भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में जिला सिरमौर के युवाओं ने नाहन में प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में एकत्रित युवाओं ने बेरोजगारी, लंबित भर्तियों और कांग्रेस की चुनावी गारंटियों को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए अपना आक्रोश व्यक्त किया।

प्रदर्शन को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने कहा कि प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार, मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों ने बेरोजगार युवक-युवतियों को इस कदर निराश और परेशान कर दिया है कि आज उनके पास सड़कों पर उतरकर धरना-प्रदर्शन करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में सत्ता हासिल करने के लिए कांग्रेस के बड़े नेताओं ने हिमाचल के बेरोजगार युवाओं को झूठी गारंटियों का सपना दिखाकर ठगा। कांग्रेस ने प्रदेश के युवाओं से एक लाख सरकारी नौकरियां और पांच लाख रोजगार देने का वादा किया था।

डॉ. बिंदल ने कहा कि कांग्रेस की राष्ट्रीय नेता प्रियंका गांधी ने हिमाचल की चुनावी सभाओं में बड़े जोर-शोर से रोजगार का मुद्दा उठाया था। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री सहित कांग्रेस नेताओं ने भी युवाओं को भरोसा दिलाया कि सरकारी नौकरियां नियमित और स्थायी होंगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने युवाओं को सपना दिखाया था कि न अस्थायी नौकरी होगी, न आउटसोर्स नौकरी होगी, बल्कि पक्की और पेंशन वाली सरकारी नौकरी मिलेगी। आज लगभग चार वर्ष बीतने को हैं और प्रदेश का बेरोजगार युवा कांग्रेस से पूछ रहा है कि वह एक लाख सरकारी नौकरियां आखिर कहां हैं? डॉ. बिंदल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार अपने चुनावी वादों को पूरा करने में पूरी तरह विफल रही है। सरकारी क्षेत्र में बड़ी संख्या में पद खाली पड़े हैं, भर्ती प्रक्रियाएं प्रभावित हैं और निजी क्षेत्र में भी पर्याप्त नए रोजगार के अवसर पैदा नहीं किए गए।उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार पारदर्शी और व्यापक भर्ती करने के बजाय भाई-भतीजावाद और चहेतों को लाभ पहुंचाने की कार्यप्रणाली अपना रही है। यदि सरकार ने कोई नियुक्तियां की हैं तो वह उनका पूरा विवरण सार्वजनिक करे और बताए कि कितने बेरोजगार युवाओं को नियमित सरकारी नौकरी दी गई है।

लुबा गोलोविना का अंदाज निराला

जॉर्जिया। लुबा गोलोविना जॉर्जिया की प्रतिभाशाली ट्रैम्पोलिन जिम्नास्ट और ओलंपियन हैं। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अपने शानदार प्रदर्शन से देश का नाम रोशन किया। उनकी खेल प्रतिभा, मेहनत और निरंतर अभ्यास युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा हैं।

स्पोर्ट्स विंडो

पाकिस्तान लीड्स टेस्ट के पहले ही दिन बैकफुट पर, 171 रन पर ऑलआउट

एजेंसी, लंदन। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंग्लैंड के खिलाफ लीड्स टेस्ट के पहले ही दिन बैकफुट पर है। उसने पहली पारी में 171 रन बनाए। बुधवार को दिन का खेल समाप्त होने तक इंग्लैंड ने अपनी पहली में 2 विकेट पर 112 रन बना लिए हैं। कप्तान जो रूट 37 और जॉर्डन कॉक्स 23 रन पर नाबाद लौटे हैं। ओपनर बेन डकेट ने 15 और इमिलिओ गै ने 33 रन बनाए। मोहम्मद अब्बास और मोहम्मद अली को एक-एक विकेट मिला। पाकिस्तान की शुरुआत खराब रही। टीम ने पहली ही बॉल पर विकेट गंवा दिया। जब ऑली रॉबिन्सन ने फुलर लेंथ की बॉल पर अजान अवैस को जीरो पर एलबीडब्ल्यू कर दिया। उनकी जगह बैटिंग करने उतरे कप्तान शान मसूद भी 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उन्हें भी रॉबिन्सन ने पगबाधा कराया।

महिला युगल जोड़ी त्रीसा-गायत्री विश्व चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में

एजेंसी, नई दिल्ली। त्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय महिला युगल जोड़ी ने बृहस्पतिवार को जापान की सातवीं वरीयता प्राप्त रिन इवानागा और की नाकानिशी को सीधे गेम में हराकर विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। भारत की गैर वरीयता प्राप्त जोड़ी ने एकतरफा मुकाबले में रिन और नाकानिशी की विश्व में सातवें नंबर की जोड़ी को 21-16 21-12 से हराया। हाल में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली त्रीसा और गायत्री ने शुरू से अच्छा प्रदर्शन किया और अपनी प्रतिद्वंद्वी टीम को कोई मौका नहीं दिया। यह भारतीय जोड़ी 2022 और 2023 में लगातार दो वर्ष ऑल इंग्लैंड ओपन के सेमीफाइनल में पहुंची थीं। इस साल की शुरुआत में त्रीसा के टखने में चोट लगने के कारण यह जोड़ी कुछ टूर्नामेंट में नहीं खेल पाई थी। उन्होंने इंडोनेशिया ओपन में वापसी की और इस महीने की शुरुआत में फिलीपीन इंटरनेशनल चैलेंज जीता।

मेजर लीग सॉकर में मेस्सी ने किया एक गोल और एक में की मदद

एजेंसी, चेस्टर। लियोनेल मेस्सी ने एक गोल किया और एक गोल करने में मदद की जिससे इंटर मियामी ने मेजर लीग सॉकर (एमएलएस) में फिलाडेल्फिया यूनियन के खिलाफ मैच 2-2 से ड्रॉ खेला। बुधवार रात को खेले गए मैच में 21वें मिनट में मेस्सी के क्रॉस पर लुई सुआरेज़ ने हेडर लगाकर गेंद को फॉरवर्ड डैनियल पिंटर की ओर बढ़ाया, जिन्होंने उस पर गोल करने में कोई गलती नहीं की। इसके बाद मेस्सी ने 26वें मिनट में 12 गज की दूरी से गोल दागा। यह अपने पिता के निधन के बाद उनका पहला गोल था। मेस्सी ने इस सत्र में एमएलएस के 17 मैचों में 13 गोल और नौ असिस्ट (गोल करने में मदद) किए हैं। पहले हाफ में इंडियाना वासिलेव ने गोल करके यूनियन को बढ़त दिलाई। इसके बाद 18 वर्षीय नील पियरे ने 58वें मिनट में हेडर से गोल दागकर स्कोर बराबर किया।

सिनसिनाटी ओपन में टॉमी पॉल और जेसिका पेगुला क्वार्टर फाइनल में

एजेंसी, मेसन। टॉमी पॉल और जेसिका पेगुला ने तीन सेटों में जीत हासिल करके सिनसिनाटी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। पॉल ने एक सेट से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए फ्रेंच ओपन चैंपियन और शीर्ष वरीयता प्राप्त एलेक्जेंडर ज्वेरेव को 4-6, 7-6, 6-4 से हराया। क्वार्टरफाइनल में उनका मुकाबला फ्लेवियो कोबोली से होगा। पेगुला ने रोमानियाई खिलाड़ी सोराना सिर्स्टिया को 6-2, 4-6, 7-5 से हराकर 2026 में डब्ल्यूटीए टूर में अपनी 43वीं जीत दर्ज की। क्वार्टर फाइनल में पेगुला का सामना हमवतन अमेरिकी खिलाड़ी अमांडा अनिसिमोवा से होगा, जिन्होंने बुधवार को विंबलडन चैंपियन लिंडा नोस्कोवा को 6-1, 6-4 से हराया था।

मिक्स्ड डिसेबिलिटी क्रिकेट : भारत ने इंग्लैंड को हराया, लॉर्ड्स में गांगुली जैसा जश्न मनाया

जीत के बाद बालकनी में भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों ने लहराई शर्ट

एजेंसी, लंदन

भारतीय मिक्स्ड डिसेबिलिटी क्रिकेट टीम ने गत दिवस सातवें और आखिरी टी-20 इंटरनेशनल में इंग्लैंड को 118 रन से हरा दिया। भारत ने इस जीत के बाद लॉर्ड्स की बालकनी में सौरव गांगुली जैसा शर्ट लहराकर जश्न मनाया।

भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट पर 206 रन बनाए। अर्जुन गावरे ने 44 गेंदों पर 68 रन बनाए, जबकि कप्तान माजिद मागरे ने सिर्फ 19 गेंदों पर नाबाद 63 रन की पारी खेली। इसके जवाब में इंग्लैंड की टीम 88 रन पर ऑलआउट हो गई। भारत की ओर से हिलाल अहमद वानी ने 21 रन देकर 4 विकेट और जयेश परमार ने 14 रन देकर 3 विकेट लिए।

भारत ने मैच, इंग्लैंड ने सीरीज जीती

भारत ने सात मैचों की सीरीज का सातवां मुकाबला जीता, लेकिन इंग्लैंड ने सीरीज 4-3 से अपने नाम की। भारतीय खिलाड़ियों ने लॉर्ड्स में जीत का जश्न खास अंदाज में मनाया। डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक्स पर खिलाड़ियों और अधिकारियों का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें सभी लॉर्ड्स की ऐतिहासिक बालकनी में अपने ब्लेजर उतारकर जश्न मनाते नजर आए। यह जश्न 2002 में इसी मैदान पर इंग्लैंड को हराकर नेटवेस्ट ट्रॉफी जीतने के बाद सौरव गांगुली के मशहूर शर्ट लहराने वाले सेलिब्रेशन की याद दिलाता है।

'यहां जीत का जश्न अलग होता है'

डीसीसीआई ने लिखा, जब लॉर्ड्स में भारत जीतता है, तो जश्न का अंदाज अलग होता है। लॉर्ड्स की बालकनी में क्रिकेट की खुशी का यह खास पल था। कोट उतर गए, उत्साह बढ़ गया और तिरंगा गर्व से लहरा रहा था। 118 रन और एक ऐसा जश्न, जिसे भुलाया नहीं जा सकेगा। मिक्स्ड डिसेबिलिटी क्रिकेट फॉर्मेट में अलग-अलग तरह की अक्षमताओं वाले खिलाड़ी एक साथ खेलते हैं। इसमें शारीरिक, सुनने और सीखने से जुड़ी समस्याओं वाले खिलाड़ी शामिल होते हैं।

सिनसिनाटी ओपन में बड़ा उलटफेर सबालेंका-ज्वेरेव टूर्नामेंट से बाहर

सबालेंका को सारा बेजलेक, ज्वेरेव को अमेरिकी खिलाड़ी टॉमी पॉल ने हराया

एजेंसी, सिनसिनाटी

सिनसिनाटी ओपन में बड़े उलटफेर देखने को मिले है। महिला एकल में दुनिया की नंबर-1 खिलाड़ी आर्यना सबालेंका को बड़ा झटका लगा। चेक गणराज्य की 20 वर्षीय सारा बेजलेक ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सबालेंका को 7-6 (7), 6-4 से हराकर टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। दुनिया की 35वें नंबर की बेजलेक के करियर की यह किसी शीर्ष रैंक वाली खिलाड़ी के खिलाफ पहली बड़ी जीत है। साथ ही यह उनका पहला डब्ल्यूटीए 1000 क्वार्टर फाइनल भी है।

वहीं, पुरुषों के एक मुकाबले में अमेरिकी टॉमी पॉल ने बड़ा उलटफेर करते हुए अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। यह पॉल के करियर का 50वां टूर-लेवल क्वार्टर फाइनल है। अब सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए पॉल का सामना फ्लेवियो कोबोली से होगा। सातवीं वरीयता प्राप्त कोबोली ने राफेल जोडार को 4-6, 7-6 (3), 6-3 से हराकर अंतिम आठ में जगह बनाई। एक अन्य मैच में पुरुष एकल में फ्रांसेस टियाफो ने दूसरे वरीय फेलिक्स ऑगर-अलियासिमे को सीधे सेटों में 6-3, 6-4 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। यह टियाफो के करियर में पहली बार है जब उन्होंने एक ही सीजन में एक से ज्यादा मास्टर्स 1000 क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है।

सबालेंका व बेजलेक के बीच रही कांटे की टक्कर

पहले सेट में आर्यना सबालेंका व बेजलेक के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली और मुकाबला टाईब्रेक तक पहुंचा। बेजलेक ने टाईब्रेक में 5-1 की बढ़त बनाई, लेकिन सबालेंका ने लगातार चार अंक जीतकर स्कोर 5-5 कर दिया। हालांकि, बेजलेक ने धैर्य बनाए रखा और तीसरे सेट पॉइंट पर टाईब्रेक 9-7 से जीतकर पहला सेट अपने नाम किया। दूसरे सेट में सबालेंका ने फिर 4-1 की बढ़त बना ली, लेकिन बेजलेक ने एक बार फिर शानदार वापसी की। उन्होंने स्कोर 4-4 किया, फिर ब्रेक हासिल कर 5-4 की बढ़त बनाई और अगले गेम में मैच अपने नाम कर लिया। जीत के बाद बेजलेक ने कहा, 'मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे पास शब्द नहीं हैं। मैंने बस विश्वास बनाए रखा। यही सबसे जरूरी था।

ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने किए महाकाल के दर्शन

एजेंसी, उज्जैन

ओलंपिक पदक विजेता निशानेबाज मनु भाकर ने गुरुवार मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग भगवान महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर बाबा महाकाल के दर्शन किए। उन्होंने तड़के होने वाली प्रसिद्ध भस्म आरती में भी भाग लिया और विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया।

इस दौरान उन्होंने नंदी हॉल में बैठकर नंदी महाराज के कान में अपनी मनोकामना भी कही। भारत की स्टार निशानेबाज और ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर आज तड़के उज्जैन के ज्योतिर्लिंग भगवान महाकालेश्वर मंदिर पहुंचीं। उन्होंने प्रात:कालीन भस्म आरती में शामिल होकर पूरे धार्मिक भाव के साथ बाबा महाकाल का पूजन-अभिषेक किया। भस्म आरती के बाद मनु भाकर ने नंदी हॉल में बैठकर भगवान शिव के वाहन नंदी महाराज के कान में अपनी मनोकामना कही। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, नंदी के कान में कही गई बात सीधे बाबा महाकाल तक पहुंचती है। पारंपरिक सलवार-कुर्ती में मंदिर पहुंचीं मनु भाकर का महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा भव्य स्वागत व सत्कार किया गया। मंदिर प्रशासन के अधिकारियों और कर्मचारियों ने उन्हें व्यवस्थित रूप से दर्शन कराने और पूजा-अर्चना संपन्न कराने में सहयोग प्रदान किया।

नंदी महाराज के कान में कही अपनी मनोकामना

महंगाई पर काबू पाने के लिए आरबीआई अपना सकता है सख्त रुख!

एजेंसी, नई दिल्ली

बढ़ती खाद्य और ईंधन कीमतों के बीच महंगाई का दबाव आम लोगों के साथ-साथ अर्थव्यवस्था के लिए भी चिंता का विषय बनता जा रहा है। ऐसे माहौल में भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति पर सबकी नजर है। फिलहाल अगस्त की मौद्रिक नीति बैठक में रेपो दर को 5.25 प्रतिशत पर स्थिर रखा गया है और केंद्रीय बैंक ने तटस्थ रुख अपनाया है। हालांकि यदि आने वाले महीनों में महंगाई लगातार बढ़ती रही तो ब्याज दरों में बदलाव की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

ब्याज दरों में बढ़ोतरी का सबसे सीधा असर कर्ज लेने वाले लोगों पर पड़ सकता है। खासकर परिवर्तनीय ब्याज दर वाले गृह ऋण और वाहन ऋण की मासिक किस्तें बढ़ सकती हैं। इससे परिवारों के मासिक बजट पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा और नई संपत्ति या वाहन खरीदने की योजनाएं भी प्रभावित हो सकती हैं। पहले से कर्ज चुका रहे लोगों के लिए भी ब्याज दरों में वृद्धि लंबी अवधि में कुल भुगतान बढ़ा सकती है।

हालांकि फिलहाल रेपो दर स्थिर होने के कारण तत्काल मौजूदा ईएमआई में बदलाव की संभावना नहीं है। आगे केंद्रीय बैंक महंगाई के आंकड़ों, खाद्य वस्तुओं की कीमतों, ईंधन के दाम और आर्थिक गतिविधियों को ध्यान में रखकर निर्णय लेगा। यदि महंगाई नियंत्रित होती है तो दरों में स्थिरता बनी रह सकती है।

भारत ने अफगानिस्तान भेजी चिकित्सा सहायता

एजेंसी, नई दिल्ली। भारत ने मानवीय सहायता के तहत वीरवार को अपने मित्र देश अफगानिस्तान के लिए आवश्यक दवाओं और चिकित्सा सामग्रियों की एक नई खेप रवाना की। यह सहायता काबुल स्थित एक सरकारी अस्पताल को सौंपी गई है। विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत ने अफगानिस्तान नागरिकों के साथ अपनी दीर्घकालिक और मजबूत स्वास्थ्य साझेदारी को दोहराते हुए यह कदम उठाया है। इस पहल का प्राथमिक उद्देश्य अफगानिस्तान की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती प्रदान करना और स्थानीय नागरिकों को बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

सेंसेक्स 628 अंक चढ़कर 77538 पर बंद

निफ्टी में भी 154 अंक की बढ़त, मीडिया और रियल्टी शेयर्स में ज्यादा खरीदारी

एजेंसी, मुंबई

शेयर बाजार में 20 अगस्त को बढ़त रही। सेंसेक्स 628 अंक चढ़कर 77,538 पर बंद हुआ। दूसरी ओर निफ्टी में भी 154 अंक की बढ़त रही, यह 24,232 पर बंद हुआ। मीडिया, रियल्टी और एफएमसीजी शेयर्स में आज ज्यादा खरीदारी रही। शेयर बाजार में कुछ दिनों से गिरावट देखी जा रही थी।

वहीं, थर्मल इंजीनियरिंग और स्पेशलाइज्ड केबल बनाने वाली कंपनी टेम्पसेंस इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड का आईपीओ आज से ओपन हो गया है। निवेशक इसमें 24 अगस्त तक बोली लगा सकेंगे। कंपनी आईपीओ के जरिए 650 करोड़ जुटाना चाहती है।

सोना 1.57 लाख, चांदी 2.38 लाख पर पहुंची

एजेंसी, नई दिल्ली। सोने-चांदी की कीमतें 20 अगस्त को बढ़ गई हैं। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक, एक किलो चांदी की कीमत 9,260 रुपए बढ़कर 2.38 लाख रुपए पहुंच गई है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 3,519 रुपए बढ़कर 1.57 लाख रुपए हो गया है। इस महीने यानी अगस्त में 20 दिन में सोना 15 हजार और चांदी 20 हजार रुपए महंगी हो चुकी है।

कांग्रेस आज की 'नई मुस्लिम लीग' : नवीन

एजेंसी, नई दिल्ली

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने 'वंदे मातरम्' को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अब अपने अपमान को एक प्रस्ताव का रूप दे दिया है। कांग्रेस कार्यसमिति ने निर्णय लिया है कि पार्टी के मंचों पर 'वंदे मातरम्' के केवल पहले दो छंद ही गाए जाएंगे। नितिन नवीन ने एक्स पर कहा, 'कुछ दिन पहले यही अपमान एक व्यक्ति के आचरण में दिखाई दिया था, जिसे कांग्रेस ने संयोग बताकर टाल दिया, लेकिन अब वही अपमान कांग्रेस की आधिकारिक नीति बन गया है।' उन्होंने कहा कि 'भारत माता' की इस पावन वंदना का अपमान उन हजारों स्वतंत्रता सेनानियों और बलिदानियों का भी अपमान है, जिन्होंने 'वंदे मातरम्' को अपनी प्रेरणा बनाकर देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया।

नितिन ने आरोप लगाया कि कांग्रेस आज 'नई मुस्लिम लीग' की तरह व्यवहार कर रही है और उसका यह रुख राष्ट्रीय भावनाओं के विपरीत है। उनके अनुसार यह केवल राजनीतिक बचाव नहीं, बल्कि वोट बैंक की राजनीति का प्रमाण है।

त्योहारों से पहले प्याज महंगा, रसोई के बजट पर बढ़ा दबाव

एजेंसी, नई दिल्ली

त्योहारी सीजन शुरू होने से पहले प्याज की कीमतों में अचानक तेजी ने आम लोगों की रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। पिछले एक सप्ताह में प्याज के दाम करीब 30 प्रतिशत तक बढ़े हैं। देश के कई हिस्सों में खुदरा बाजार में प्याज 40 से 50 रुपये प्रति किलोग्राम तक बिक रहा है। कीमतों में इस बढ़ोतरी के पीछे बारिश के कारण आपूर्ति प्रभावित होना और प्याज के खराब होने को प्रमुख कारण माना जा रहा है। थोक बाजार में कीमत बढ़ने का सीधा असर खुदरा बाजार पर दिखाई दे रहा है।

महाराष्ट्र के लासलगांव मंडी में भी प्याज के भाव में तेजी दर्ज की गई है। व्यापारियों के अनुसार लगातार बारिश के कारण प्याज की गुणवत्ता प्रभावित हुई है और बड़ी मात्रा में फसल खराब होने की आशंका है। दूसरी ओर त्योहारों के नजदीक आने के साथ मांग बढ़ने से बाजार पर अतिरिक्त दबाव बन गया है। जून के बाद से प्याज की कीमतों में लगातार तेजी देखी जा रही है।

कीमतों पर नियंत्रण के लिए सरकार बफर स्टॉक से प्याज बाजार में उतारने की तैयारी कर रही है। नैफेड और एनसीसीएफ के माध्यम से उपभोक्ताओं को अपेक्षाकृत सस्ती दरों पर प्याज उपलब्ध कराने की योजना है।

चीन पर खनिज निर्भरता घटाने की तैयारी में कोल इंडिया, सिंगापुर में खोलेगी पहला विदेशी कार्यालय

एजेंसी, नई दिल्ली

भारत की खनिज सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में कोल इंडिया ने बड़ी रणनीति तैयार की है। कंपनी चीन पर महत्वपूर्ण खनिजों के लिए निर्भरता कम करने और वैश्विक स्तर पर अपनी मौजूदगी बढ़ाने के उद्देश्य से सिंगापुर में अपना पहला विदेशी व्यापार कार्यालय खोलने की तैयारी कर रही है। इसके लिए सिंगापुर के अधिकारियों के पास कार्यालय के पंजीकरण को लेकर आवेदन किए जाने की जानकारी सामने आई है। कंपनी का यह कदम लिथियम, बॉक्साइट, लौह अयस्क और अन्य रणनीतिक खनिजों की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अपनी भूमिका मजबूत करने के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

कोल इंडिया का विदेशी कार्यालय केवल खनिजों के व्यापार तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि विदेशों में खनिज संपत्तियों की पहचान और संभावित अधिग्रहण के अवसर तलाशने में भी मदद करेगा। कंपनी की नजर खनिज संपदा से समृद्ध कई देशों पर है। घाना और अफ्रीका के अन्य हिस्सों में बॉक्साइट से जुड़ी संभावनाओं का आकलन किया जा रहा है।

भारत की खनिज सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम

भारत के लिए यह पहल इसलिए अहम है क्योंकि लिथियम, दुर्लभ खनिज और अन्य महत्वपूर्ण संसाधन आधुनिक उद्योगों के लिए बेहद जरूरी हो गए हैं। इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी, ऊर्जा भंडारण, रक्षा उपकरण और उच्च तकनीकी उद्योगों में इन खनिजों की मांग लगातार बढ़ रही है।

अस्थिरता दस महीने में दो ट्रिलियन डॉलर बढ़ा अमेरिकी कर्ज, आर्थिक चुनौतियां हुईं गंभीर

अमेरिका का राष्ट्रीय कर्ज पहली बार 40 ट्रिलियन डॉलर के पार

एजेंसी, नई दिल्ली

अमेरिका का राष्ट्रीय कर्ज पहली बार 40 ट्रिलियन डॉलर के ऐतिहासिक स्तर को पार कर गया है। अमेरिकी वित्त विभाग के नए आंकड़ों के अनुसार पिछले करीब दस महीनों में ही देश के कर्ज में लगभग दो ट्रिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई है। कर्ज में इतनी तेज वृद्धि ने अमेरिका की आर्थिक स्थिति को लेकर विशेषज्ञों की चिंता बढ़ा दी है। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल अमेरिका का वित्तीय स्वास्थ्य वैश्विक बाजारों और अंतरराष्ट्रीय निवेश पर भी व्यापक प्रभाव डालता है।

अमेरिकी सरकार के बढ़ते खर्च को कर्ज में वृद्धि का प्रमुख कारण माना जा रहा है। रक्षा क्षेत्र पर भारी खर्च के साथ सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं के लिए बड़ी राशि खर्च की जा रही है। इसके अलावा पहले लिए गए कर्ज पर ब्याज भुगतान का बोझ भी लगातार बढ़ रहा है। ब्याज भुगतान में वृद्धि का अर्थ है कि सरकार की आय का बड़ा हिस्सा केवल पुराने कर्ज की लागत चुकाने में खर्च हो रहा है। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और अन्य विकास योजनाओं के लिए उपलब्ध वित्तीय संसाधनों पर दबाव बढ़ सकता है।

कर्ज बढ़ने का असर केवल सरकारी बजट तक सीमित नहीं रहता। यदि सरकार लगातार बड़ी मात्रा में उधार लेती है तो वित्तीय बाजारों पर दबाव बढ़ सकता है। सरकार को अधिक ब्याज दर पर कर्ज लेना पड़ सकता है और इसका प्रभाव व्यापक अर्थव्यवस्था में भी दिखाई दे सकता है। बैंक और वित्तीय संस्थान ब्याज दरों में बदलाव के आधार पर ऋण की लागत तय करते हैं। ऐसे में घर खरीदने के लिए लिया जाने वाला ऋण, वाहन ऋण और कारोबार के लिए मिलने वाला कर्ज महंगा होने की आशंका रहती है।

अमेरिकी अर्थव्यवस्था की स्थिति का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। डॉलर अंतरराष्ट्रीय व्यापार और वित्तीय व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दुनिया के कई देश अपने विदेशी मुद्रा भंडार में अमेरिकी डॉलर रखते हैं और अमेरिकी सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं। इसलिए अमेरिका के बढ़ते कर्ज से वैश्विक निवेशकों की चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। यदि निवेशकों का भरोसा कमजोर होता है तो वित्तीय बाजारों में अस्थिरता बढ़ सकती है।